चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

www.chauthiduniya.com

1986 से प्रकाशित

दिल्ली, 09 जनवरी-15 जनवरी 2012

मूल्य 5 रुपये

मिशन-2012 दूर की कौड़ी

पेज-3

नीतीश की सभा में कुर्सियां क्यों उछलीं

पेज-4

बसपा का श्वेत पत्र झूठ का पुलिंदा है

पेज-6

आरक्षण के नाम पर मुसलमानों से धोखा

पेज-7

सरकारी लोकपाल बिल

यह अंधा क़ानून है

जिन्हें संसद की गरिमा का ख्याल था, जिन्हें संसद में सिविल सोसाइटी का दखल पसंद नहीं था, जिन पर संसद की साख बचाने की ज़िम्मेदारी थी, जिनके सामने इतिहास गढ़ने का मौका था, वे चूक गए और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया. कांग्रेस पार्टी ने लोकपाल पर जो किया, उससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि देश चलाने वालों में भ्रष्टाचार ख़त्म करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं है. भ्रष्टाचार के अंधकार को ख़त्म करने के लिए सरकार को क़ानून बनाना था, लेकिन उसने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला एक अंधा क़ानून बनाने की पहल की है.

सभी फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

मनीष कुमार

पांच जून, 1975 को पटना के गांधी मैदान में लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि इस संसद को आग लगा दो. अगले दिन अख़बारों ने उनके इसी वाक्य को इस समाचार का शीर्षक बनाया. लालू यादव उस वक़्त छात्रनेता थे, युवा थे और जयप्रकाश जी के आंदोलन के महत्वपूर्ण आंदोलनकारी थे. 29 दिसंबर, 2011 को लालू यादव सचमुच संसद को आग लगाने का काम कर रहे थे. राज्यसभा में दिन भर लोकपाल बिल पर बहस होती रही. सरकार के पास बिल को पास कराने के लिए बहुमत नहीं था. रात नौ बजे से ऐसी ख़बरें आने लगीं कि सरकार जानबूझ कर हंगामा करने वाली है. बहस को लंबा करके 12 बजा दिया जाएगा और फिर सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा. रात के 10 बजकर 50 मिनट पर लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के सांसद राजनीति प्रसाद भाषण दे रहे थे. पूरा देश राज्यसभा को लाइव देख रहा था. तभी एक अंग्रेजी चैनल के संपादक-एंकर ने अपने रिपोर्टर से कुछ ताज़ा जानकारी मांगने के लिए सवाल पूछा. राजनीति प्रसाद का नाम सुनते ही उस रिपोर्टर ने सरकार की पूरी योजना बता दी. 10 बजकर 50 मिनट पर उस रिपोर्टर ने बताया कि राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सांसदों को सदन में हंगामा करने की ज़िम्मेदारी दी गई है. उसने यह भी बताया कि जब मंत्री सवालों के जवाब देंगे, तब हंगामा होगा. उसने यह भी बताया कि कांग्रेस पार्टी और इन पार्टियों के बीच यह योजना बनी है कि जब मंत्री महोदय अल्पसंख्यकों के आरक्षण के मामले पर बोलना शुरू करेंगे, उसी वक़्त राजनीति प्रसाद उन्हें रोकेंगे. इस रिपोर्टर ने जैसी जानकारी दी, बिल्कुल वैसा ही हुआ. जब पीएमओ में राज्यमंत्री नारायण सामी जवाब दे रहे थे, तभी राजनीति प्रसाद ने उनसे बिल की कापी छीन कर उसे फाड़ दिया और हॉल में उछाल कर फेंक दिया. राज्यसभा में हंगामा मचाने की योजना के सूत्रधार लालू यादव संसद में मौजूद थे और जब यह शर्मनाक वाक्या घटित हो रहा था, उस वक़्त लालू यादव गैलरी में पूरे नज़ारे का आनंद उठा रहे थे. हंगामा हुआ. सदन की कार्रवाई रोक दी गई. विपक्ष यह कहता रह गया कि वह संसद में लगातार बैठने और वोटिंग कराने को राजी है, लेकिन सभापति हामिद अंसारी ने अनिश्चितकाल के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित करते हुए राष्ट्रगान शुरू करने का आदेश दे दिया. पूरा देश हैरान और शर्मसार होकर इस ड्रामे को देख रहा था. लोकपाल बिल लटक गया और संसद कलंकित हो गई. इस तरह भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ कड़ा क़ानून बनाने निकली सरकार द्वारा प्रजातंत्र में भ्रष्टाचार का नया इतिहास लिख दिया गया.

सरकार की नीयत में खोट है, यह शुरुआत से ही लग रहा था. जो लोकपाल क़ानून सरकार लागू करना चाहती है, वह इस बात का सबूत है. जबसे लोकपाल को लेकर विवाद शुरू हुआ, तबसे दो-दो लोकपाल बिलों की बात चली. एक वह, जो सरकार बनाना चाहती थी और दूसरा वह, जो अन्ना हजारे की टीम ने तैयार किया था, जिसे जन लोकपाल बिल कहा जाता है. भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ एक सशक्त लोकपाल बने, इसके लिए अन्ना हजारे ने 5 अप्रैल, 2011 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनशन शुरू किया, उन्हें लोगों का अपार समर्थन मिला. सरकार भी डर गई कि दिल्ली में कहीं मिस्र जैसी हालत न हो जाए. इसलिए सरकार ने बिल को तैयार करने के लिए एक संयुक्त समिति बनाई, जिसमें टीम अन्ना के पांच सदस्य शामिल किए गए. टीम अन्ना की तरफ से अन्ना हजारे, शांतिभूषण, प्रशांत भूषण, संतोष हेगड़े और अरविंद केजरीवाल थे तो सरकार की तरफ से प्रणव मुखर्जी, कपिल सिब्बल, पी चिदंबरम, अभिषेक मनु सिंघवी और सलमान खुर्शीद थे. सरकार के पास उस वक़्त भी लोकपाल बिल का एक मसौदा था. संयुक्त कमेटी में टीम अन्ना ने कुछ सुझाव दिए.

सरकार की नीयत में खोट थी, इसलिए उसने टीम अन्ना की बात नहीं मानी. आख़िर उसने संयुक्त समिति का ड्रामा क्यों किया? इस संयुक्त समिति में यह फ़ैसला लिया गया कि दोनों ही लोकपाल बिल कैबिनेट के सामने रखे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अन्ना ने रामलीला मैदान में अनशन किया. तेरह दिनों के बाद सरकार और अन्ना में समझौता हुआ. प्रधानमंत्री ने पत्र लिखकर सेंस ऑफ हाउस (संसद की भावना) को लागू करने का आश्वासन दिया. अन्ना की यह मांग थी कि लोकपाल बिल संसद के शीतकालीन सत्र में पास कर दिया जाए. सरकार ने शीतकालीन सत्र के दौरान लोकपाल बिल पेश किया. सरकार की चाल, चरित्र और चेहरा उजागर हो गया. अन्ना हजारे के आंदोलन से पहले सरकार ने लोकपाल क़ानून का जो मसौदा तैयार किया था, उसकी तुलना में मौजूदा सरकारी लोकपाल बिल का स्वरूप ख़राब और कमज़ोर है.

देश की भावना क्या है. देश की भावना यही है कि सरकार भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ एक कठोर क़ानून लाए. एक ऐसा क़ानून, जिससे भ्रष्टाचार को मिटाया जा सके. सरकार ने न देश की भावना का ख्याल रखा और न वह संसद की भावना को लागू करना चाहती है. सेंस ऑफ द हाउस क्या था. संसद में यह तय हुआ था कि लोकपाल बिल में सी और डी कैटेगरी के कर्मचारी लोकपाल के अधीन होंगे और सिटीजंस चार्टर को लोकपाल में शामिल किया जाएगा. इसके अलावा राज्यों में लोकायुक्त का गठन लोकपाल क़ानून के तहत होगा, लेकिन सरकार ने जो वायदा किया था, उसे नहीं निभाया. सिटीजंस चार्टर बिल को अलग कर दिया गया. राज्यों में लोकायुक्त के लिए अलग व्यवस्था है और निचले कर्मचारियों को लोकपाल की जगह केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधिकार क्षेत्र में दे दिया गया. अगर यह क़ानून पास हो गया होता तो निचले कर्मचारियों का भ्रष्टाचार लोकपाल के तहत नहीं आता. सेना के भ्रष्टाचार की तहकीकात करने का अधिकार लोकपाल के पास नहीं है. सांसदों का भ्रष्टाचार भी अब लोकपाल के दायरे से बाहर कर दिया गया है. न्यायपालिका भी लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है. संसद में सरकारी पक्ष ने अपनी किरकिरी ख़ुद कराई. लोकसभा में सरकारी लोकपाल बिल में कुल 55 संशोधनों पर वोटिंग होनी थी, जिनमें से सिर्फ़ 9 संशोधन ही पास हो पाए. ये नौ संशोधन वे थे, जिन्हें सरकारी पक्ष की तरफ से रखा गया. हैरतअंगेज बात यह है कि सरकार ने ख़ुद बिल तैयार किया और ख़ुद संशोधन की अर्जी भी लगाई.

सरकार की मंशा देखिए, ऐसा लगता है कि लोकपाल क़ानून बनाने वालों को भ्रष्टाचारियों की चिंता ज़्यादा है. सरकारी लोकपाल क़ानून के अनुसार, अगर किसी अधिकारी के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो उसे सरकार की तरफ से वकील दिया जाएगा. मतलब यह कि भ्रष्ट अधिकारियों को

(शेष पृष्ठ 2 पर)

सरकार की नीयत में खोट है, यह शुरुआत से ही लग रहा था. जो लोकपाल क़ानून सरकार लागू करना चाहती है, वह इस बात का सबूत है. जबसे लोकपाल को लेकर विवाद शुरू हुआ, तब से दो-दो लोकपाल बिलों की बात चली. एक वह, जो सरकार बनाना चाहती थी और दूसरा वह, जो अन्ना हजारे की टीम ने तैयार किया था, जिसे जन लोकपाल बिल कहा जाता है. भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ एक सशक्त लोकपाल बने, इसके लिए अन्ना हजारे ने 5 अप्रैल, 2011 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनशन शुरू किया, उन्हें लोगों का अपार समर्थन मिला. सरकार भी डर गई कि दिल्ली में कहीं मिस्र जैसी हालत न हो जाए.

यहां के बाबू चर्चा में नहीं आना चाहते हैं. महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक पद पर बैठे बाबू सुरक्षित स्थान पाने के लिए होड़ लगाए हुए हैं.

दिल्ली का बाबू

ममता को बाबुओं की तलाश

पश्चिम बंगाल के बाबुओं के साथ सब ठीक नहीं हो रहा है. पहले तो ममता बनर्जी ने उन्हें केंद्र में जाने से मना कर दिया, जो डिपुटेशन पर जाना चाहते थे. इससे बाबुओं को परेशानी हुई. अब वह राज्य के कई प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के लिए बाबुओं की खोज कर रही हैं. सूत्रों के अनुसार, राज्य के वित्त सचिव सी एम बछावत अपना स्थानांतरण कराना चाहते हैं, लेकिन उनका स्थानांतरण नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सरकार को इस पद पर नियुक्ति के लिए जिस तरह के अधिकारी की आवश्यकता है, उसे ढूंढने के लिए महीनों का समय चाहिए. सच बात तो यह है कि सरकार बछावत की जगह आबकारी सचिव एच के द्विवेदी को लाना चाहती है, जिसके लिए उसे कुछ महीने इंतजार करना पड़ेगा. इसीलिए वह वित्त सचिव का स्थानांतरण नहीं कर रही है. अभी इस राज्य के बाबुओं का रूटीन स्थानांतरण भी सही तरीके से नहीं हो रहा है. यहां के बाबू चर्चा में नहीं आना चाहते हैं. महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक पद पर बैठे बाबू सुरक्षित स्थान पाने के लिए होड़ लगाए हुए हैं. पता नहीं, दीदी को अपने प्रशासन में सुधार के लिए किस तरह के अधिकारियों की आवश्यकता है, जिन्हें खोजने के लिए उन्हें इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है.

स्थानांतरण की राजनीति

पंजाब विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के कारण आईएएस अधिकारी अडप्पा कार्तिक को राहत मिली है. एक साल के भीतर कार्तिक का सात बार स्थानांतरण किया जा चुका है, लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कम से कम उन्हें स्थानांतरण से कुछ समय के लिए निजात मिल जाएगी. इस समय कार्तिक सचिव-तकनीकी शिक्षा हैं और अब वह नई सरकार के गठन तक इस पद पर रह सकते हैं. सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण संबंधी नीति समान नहीं है. वह कुछ अधिकारियों का स्थानांतरण बहुत जल्दी-जल्दी कर देते हैं, जबकि कुछ अधिकारी ऐसे हैं, जो एक ही पद पर पांच साल से बैठे हुए हैं और उनका स्थानांतरण नहीं किया जा रहा है. स्थानांतरण की यह नीति तो राजनीति से ही प्रेरित मानी जा सकती है. वैसे कई आईएएस अधिकारी सेवानिवृत्त होने के बाद राजनीति में आने लगे हैं और चुनाव भी लड़ना चाहते हैं. ऐसे में यही कहा जा सकता है कि यह तो स्थानांतरण की राजनीति है, जो पहले से चली आ रही है, लेकिन इस बीच कुछ बढ़ती जा रही है.

सीबीआई की परेशानी

दिलीप चेरियन

सीबीआई आजकल कई कारणों से चर्चा में है. सामाजिक कार्यकर्ता उसे सरकार के चंगुल से मुक्त कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. राजनेताओं के बीच भी इस बात के लिए बहस चल रही है कि किस तरह सीबीआई के दुरुपयोग को रोका जाए. सीबीआई अभी कई घोटालों की जांच कर रही है, लेकिन इस समय उसकी चिंता का एक और कारण है. इस विभाग में कई पद खाली हैं, जिन्हें भरा जाना जरूरी है, लेकिन नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं. सीबीआई में निरीक्षक, उपनिरीक्षक, एएसपी और एसपी जैसे कई अधिकारियों की जरूरत है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. सूत्रों के अनुसार, सीबीआई के कार्यकारी विभाग में 690 पद खाली हैं, जबकि विधि विभाग में 100 से अधिक पद खाली हैं. इसके अलावा संयुक्त निदेशक के कम से कम चार पद खाली हैं. इस समय सीबीआई के निदेशक ए पी सिंह प्रधानमंत्री एवं अन्य नेताओं से मिलने में व्यस्त हैं, ताकि वह सीबीआई के भविष्य के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकें. लोकपाल आने के बाद सीबीआई की क्या स्थिति होगी, यह अभी तय नहीं है. लगता है कि जब तक सीबीआई की स्थिति स्पष्ट नहीं होगी, तब तक इन खाली पदों पर नियुक्तियों के लिए इंतजार करना पड़ेगा. इससे सीबीआई को परेशानी हो रही है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे मामले हैं, जिनकी वह जांच कर रही है.

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

वेणुगोपाल वित्तीय सलाहकार

1984 बैच के आईडीएएस अधिकारी वेणुगोपाल वेलीदंडा को गृह मंत्रालय के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल का वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया गया है. वह अरुणव दत्त की जगह लेंगे, जिन्हें टैरिफ कमीशन में सदस्य सचिव बनाया गया है.

वासुदेव बने परियोजना निदेशक

1982 बैच के आईएएस अधिकारी सृष्टि पाल वासुदेव को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का परियोजना निदेशक बनाया गया है. यह पद नवसृजित है और संयुक्त सचिव रैंक का है.

जौहरी एवं ज्योति संयुक्त सचिव

1987 बैच के आईएएस अधिकारी एम सी जौहरी को जहाजरानी विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है. वह राजीव गुप्ता की जगह लेंगे, जिन्हें मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है. इसी तरह 1987 बैच की आईएएस अधिकारी ज्योति अरोड़ा को ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया है. वह सुधीर कुमार की जगह लेंगी.

श्रीनिधि वित्त सदस्य बने

1979 बैच के सीएसएस कैडर के अधिकारी टी श्रीनिधि को शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण का वित्त सदस्य बनाया गया है. वह नंद लाल की जगह लेंगे.

एमडी बने पालीवाल

1981 बैच के आईएएस अधिकारी चंद्रभूषण पालीवाल को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का एमडी बनाया गया है. वह अभी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के सीवीओ के पद पर काम कर रहे हैं.

यह अंधा क़ानून है

पृष्ठ एक का शेष

वकील पर पैसा भी नहीं ख़र्च करना पड़ेगा. हैरानी की बात यह भी है कि अगर कोई व्यक्ति लोकपाल के पास किसी अधिकारी के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराएगा तो सरकार उस अधिकारी को वकील मुहैया कराएगी, ताकि वह अदालत में शिकायतकर्ता पर यह मुकदमा कर सके कि उसके ख़िलाफ़ लगाए गए आरोप फ़र्ज़ी हैं. सरकार अधिकारियों को बचाने के लिए एक और नियम बनाना चाहती है. आरोपी अधिकारी के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कराने से पहले उसे एक नोटिस देकर पूछा जाएगा कि उसके ख़िलाफ़ एफआईआर क्यों न दर्ज कराई जाए. साथ ही उसके ख़िलाफ़ जितने सबूत हैं, वे उसे दिखाए जाएंगे. आरोपी उस नोटिस का पहले जवाब देगा, तब जाकर उसके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की जा सकेगी. इसका मतलब यह है कि जिस अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा, उससे पहले पूछा जाएगा कि उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों न की जाए. अगर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई भी तो पहले सारे सबूत उसके सामने रखने का प्रावधान बनाया गया है. सरकार ऐसा क़ानून बनाना चाहती है, जिसमें भ्रष्टाचार का मामला जांच और कार्रवाई के लिए दफ्तरों में घूमता रहेगा और भ्रष्ट अधिकारी को इतना समय मिल जाएगा कि वह सारे सबूत नष्ट कर सके. पहले जो क़ानून लाया जा रहा था, उसमें यह प्रावधान था कि भ्रष्टाचार के प्रत्येक मामले को छह महीने की अवधि के अंदर निपटा दिया जाएगा. अब यह अनिवार्य समय सीमा हटा ली गई है. मतलब यह कि अब किसी घोटाले की जांच कई सालों तक चल सकती है. जैसा कि बड़े-बड़े घोटालों में हुआ, जांच और अदालत में सुनवाई होते-होते ज़माना बीत गया और घोटालेबाज छूट गए. हैरानी की बात यह है कि यह प्रावधान सरकार ने लोकसभा में संशोधन के तहत किया. अब सवाल उठता है कि सरकार भ्रष्टाचारियों को पकड़ना चाहती है या फिर उन्हें बचने का रास्ता देना चाहती है. लोकपाल क़ानून बनाने वालों की महानता देखिए. अगर कोई ग़रीब आदमी ग़लती से चोरी कर लेता है तो पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार करके उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लेती है और उसे जेल भेज दिया जाता है, उसे बोलने का मौका भी नहीं दिया जाता. क़ानून में ऐसे लोगों के लिए कोई रहम नहीं है. सरकार ने जो लोकपाल बिल तैयार किया, उसके पीछे की दलील यही लगती है कि वह यह मानती है कि देश के अधिकारी ईमानदार हैं.

निचले कर्मचारियों को सीवीसी के हाथों सौंप दिया गया है. देश में 60 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, जो केंद्र सरकार से जुड़े हैं. इनमें से सिर्फ़ 3 लाख कर्मचारी ही लोकपाल के दायरे में हैं. लोकपाल के पास सिर्फ़ ए और बी ग्रुप के अधिकारी हैं. सरकार की दलील है कि सारे कर्मचारियों को लोकपाल के तहत नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि यह संख्या काफ़ी ज़्यादा है. अगर यह दलील है तो उन्हें सीवीसी को क्यों दे दिया गया, क्या सीवीसी के पास इतने लोग हैं या उसकी इतनी क्षमता है कि वह 57 लाख कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के मामलों की तहकीक़ात कर सके. सरकार ने यह दलील देकर निचले कर्मचारियों को तो निकाल दिया, लेकिन उनकी जगह करोड़ों संस्थाओं और लोगों को लोकपाल के हवाले कर दिया. निजी संगठन, मंदिर, मठ, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ट्रस्ट, यूथ क्लब, निजी स्कूल-कॉलेज और अस्पताल, ये सब लोकपाल के दायरे में डाल दिए गए हैं. इसके पीछे दलील यह है कि जो भी व्यक्ति या संगठन चंदा इकट्ठा करते हैं, उन्हें लोकपाल के दायरे में शामिल कर दिया गया है. लोकपाल बिल का मसौदा इस बात का प्रमाण है कि सरकार ने वही किया, जो वह पहले करना चाह रही थी.

अब सवाल उठता है कि लोकपाल का चयन कौन करेगा. उसके चयन के लिए पांच लोगों की एक कमेटी गठित होगी, जिसमें प्रधानमंत्री, स्पीकर, चीफ जस्टिस, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एक न्यायविद् को शामिल किया जाएगा. मतलब यह कि चीफ जस्टिस एवं नेता प्रतिपक्ष के अलावा सभी सदस्य सत्ता पक्ष के होंगे और सरकार अपने हिसाब से लोकपाल चुनेगी. इस तरह लोकपाल का भी राजनीतिकरण हो जाएगा. जो हाल राज्यपाल के पद का है, उसी तरह सरकार अपनी पार्टी के रिटायर लोगों को लोकपाल बना देगी यानी सरकार जिसे चाहेगी, उसे लोकपाल बनाएगी. सरकार ही लोकपाल को हटा सकती है, जब चाहे उसे सस्पेंड कर सकती है. अन्ना हजारे की टीम ने लोकपाल को हटाने का अधिकार जनता को दिया था. जन लोकपाल मसौदे के मुताबिक़, कोई भी आम नागरिक लोकपाल के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और उसे हटवा सकता है, लेकिन सरकारी लोकपाल को हटाने का हक़ सिर्फ़ और सिर्फ़ सरकार के पास रहेगा. कहने का मतलब यह है कि लोकपाल पूरी तरह सरकार के हाथों की कठपुतली बन जाएगा. अब यह समझ में नहीं आता है कि सरकार जो लोकपाल नियुक्त करेगी और उसके निलंबन-बर्ख़ास्तगी का अधिकार अपने पास रखेगी, वह लोकपाल मंत्रियों, मंत्रालयों और बड़े-बड़े अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कैसे कर सकेगा? जिस तरह सीवीसी सरकार के मंत्रियों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, उसी तरह लोकपाल भी सीबीआई और सीवीसी जैसी नख-दंत-विष हीन संस्था बनकर रह जाएगा. मनमोहन सिंह सरकार का यही सशक्त लोकपाल है.

लोकपाल क़ानून बनाते समय सरकार से एक और ग़लती हुई. इस ग़लती की शिकार हुई है सीबीआई यानी देश की प्रीमियम जांच एजेंसी. सरकार ने दो काम किए. एक तो सीबीआई को कमज़ोर किया और अपना शिकंजा भी बरक़रार रखा. लोकपाल या भ्रष्टाचार से लड़ने वाली किसी भी संस्था की परिकल्पना जांच के अधिकार के बिना नहीं की जा सकती, लेकिन सरकार ने लोकपाल तो बनाया, पर उसे जांच के कोई अधिकार नहीं दिए. अधिकार सिर्फ़ इतना दिया गया कि वह संबंधित मामले की जांच सीबीआई, ईडी या किसी अन्य जांच एजेंसी से करा सकती है. जांच में क्या हो रहा है, आरोपी को गिरफ्तार करना है या नहीं, उसके घर छापा मारना है या नहीं, सबूत इकट्ठा करने के लिए क्या करना है आदि बातों से लोकपाल को कोई लेना-देना नहीं है. वह जांच अधिकारी या एजेंसी से कोई पूछताछ नहीं कर सकता, वह सिर्फ़ जांच एजेंसियों की रिपोर्ट पर ही कार्रवाई कर सकता है. 2-जी स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम्स या फिर हसन अली के मामले में जांच एजेंसियों ने क्या किया, यह जगज़ाहिर है. सुप्रीम कोर्ट अगर प्रोएक्टिव न होता तो इन बड़े-बड़े घोटालों में किसी को कुछ नहीं होता.

संसद और राजनीतिक दलों ने एक अजीबोग़रीब संदेश दिया है. लोकपाल के दायरे से बड़ी-बड़ी कंपनियों को बाहर कर दिया गया. इस काम में सभी पार्टियों ने सरकार की मदद की. 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाला हो या कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला, देश में भ्रष्टाचार का तरीका बदला है. आज जितने भी घोटाले होते हैं, उनमें बड़ी-बड़ी कंपनियां शामिल रहती हैं, जो अधिकारियों को रिश्वत देती हैं, काग़ज़ों पर शब्दों के हेरफेर से करोड़ों रुपये कमाती हैं. ये बड़ी-बड़ी कंपनियां अधिकारियों और नेताओं से हाथ मिलाकर देश की खनिज संपदा लूट रही हैं, किसानों की ज़मीनों पर क़ब्ज़ा कर रही हैं. सरकारी लोकपाल क़ानून में इन कंपनियों के ख़िलाफ़ कोई प्रावधान नहीं है. अब ऐसे में निष्कर्ष यही निकाला जा सकता है कि सरकार भ्रष्टाचार को ख़त्म करना ही नहीं चाहती है, क्योंकि इन कंपनियों से नेताओं, अधिकारियों और राजनीतिक दलों की कमाई होती है. जनता का राजनीतिक दलों से विश्वास उठता जा रहा है. सरकार ही अगर संसद में हंगामा करने लग जाए तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है. दूसरे राजनीतिक दलों का रवैया भी टालमटोल वाला रहा. देश की जनता को इन राजनीतिक दलों का चरित्र पहचानने की ज़रूरत है. जनता को इनकी जवाबदेही तय करने की ज़रूरत है, वरना लोकपाल बिल हमेशा के लिए लटका रह जाएगा. अन्ना हजारे और भ्रष्टाचार से लड़ने वाले अन्य लोगों के सामने चुनौती है. उन्हें नए सिरे से आंदोलन का आगाज करना होगा, सरकार और राजनीतिक दलों पर दबाव बनाना होगा, ताकि भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ एक निर्णायक लड़ाई की शुरुआत हो सके.

manish@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 3 अंक 44
दिल्ली, 09 जनवरी–15 जनवरी 2012
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
प्रथम तल, विराट कॉम्प्लेक्स के पीछे, सरदार पटेल पथ, कृष्णा अपार्टमेंट के नज़दीक, बोरिंग रोड, पटना-800013
फोन : 0612 2570092, 9431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे-3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ-226001
फोन : 0522-2204678, 9415005111

प्रबंध संपादक
श्रीनिवास गुप्ता (ठाकुर) (उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)
सी-20, ट्रांस यमुना, एनएच-2, आगरा
फोन : 0526-4064901, 9837082462

प्रबंध संपादक (महाराष्ट्र)
प्रवीण महाजन
मुरलीधर कॉम्प्लेक्स, बुटीवाडा के सामने होटल गणराज के बाजू में टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर-440012
फोन नं : 0712-2544988, 2549846

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-4783999/011-23418962
0120-6450888, 0120-6452888
0120-6451999
विज्ञापन व प्रसार +91 120-4783999
+91 9266627366
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

राहुल गांधी की छात्र राजनीति को बल देने और युवाओं को राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ने वाली क़वायद भी प्रदेश में नाकाम हो चुकी है.

राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश

मिशन-2012 दूर की कौड़ी

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

राहुल गांधी के अपने लोग ही उत्तर प्रदेश में उनका खेल ख़राब करने में लगे हैं. कांग्रेस के कुछ पुराने दिग्गज राहुल गांधी से नाराज़ हैं. वज़ह है राहुल गांधी द्वारा बेनी प्रसाद वर्मा, पी एल पुनिया और राजबब्बर को उनके मुक़ाबले ज़्यादा महत्व दिया जाना. उत्तर प्रदेश में पिछले साल से ही कांग्रेस के पक्ष में चुनावी फिज़ा तैयार करने में लगे ये पुराने कांग्रेसी नेता पिछड़ों के टिकट बंटवारे में बेनी प्रसाद वर्मा को मिल रही अहमियत से चिढ़ गए हैं. कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों से जूझने के बजाय आपस में ही असली कांग्रेसी बनाम बाहरी का मुद्दा लेकर सिर-फुटौव्वल कर रहे हैं, जो राहुल गांधी के हसीन सपने यानी मिशन-2012 के लिए घातक साबित हो रहा है.

रूबी अरुण

उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह, रीता बहुगुणा जोशी और प्रमोद तिवारी को फ्रंट लाइन के योद्धा के तौर पर नियुक्त किया, जबकि प्रदीप जैन, आरपीएन सिंह एवं जतिन प्रसाद जैसे युवाओं को उन्हें बैकअप देने का काम सौंपा गया. बेनी प्रसाद वर्मा, सलमान खुर्शीद, राजीव शुक्ला एवं श्रीप्रकाश जायसवाल जैसे अनुभवी कांग्रेसियों को रणनीति बनाने और सबके बीच समन्वय बनाए रखने की ज़िम्मेदारी दी गई. राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में जीत पक्की करने की गरज से काफ़ी पहले से ही जुगत शुरू कर दी थी. उन्होंने जाति आधारित मैप तैयार किया और उस पर सरकार से अमल भी कराया. केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल करके बेनी प्रसाद वर्मा को राज्यमंत्री से केंद्रीय मंत्री बनाया गया. सलमान खुर्शीद को क़ानून मंत्री जैसा अहम पद देना और राजीव शुक्ला को मंत्री बनाना मिशन–2012 की ही कवायद थी, लेकिन राहुल की सारी ज़द्दोजहद कोई रंग लाती नहीं दिख रही. पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में जो मारामारी हुई थी, बिल्कुल वही कहानी उत्तर प्रदेश में दोहराई जा रही है. राहुल गांधी लगातार पूरी स्थिति पर नियंत्रण रखने की कोशिश में जुटे हैं, बावजूद इसके टिकट बंटवारे से लेकर चुनावी सभावों तक यह गुटबंदी साफ़–साफ़ दिख रही है.

कभी मायावती के ख़ासमख़ास रहे पी एल पुनिया ने अंदर ही अंदर अपनी ही पार्टी के बेनी प्रसाद वर्मा के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया है. पुनिया के हिमायती इस शिगूफ़े को ज़ोर–शोर से हवा में उछाल रहे हैं कि बेनी प्रसाद वर्मा समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं और वह कांग्रेस का नुकसान करने की नीयत से ही इसमें शामिल हुए हैं. इस ज़हर बयानी के नतीजे कांग्रेस की सेहत के लिए कितने विपरीत जा रहे हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब फूलपुर की चुनावी सभा में राहुल गांधी ने बेनी प्रसाद वर्मा को अपने बगल में बैठाया तो इससे तिलमिलाए पुनिया समर्थक राहुल गांधी की मौजूदगी में ही वर्मा के समर्थकों से भिड़ गए. दूसरी तरफ टिकट बंटवारे के मसले पर ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी और प्रदेश के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने एक–दूसरे के ख़िलाफ़ तलवारें खींच रखी हैं. इन दोनों नेताओं को कार्यकर्ताओं के सामने भी एक–दूसरे पर चीखने–चिल्लाने से कोई परहेज़ नहीं है. रीता बहुगुणा जोशी और प्रमोद तिवारी के दो गुट बन चुके हैं और दोनों गुट पार्टी की बैठकों में एक–दूसरे पर सरेआम पैसे लेकर टिकट बेचने का इलज़ाम लगाने से नहीं चूकते. अब तो प्रमोद तिवारी के समर्थक उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी के बराबर कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग करने लगे हैं. इसके लिए वे कांग्रेस के कुछ चुनिंदा बड़े नेताओं से लगातार संपर्क में भी हैं.

दूसरी तरफ 16 साल तक कांग्रेस के वफ़ादार रहे सभासद राजेंद्र सिंह गप्पू, जो अपनी दावेदारी वाली कैंट विधानसभा सीट से कर रहे थे, उसे रीता बहुगुणा जोशी द्वारा हड़प लिए जाने से नाराज़ होकर समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं. उनका अभियान भी राहुल के चुनावी नाद को धूमिल कर रहा है. राजेंद्र सिंह गप्पू की नाराज़गी पहली सूची जारी होने के बाद ही सामने आ गई थी, पर उस वक़्त राहुल ने इस मसले को तवज्जो नहीं दी, जो अब उनके लिए भारी साबित हो रहा है. उधर राजबब्बर को मीडिया अभियान का ज़िम्मा दिए जाने से भी पार्टी के अंदर नाराज़गी है. कुल मिलाकर प्रदेश कांग्रेस के अंदर चल रही इस खींचतान का नतीजा पार्टी को ज़मीनी स्तर पर भुगतना पड़ रहा है. राहुल गांधी की छात्र राजनीति को बल देने और युवाओं को राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ने वाली कवायद भी प्रदेश में नाकाम हो चुकी है. युवक कांग्रेस में ज़बरदस्त दरार पड़ चुकी है. हालांकि कांग्रेस की युवा ब्रिगेड, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के बीच पहले से मनमुटाव चल रहा था, पर अब यह नाराज़गी खुलकर सामने आने लगी है और उन्हें राहुल गांधी का भी कोई लिहाज़ नहीं रहा. यही वज़ह है कि जब प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुबोध श्रीवास्तव का टिकट कांग्रेस ने काट दिया तो लखनऊ के अमौसी हवाई अड्डे पर यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने राहुल गांधी की गाड़ी रोककर बड़े ही तल्ख़ अंदाज़ में अपना विरोध दर्ज कराया. सुबोध लखनऊ के मध्य विधानसभा क्षेत्र से टिकट चाहते थे, लेकिन तीसरी सूची में भी उनका नाम नहीं आया और उनकी जगह हाल में बसपा से आए फाकिर सिद्दीक़ी को टिकट दे दिया गया. इसी बात से नाराज़ होकर उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफ़ा दे दिया. अब सुबोध के समर्थक जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हुआ करते थे, उन्होंने कांग्रेस के ख़िलाफ़ कमान संभाल ली है.

युवा कांग्रेस भी फूट का अड्डा बन गई है, जिसका बड़ा कारण रहा उसका लोकतांत्रिक ढंग से कराया गया चुनाव. उत्तर प्रदेश को विभिन्न जोनों में बांटकर चुनाव कराए गए, जिनमें कई पदाधिकारी चुनकर आए. यही चुनाव संगठन के लिए कड़वाहट भरे हो गए. चुनाव में हारे हुए सदस्यों ने जीते हुए पदाधिकारियों का साथ देना बंद कर दिया. युवा कांग्रेस में भयंकर गुटबाजी शुरू हो गई. आज आलम यह है कि एक गुट का व्यक्ति दूसरे गुट के व्यक्ति से बात तक नहीं करता. सहज सोचा जा सकता है कि जब राहुल गांधी के सपनों को साकार करने वाली यूथ कांग्रेस ही इस क़दर बिखरी हुई है तो वह आमजनों–मतदाताओं को कांग्रेस से क्या खाक जोड़ पाएगी. यही हाल एनएसयूआई का है. मज़े की बात तो यह है कि यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई में हो रही गुटबाज़ी का फ़ायदा समाजवादी युवजन सभा और समाजवादी छात्रसभा जमकर उठाने लगी हैं. वे कांग्रेस से नाराज़ कार्यकर्ताओं का रुख़ अपनी ओर करने में सफल भी हो रही हैं. नतीजतन, हो यह रहा है कि यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई कांग्रेस की मज़बूती के बजाय अगले चुनाव में अपने–अपने प्रत्याशियों को लड़ाने की तैयारी में लग गए हैं. कांग्रेस नेताओं के इन आपसी झगड़ों और गुटबाज़ियों से चुनावी तैयारियां प्रभावित हो रही हैं. बिहार में नेताओं की इसी गुटबाज़ी ने कांग्रेस को मिट्टी में मिला दिया, जहां उसे विधानसभा की 243 सीटों में से सिर्फ़ चार सीटें मिल पाईं.

वैसे तो यह चुनाव चारों मुख्य पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है, पर कांग्रेस के लिए यह ख़ास मायने इसलिए रखता है, क्योंकि यहां राहुल गांधी की निजी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है. लोकसभा चुनाव में कुछ बेहतर प्रदर्शन के बाद से राहुल का उत्तर प्रदेश का मिशन–2012 शुरू हो गया था, जिसका लक्ष्य उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनवाना था. 2012 आने के साथ अब शायद ही कोई कांग्रेसी यह सोच रहा हो कि पार्टी अपने बूते सरकार बना सकेगी. लिहाज़ा अब मिशन–2012 का मक़सद ज़्यादा से ज़्यादा वहां की सरकार के गठन में अपनी भूमिका निभाना और सम्मानजनक संख्या में विधानसभा सीटें पाना हो सकता है. लेकिन, प्रदेश में पार्टी के जो अंदरूनी हालात हैं, उनमें ऐसा होना भी मुमकिन नहीं दिख रहा. उत्तर प्रदेश में कमान संभालने वाले सभी कांग्रेसी वरिष्ठ हैं और सबकी अपनी दमित इच्छाएं भी हैं. राहुल गांधी की मुश्किल यह है कि वह न तो पार्टी नेताओं की ख्वाहिशों पर लगाम लगा पा रहे हैं और न अपने आक्रामक–मुखर तेवरों से विपक्षी पार्टियों पर करीने से धावा बोल पा रहे हैं. अब तो कांग्रेस के युवराज के पास इतना भी वक़्त नहीं है कि वह डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करें, लिहाज़ा उनके लिए मिशन–2012 अब दूर की कौड़ी नज़र आ रहा है.

ruby@chauthiduniya.com

युवा कांग्रेस भी फूट का अड्डा बन गई है, जिसका बड़ा कारण रहा उसका लोकतांत्रिक ढंग से कराया गया चुनाव. उत्तर प्रदेश को विभिन्न ज़ोनों में बांटकर चुनाव कराए गए, जिनमें कई पदाधिकारी चुनकर आए. यही चुनाव संगठन के लिए कड़वाहट भरे हो गए. चुनाव में हारे हुए सदस्यों ने जीते हुए पदाधिकारियों का साथ देना बंद कर दिया. युवा कांग्रेस में भयंकर गुटबाज़ी शुरू हो गई. आज आलम यह है कि एक गुट का व्यक्ति दूसरे गुट के व्यक्ति से बात तक नहीं करता. सहज सोचा जा सकता है कि जब राहुल गांधी के सपनों को साकार करने वाली यूथ कांग्रेस ही इस क़दर बिखरी हुई है तो वह आमजनों-मतदाताओं को कांग्रेस से क्या खाक जोड़ पाएगी.

कभी मायावती के ख़ासमख़ास रहे पी एल पुनिया ने अंदर ही अंदर अपनी ही पार्टी के बेनी प्रसाद वर्मा के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया है. पुनिया के हिमायती इस शिगूफ़े को ज़ोर-शोर से हवा में उछाल रहे हैं कि बेनी प्रसाद वर्मा समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं और वह कांग्रेस का नुक़सान करने की नीयत से ही इसमें शामिल हुए हैं. इस ज़हर बयानी के नतीजे कांग्रेस की सेहत के लिए कितने विपरीत जा रहे हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब फूलपुर की चुनावी सभा में राहुल गांधी ने बेनी प्रसाद वर्मा को अपने बगल में बैठाया तो इससे तिलमिलाए पुनिया समर्थक राहुल गांधी की मौजूदगी में ही वर्मा के समर्थकों से भिड़ गए.

देखते-देखते बिक्रमगंज की सभा कुछ पलों के लिए ऐसी बिगड़ गई कि लोग हवा में कुर्सियां लहराने लगे.

बिहार

नीतीश की सभा में कुर्सियां क्यों उछलीं

सरोज सिंह

सत्ता की राजनीति में कुर्सियों का हिलना-डुलना शुभ नहीं माना जाता है. ऐसे में अगर कुर्सियां उछाली जाने लगें तो उसे ख़तरे की घंटी ही समझिए. सेवा यात्रा के दौरान बिक्रमगंज में मुख्यमंत्री की सभा में जब नाराज़ लोगों ने कुर्सियां लहरानी शुरू कर दीं तो सभी अवाक रह गए. पटना में फोन की घंटियां घनघनाने लगीं. एक ही सवाल, यह क्या हो गया. सुशासन में इस तरीक़े का विरोध अपने आप में ऐसा सवाल है कि क्या कोरे वायदों से लोगों का भ्रम टूट रहा है और बिहार की जनता अब यह समझने लगी है कि अभी ज़मीनी विकास के रास्ते में बहुत सारी बाधाएं हैं. कुर्सी उछाल कर जिस विरोध का एहसास कराने की कोशिश की गई, दरअसल वह गुस्सा शाहाबाद में दुर्गावती एवं इंद्रपुरी जलाशय परियोजनाओं सहित जनहित के कई मसलों, जैसे कि चावल एवं पत्थर उद्योग पर सरकार की वायदाख़िलाफ़ी, लेटलतीफी और वोट की राजनीति को लेकर जनता के दिल व पेट पर लगी चोट की एक झलक मात्र है. अगर नीति और नीयत साफ न हुई तो तख्त-ओ-ताज बदलने के लिए शाहाबाद की धरती पहले भी नाम कमा चुकी है.

दरअसल, इस बार सेवा यात्रा के दौरान नीतीश कुमार को कई ज़िलों में जनता की नाराज़गी का शिकार होना पड़ रहा है. बेतिया, मुज़फ्फरपुर और सहरसा की कहानी सभी जानते हैं. इसी क्रम में सुरक्षा के बड़े तामझाम और पुख्ता प्रबंधों के बीच रोहतास में भी सेवा यात्रा हुई. शुरुआती दौर में ठीकठाक चली यात्रा में लोग नई घोषणाओं की आस में सुशासन बाबू की ओर टकटकी लगाए बैठे थे. मुख्यमंत्री ने दुर्गावती जलाशय परियोजना, इंद्रपुरी सोन बैराज, रोहतासगढ़ किला, जलालपुर और तेनुअज के खेत-खलिहानों में अपने काफिले के साथ किसानों के बीच जाकर उनकी बात सुनी. अंत में बिक्रमगंज की सभा में लोग इसलिए जुटे कि यही वह समय है, जब मुख्यमंत्री रोहतास को कुछ देने की घोषणा करेंगे. सभा की शुरुआत होते ही भीड़ ने ऐसे तेवर दिखाए कि मुख्यमंत्री की चार दिवसीय सुखद यात्रा दु:खद पहलू में बदल गई. मंच पर काराकाट के जदयू सांसद महाबली के आते ही भीड़ ने उनसे वापस जाने की मांग करते हुए नारेबाज़ी शुरू कर दी. इसी के साथ सुशासन की बखिया उधेड़ने का काम शुरू हो गया. यह गुबार रोहतास के ज़िला मुख्यालय सासाराम में आयोजित जनता दरबार में पत्थर उद्यमियों को सुनाई गई खरी-खोटी और कई समस्याओं का निराकरण न होने के कारण बाहर निकल रहा था.

देखते-देखते बिक्रमगंज की सभा कुछ पलों के लिए ऐसी बिगड़ गई कि लोग हवा में कुर्सियां लहराने लगे. वैसे तो सेवा यात्रा की किरकिरी 23 दिसंबर से ही शुरू हो गई थी, जब डेहरी में मुख्यमंत्री द्वारा कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा के अनावरण के बाद अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र ठाकुर ने उसे यह कहकर दूध से धो डाला कि नीतीश कुमार को कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा छूने का कोई अधिकार नहीं है. उन्होंने ज़िले में घूम-घूमकर एक पर्चा वितरित किया, जिसमें लिखा था कि 1978 के वैशाली ज़िला अंतर्गत सराय सम्मेलन में नीतीश कुमार और उनकी टीम ने कर्पूरी ठाकुर द्वारा अति पिछड़ों के संदर्भ में दिए गए आरक्षण फॉर्मूले का विरोध किया था. सेवा यात्रा का विरोध राजद ने 10 दिन पहले से ही शुरू कर दिया था. पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राम बिहारी सिंह एवं पूर्व विधायक ललन पासवान ने दुर्गावती जलाशय परियोजना को लेकर ज़बरदस्त मोर्चाबंदी की. जिस दिन सेवा यात्रा की शुरुआत हुई, उसी दिन इन नेताओं ने ज़िला मुख्यालय में दुर्गावती जलाशय परियोजना के सवाल पर एक बड़ा धरना आयोजित किया, जिसमें शाहाबाद के हितों से जुड़े कई मुद्दे उठाए गए. सेवा यात्रा के दौरान जब मुख्यमंत्री उक्त परियोजना का निरीक्षण करने पहुंचे और उन्होंने उसके संबंध में कोई ठोस वायदा नहीं किया तो राजद की घेराबंदी का असर साफ दिखा.

इस बार सेवा यात्रा के दौरान नीतीश कुमार को कई ज़िलों में जनता की नाराज़गी का शिकार होना पड़ रहा है. बेतिया, मुज़फ्फरपुर और सहरसा की कहानी सभी जानते हैं. इसी क्रम में सुरक्षा के बड़े तामझाम और पुख्ता प्रबंधों के बीच रोहतास में भी सेवा यात्रा हुई. शुरुआती दौर में ठीकठाक चली यात्रा में लोग नई घोषणाओं की आस में सुशासन बाबू की ओर टकटकी लगाए बैठे थे. मुख्यमंत्री ने दुर्गावती जलाशय परियोजना, इंद्रपुरी सोन बैराज, रोहतासगढ़ किला, जलालपुर और तेनुअज के खेत-खलिहानों में अपने काफिले के साथ किसानों के बीच जाकर उनकी बात सुनी.

इन परिस्थितियों के बाद भी लोगों को उम्मीद थी कि बिक्रमगंज की सभा में मुख्यमंत्री ज़रूर कुछ नया कहेंगे, लेकिन जब उन्होंने वहां भी पुराना राग अलापा तो पता चला कि धान के कटोरे रोहतास के लिए सेवा यात्रा में कुछ भी नहीं था. कुछ देर के लिए मुख्यमंत्री रोहतासगढ़ किला ज़रूर गए और उसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की बात कही, लेकिन यह बात पिछले 20 वर्षों से कही जा रही है. मुख्यमंत्री ने सेवा यात्रा के सफल संचालन हेतु प्रशासन को धन्यवाद दिया. उनके चले जाने के बाद रोहतास के लोगों में पत्थर उद्योग को लेकर उनकी तरफ़ से मिले जवाब, दुर्गावती जलाशय परियोजना के संबंध में गोलमटोल अंदाज़, रोहतासगढ़ किले और धान ख़रीददारी को लेकर हो रही नाटकबाज़ी की चर्चा ख़ूब है. राजद प्रवक्ता रामबिहारी सिंह कहते हैं कि सेवा यात्रा में शाहाबाद की जनता ठग ली गई. धान के कटोरे में धान की ख़रीददारी में सरकार पूरी तरह विफल रही. जनता को उम्मीद थी कि सेवा यात्रा में नीतीश कुमार शाहाबाद को उसका वाजिब हक देंगे, मगर वह सिर्फ़ गोलमटोल बातें करके चले गए. लगता है, झूठे वायदे करने में उन्होंने पीएचडी कर रखी है, लेकिन शाहाबाद की जनता उन्हें समझ चुकी है और वह सही समय पर अपना फ़ैसला ज़रूर सुनाएगी. पूर्व विधायक ललन पासवान कहते हैं कि देखते जाइए, अभी तो विरोध की शुरुआत है. जनता बहुत त्रस्त है और राजद जल्द ही पूरे बिहार में इस सरकार को बेनकाब कर देगा.

साथ में ममता चौहान
feedback@chauthiduniya.com

महाराष्ट्र

राजेश नामदेव

चंदे के फंदे में मंत्री

बाएं से क्रमश: हर्षवर्द्धन पाटिल, छगन भुजबल एवं गणेश नाईक

पावर और पैसा आज हर महत्वाकांक्षी व्यक्ति की चाहत है. जिसके पास पावर है, उसके पास पैसे वाले स्वयं चले आते हैं. व्यवसायी, ठेकेदार एवं उद्योगपति पावर के चारों ओर सौर मंडल के ग्रहों की तरह चक्कर लगाते नज़र आते हैं. उनकी निकटता पाकर मंत्री-संतरी भी उनसे अपना उल्लू सीधा करने में गुरेज़ नहीं करते. देश की जिस कंपनी का साम्राज्य जितना बड़ा होता है, राजनेताओं से उसके उतने ही गहरे संबंध होते हैं. कंपनियां अपने हित में पावर को दुहने की खातिर राजनेताओं से संबंध मेंटेन रखने के लिए तोहफ़ों-चंदों का सहारा लेती हैं और नेता कंपनियों को दुहने के लिए पार्टी फंड एवं अपने सामाजिक कार्यों के नाम पर उनसे चंदा वसूलती हैं. आजकल महाराष्ट्र की राजनीति में मंत्रियों द्वारा कुछ कंपनियों से अपने-अपने सामाजिक संगठनों के नाम मोटी रक़म लेने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. यह मुद्दा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी उठा, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया गया.

राज्य के सार्वजनिक निर्माण कार्य मंत्री छगन भुजबल द्वारा इंडिया बुल्स कंपनी से अपने नाम पर गठित भुजबल फाउंडेशन के लिए 2 करोड़ 45 लाख रुपये लिए जाने का मामला विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ही अख़बारों की सुर्ख़ियां बन गया. इससे यह सवाल उठ खड़ा हुआ कि मंत्रियों के ट्रस्टों एवं संगठनों द्वारा औद्योगिक कंपनियों से पैसा लेना कितना उचित, कितना नैतिक है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है, क्योंकि ईमानदारी से कार्य करने वाले सामाजिक संगठनों को बड़ी कंपनियां कभी घास तक नहीं डालती हैं, लेकिन वे समाजसेवा का ढिंढोरा पीटने वाले नेताओं के पारिवारिक ट्रस्टों एवं संगठनों को करोड़ों रुपये आसानी से दे देती हैं. विधानसभा में इस मामले को उठाते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के विधायक बाला नांदगांवकर ने कहा कि इंडिया बुल्स कंपनी से सार्वजनिक निर्माण कार्य मंत्री छगन भुजबल के मधुर संबंध होने के चलते उनके कामकाज में संदेह की स्थिति पैदा हो गई है. उन्होंने इतिहास याद दिलाते हुए कहा कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के लिए एक लाख रुपये का चंदा स्वीकार करने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री ए आर अंतुले को विपक्ष के भारी विरोध के चलते इस्तीफ़ा देना पड़ा था. उस समय अंतुले से इस्तीफ़ा देने की मांग करने वालों में शरद पवार भी शामिल थे. विशेष बात यह है कि छगन भुजबल उसी पार्टी के नेता हैं, जिसके मुखिया आज शरद पवार हैं, लेकिन पार्टी ने छगन भुजबल के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चंदा लेने के बदले में सार्वजनिक निर्माण मंत्रालय द्वारा विकास के कई कार्य उक्त कंपनी को दिए गए.

भारतीय जनता पार्टी के नेता एकनाथ खड़से ने कुछ और ख़ुलासे किए. खड़से ने सदन को बताया कि छगन भुजबल के अलावा संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन पाटिल और उत्पादन शुल्क (कर) व ग़ैर परंपरागत ऊर्जा मंत्री गणेश नाईक ने भी अपने-अपने ट्रस्टों एवं संगठनों के लिए करोड़ों में चंदा वसूल किया है, जिसके सबूत उनके पास हैं. उन्होंने कहा कि उत्पादन शुल्क मंत्री नाईक के शिव संग्राम ट्रस्ट को पिछले दस वर्षों में करोड़ों रुपये का चंदा मिला. इसी तरह संसदीय कार्य मंत्री पाटिल के शाह जी प्रतिष्ठान को एक दिन में 16 करोड़ रुपये का चंदा दिया गया. खड़से ने पाटिल पर कई नागरी सहकारी बैंकों को कर्ज़ माफ़ी का लाभ दिलाने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि मंत्री पैसे लिए जाने से इंक़ार करते हैं, लेकिन दूसरी ओर कामकाज के बदले कंपनियों से अपने ट्रस्टों एवं संगठनों के नाम पर करोड़ों रुपये वसूल करते हैं. कंपनियां मंत्रियों के ट्रस्टों-संगठनों को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से पैसे देती हैं. अपने पास इसके सबूत होने का दावा करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण से इस मामले की जांच कराने की मांग की. चव्हाण ने यह कहते हुए इस मामले को ख़त्म कर दिया कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसकी जानकारी ली जाएगी. बावजूद इसके चंदे के फंदे का मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ है. इस पर बहस शुरू हो गई है.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सभी बड़ी कंपनियों से नेताओं के मधुर संबंध रहते हैं. जिन कंपनियों के मंत्रियों से संबंध नहीं होते, उनके प्रोजेक्ट्स की फाइलें आसानी से आगे नहीं बढ़ती हैं. हर मंत्री के किसी न किसी कंपनी के अध्यक्ष या प्रबंधन से मधुर संबंध रहते हैं. कंपनियों से मधुर संबंध होने का फ़ायदा मंत्री एवं उनके घर वाले किसी न किसी रूप में उठाते हैं. कोई अपने पुत्र-पुत्रियों को कंपनी में डायरेक्टर बनवा देता है तो कोई शेयर होल्डर हो जाता है. इसके अलावा मंत्री अपनी पार्टी को फंड दिलाते हैं तो कई अपने ट्रस्टों एवं संगठनों के लिए चंदे में मोटी रक़म वसूल करते हैं. यह काम सिर्फ़ राजनेता ही नहीं करते, बल्कि कई ऊंचे पद पर बैठे अफसरशाहों द्वारा भी कंपनियों से येन-केन-प्रकारेण लेनदेन किया जाता है. यहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है. व्यापार जगत में बिना उद्देश्य कोई लेनदेन नहीं होता, लेकिन कोई भी सरकार इस विषय को गंभीरता से नहीं लेती. वजह यह है कि इन बड़ी कंपनियों से सभी दलों के वरिष्ठ नेताओं के संबंध होते हैं. भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय प्रमोद महाजन के अनिल अंबानी से मधुर संबंध होने की चर्चा कई बार हो चुकी है. राकांपा नेता शरद पवार की पुत्री एवं दामाद के लवासा कॉरपोरेशन और डी बी रियलटी जैसी कंपनियों से संबंध होने की बातें सामने आ चुकी हैं. इंडिया बुल्स में कई बड़े नेताओं के शेयर होल्डर होने की बातें जब-तब उठती रहती हैं. आख़िर कुछ न कुछ बात ज़रूर होगी, तभी तो चर्चा हो रही है.

feedback@chauthiduniya.com

देश को जगाने के लिए निकला हूं और उसके जागने तक चुप नहीं बैठूंगा. अन्ना ने भी साफ कर दिया है कि वह उत्तर प्रदेश में घूम-घूमकर जनता को बताएंगे कि केंद्र सरकार ने जन लोकपाल पर लोगों को किस तरह गुमराह किया.

उत्तर प्रदेश

अन्ना और रामदेव

कांग्रेस के लिए ख़तरा

अजय कुमार

सरकार और राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए किस तरह लोगों की छवि धूमिल करते हैं, इसकी ताजा मिसाल हैं समाजसेवी अन्ना हजारे और योग गुरु बाबा रामदेव. कुसूर यह है कि एक जनता को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए सख्त क़ानून की वकालत कर रहा है और दूसरा विदेशों में जमा काला धन वापस मंगाने के लिए हाथ-पैर मार रहा है. दोनों को केंद्र सरकार ने तर्कों-कुतर्कों के सहारे विवादित बनाने का अभियान चला दिया. छवि धूमिल करने के लिए ऐसे शिगूफे छोड़े गए कि लोग दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए. कभी संसद के अंदर तो कभी बाहर उन्हें खरी-खोटी सुनाई गई. उनके साथ खड़े होने वालों का भी मज़ाक उड़ाया गया. श्रीश्री रविशंकर भी अछूते नहीं रह सके. राजनीति से दूर रहने वाले लोगों से पूछा गया कि वे किसके इशारे पर जनता के हित के लिए अभियान चला रहे हैं. मानों कांग्रेस को छोड़कर किसी अन्य को जनहित की बात करने का अधिकार न हो. हद तो तब हो गई, जब कांग्रेस के अंदर कहा जाने लगा कि 125 साल के इतिहास में कई लोग चुनौती देने आए और चले गए, लेकिन कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया. कांग्रेस की तरफ़ से अन्ना, बाबा रामदेव एवं श्रीश्री रविशंकर को भाजपा और संघ का ए, बी और सी प्लान बताया जा रहा है. भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जो भी आवाज़ उठाता है, कांग्रेस उसका गला घोंट देना चाहती है. कांग्रेस को सख्त लोकपाल से परहेज है, इसलिए वह उसे संसद के माध्यम से लटकाए रखना चाहती है. सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस लोकपाल के ख़िलाफ़ क्यों है और लोग उसके जवाब में राहुल गांधी की ओर इशारा कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश में यह आम धारणा है कि कांग्रेस अपने भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी के रास्ते में लोकपाल रूपी रोड़ा नहीं डालना चाहती. इसके लिए उसे न संसद की अवमानना की चिंता है और न संविधान के ख़िलाफ़ जाने से परहेज. कांग्रेस सख्त लोकपाल लाने से बचने के लिए जो टोटके आजमा रही है, वे कहीं उत्तर प्रदेश में उसकी राह में बाधक न बन जाएं. कांग्रेस के बड़े नेता ऐसी चर्चा करने से भले बच रहे हों, लेकिन आम कांग्रेसी को लगातार यह भय सता रहा है कि मतदाताओं की नाराज़गी कहीं भारी न पड़ जाए. अन्ना और बाबा रामदेव कांग्रेस के ख़िलाफ़ हुंकार भर रहे हैं. यह हुंकार चुनाव आते-आते दहाड़ में बदल सकती है. अन्ना अपनी टीम के साथ उत्तर प्रदेश सहित पांचों राज्यों का दौरा करके कांग्रेस और सरकार की कलई खोलने के लिए बेताब हैं. और तो और, जिन युवाओं को राहुल गांधी अपनी ताक़त समझ रहे थे, वे भ्रष्टाचार और लोकपाल के प्रति उनके ढुलमुल रवैये से आहत होकर अन्ना के साथ खड़े हो गए हैं.

यह लगभग तय हो गया है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आंदोलन की अगुवाई कर रहे अन्ना हजारे के साये में होंगे. बाबा रामदेव भी काला धन प्रकरण पर कांग्रेस की नाक में दम भरने का कोई मौक़ा नहीं छोड़ेंगे. वह झांसी से शुरू हुई अपनी 10 हज़ार किलोमीटर की भारत स्वाभिमान यात्रा भी पूरी कर चुके हैं. यात्रा के दौरान उन्होंने दोहराया कि यह संग्राम सड़क से संसद तक चलेगा. देश को जगाने के लिए निकला हूं और उसके जागने तक चुप नहीं बैठूंगा. अन्ना ने भी साफ कर दिया है कि वह उत्तर प्रदेश में घूम-घूमकर जनता को बताएंगे कि केंद्र सरकार ने जन लोकपाल पर लोगों को किस तरह गुमराह किया. इंडिया अगेंस्ट करप्शन की कोर कमेटी के सदस्य अंशुमालि शर्मा कहते हैं कि अन्ना के दौरे का सीधा असर विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा. टीम अन्ना शुरू से ही स्वच्छ छवि का प्रत्याशी चुनने की मुहिम चला रही है. मतदान के दिन युवा मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यकर्ता नए मतदाता बनाने का अभियान भी चला रहे हैं. अन्ना को अगर युवाओं का साथ मिल गया तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के युवराज का सपना टूट सकता है.

राष्ट्रीय सेवा योजना संगठन की सक्रियता का ही परिणाम था कि इस बार लखनऊ में दो लाख नए मतदाताओं में डेढ़ लाख युवा शामिल हैं. पूरे प्रदेश में यह आंकड़ा और भी मज़बूत होता दिख रहा है. राजनीति से दूर, मौजमस्ती को तरजीह देने वाले युवा अन्ना के कारण पहली बार राजनीतिक रूप से परिपक्व दिख रहे हैं. उन्हें अन्ना के रूप में आईकॉन मिल गया है. राजनीति को लेकर भ्रमित रहने वाले युवा आज अन्ना को अपने युग का महात्मा गांधी मानते हैं. आख़िर राजनेताओं ने उन्हें बेरोज़गारी और शिक्षा के व्यवसायीकरण के अलावा दिया ही क्या है. उच्च शिक्षा हासिल करना गरीब ही नहीं, निम्न मध्यम परिवार के होनहार बेटे-बेटियों के लिए भी सपने जैसा हो गया है. लंबे समय के बाद युवाओं को कोई ऐसा जननेता दिखा, जिसकी बात में दम है और हौसलों में फौलाद. 74 वर्षीय अन्ना हजारे ने जिस तरह 13 दिनों तक भूखे रहकर जनता के सवालों और चिंताओं को सरकार तक पहुंचाया, वह विरले लोग कर सकते हैं. अगर अन्ना ने किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जाकर जन लोकपाल बिल पर सरकार के धोखे को बयान किया तो वहां कांग्रेस प्रत्याशी की राह मुश्किल हो जाएगी. इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है. युवाओं को लक्ष्य करके उनके बीच कांग्रेस के ख़िलाफ़ चुनावी अभियान चलाया जा रहा है. उत्तर प्रदेश के पूर्व नौकरशाह अखंड प्रताप सिंह कहते हैं कि अन्ना की अपील चुनाव में असर दिखाएगी. ऐसे में अन्ना को यह ज़रूर ध्यान रखना होगा कि हर राजनीतिक दल में भ्रष्ट और आपराधिक किस्म के लोग हैं, इसलिए उनकी अपील से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वह किसी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध कर रहे हैं.

लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति रूपरेखा वर्मा कहती हैं कि आम जनता का अन्ना के प्रति विशेष लगाव है. वह भ्रष्टाचार से त्रस्त है, वह जन लोकपाल बिल की बारीकियां तो नहीं समझती, लेकिन एक ऐसा बिल चाहती है, जिससे उसे भ्रष्टाचार से छुटकारा मिले. उसकी सोच यह है कि अन्ना हजारे तो फकीर जैसे हैं, उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए. वह जनता के हित में सख्त लोकपाल बिल चाहते हैं, जिसमें सीबीआई हो और सी-डी ग्रेड के कर्मचारी भी. उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनके कूदने से कांग्रेस के ख़िलाफ़ माहौल बन सकता है. कांग्रेसी अक्सर कहते हैं कि अन्ना कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं और भाजपा को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि पार्टी और सरकार अपने वचन से पीछे क्यों हट रही है. कभी वह आरक्षण का शिगूफा छोड़ देती है तो कभी अन्ना को बेईमान बताने लगती है. जानकार कहते हैं कि अन्ना के विरोध को इस तरह लेना चाहिए कि वह कांग्रेस नहीं, सरकार का विरोध कर रहे हैं. कांग्रेस का विरोध इसलिए है, क्योंकि उसकी सरकार है और उसके नेता दोमुंही बातें कर रहे हैं. कांग्रेसी भले कह रहे हों कि उन्हें अन्ना का डर नहीं सता रहा है, वह तो भाजपा और संघ के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हक़ीक़त यह है कि कांग्रेस डरी-सहमी है. कांग्रेस को पटकनी देने के लिए बसपा भी ना-ना करते हुए अन्ना के समर्थन में आ गई. उसने लोकपाल मुद्दे पर अपना स्टैंड बदल लिया. अन्य राजनीतिक दल भी अन्ना को लेकर असमंजस में हैं. वे यह नहीं सोच पा रहे हैं कि क्या किया जाए. अन्ना के आंदोलन को दलित विरोधी बताने वाली बसपा प्रमुख मायावती भले ही उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त को इतनी ताक़त नहीं देना चाहती कि मुख्यमंत्री उसके दायरे में आए, पर जब बात केंद्र की चलती है तो वह सशक्त लोकपाल बिल के लिए अन्ना का समर्थन करती नज़र आती हैं, प्रधानमंत्री को उसके दायरे में लाने के लिए कहती हैं.

चुनाव के बाद कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार बनाने का सपना देख रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव भले ही जन लोकपाल का विरोध करते हुए संसद में कहते हों कि दारोगा भी हमारा गिरेबान पकड़ कर जेल में डाल देगा, लेकिन वह कई बार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अन्ना का समर्थन कर चुके हैं. सपा की तरफ़ से रामगोपाल यादव अन्ना के मंच पर गए. भारतीय जनता पार्टी तो लगातार उनका समर्थन कर रही है. उसका मक़सद अन्ना के बहाने वोट बैंक मज़बूत करना है. अगर भाजपा केंद्र में सत्तारूढ़ होती तो उसका स्टैंड भी कांग्रेस से अलग न होता, ऐसी सोच रखने वालों की भी संख्या कम नहीं है. अन्ना जैसा समर्थन रामदेव को भले न मिल रहा हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनका आंदोलन कोई गुल नहीं खिला सका. रामदेव के समर्थकों की संख्या करोड़ों में है, जो मौक़ा पड़ने पर उनकी ताक़त बन सकते हैं. रामदेव कहते हैं, 2012 में जनक्रांति होगी, जिसकी कमान युवा वर्ग संभालेगा. बाबा अपने साथ जुटती भीड़ से गदगद हैं. वह मौक़ा देखकर बात करना भी सीख गए हैं. वह अन्ना और अपने आंदोलन में फ़र्क़ भी बताते हैं. उनका कहना है, अन्ना हजारे व्यवस्था परिवर्तन से भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि हमारा आंदोलन समूल नाश के लिए है. विदेशों में जमा काला धन वापस आ गया तो लोग अवैध कमाई और घोटाले करना भूल जाएंगे. दिल्ली के रामलीला मैदान में जैसा व्यवहार उनके साथ किया गया, उसकी टीस अभी भी उनकी बातों में झलकती है.

चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए कांग्रेस छोड़कर हर दल अन्ना और रामदेव के ख़िलाफ़ मुंह खोलने से बच रहा है. मायावती कहती हैं कि अगर सीबीआई को लोकपाल के दायरे में नहीं लाया गया तो बसपा समर्थन नहीं करेगी. मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि मज़बूत लोकपाल आना चाहिए, सरकारी लोकपाल कमज़ोर है. पार्टी प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि अन्ना केंद्र की तरह मायावती सरकार के भ्रष्टाचार को भी उजागर करें. प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक कहते हैं कि अच्छे और ईमानदार उम्मीदवारों को जिताने की अन्ना की मुहिम पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है. कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी कहती हैं, मुझे नहीं लगता कि अन्ना का असर विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा. अन्ना के आंदोलन में पर्दे के पीछे कोई और है. यह आंदोलन सोनिया और राहुल की छवि ख़राब करने के लिए चलाया जा रहा है.

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

feedback@chauthiduniya.com

बसपा केवल सरकारी खजाना लूटने का काम कर रही है. मायावती सरकार भ्रष्टों की जमात है. हर मंत्री किसी न किसी घोटाले या काले कारनामे में फंसा हुआ है.

बसपा का श्वेत पत्र झूठ का पुलिंदा है

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के क्षत्रप श्रीप्रकाश जायसवाल की अहम भूमिका है. केंद्रीय कोयला मंत्री जायसवाल का कद इसलिए भी ऊंचा कहा जा सकता है कि वह ऐसे समय में उत्तर प्रदेश से संसदीय चुनाव जीतकर पहुंचे, जब यहां कांग्रेस हाशिए पर थी. सोनिया और राहुल के लगातार दौरों और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद प्रदेश के कांग्रेसियों ने ताक़त लगानी शुरू कर दी. कांग्रेस के युवराज राहुल का मिशन यूपी पूरा करने के लिए प्रयासरत श्रीप्रकाश जायसवाल से *अजय कुमार* ने एक लंबी बातचीत की. पेश हैं मुख्य अंश:-

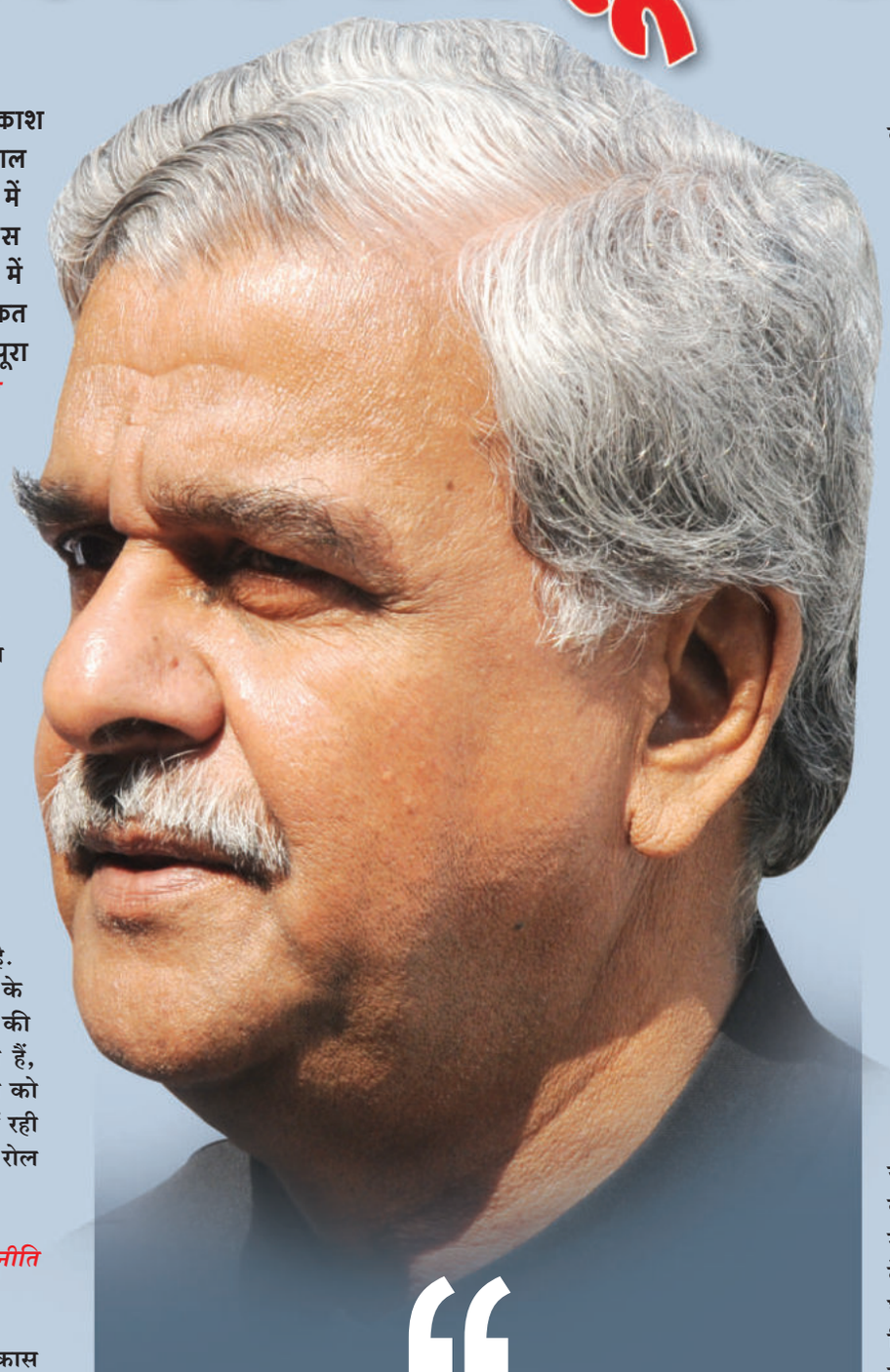

कोयला मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश के लिए आपकी क्या भूमिका रही?

भारत की कोयला खानों और उनके उत्पादन, खनन एवं ब्लॉकों को लेकर काफी जटिलताएं थीं, खानों पर दबंग ठेकेदारों का एकछत्र राज था, जिसे काफी हद तक दूर किया जा चुका है. उत्तर प्रदेश के लिए कोयले की कमी न होने पाए, इस पर पूरा ध्यान दिया गया. बाहर के देशों में भी कोयला खनन के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं.

चुनाव सिर पर हैं, अब तक आपका राजनीतिक कौशल कितना कारगर रहा है?

राहुल का मिशन पूरा करने के लिए हरसंभव कोशिश हो रही है. राहुल स्वयं कद्दावर नेता बन चुके हैं. उत्तर प्रदेश में उनके दौरों के दरम्यान जनता का रुझान अच्छा देखा जा रहा है. राजनीति करने की उनकी शैली अपने में एक है. वह गंभीर हैं, तीखा सच बोलते हैं, जिसके कारण दूसरे दल के लोग आहत हो उठते हैं, मगर कांग्रेस को इसकी कोई परवाह नहीं है, कांग्रेस पुरानी और सर्वजन की पार्टी रही है. दलितों एवं अल्पसंख्यकों को ऊपर उठाने में कांग्रेस का अहम रोल रहा है.

मुस्लिम राजनीति के संबंध में सपा और बसपा से निपटने की रणनीति क्या होगी?

सपा और बसपा की कार्यशैली से जनता आहत हो चुकी है. विकास के नाम पर दोनों दलों ने राजनीति के नाम पर अल्पसंख्यकों के वोट ही झटके, उनके लिए कोई ऐसी योजनाएं नहीं बनाईं, जिनसे उनका स्तर ऊंचा होता. कांग्रेस इस पर लगातार विचार करती चली आ रही है. संप्रदायवादी राजनीति ने प्रदेश के विकास का पहिया रोक दिया है. प्रदेश की इन सरकारों ने विकास के छठे पायदान बैठे प्रदेश को 21वें पायदान पर ढकेल दिया है, जनता इसे बर्दाश्त नहीं करने वाली. जहां अन्य राज्य विकास के शिखर पर पहुंच रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश सपा और बसपा के कारण आंसू बहा रहा है, जनता घुट-घुटकर जी रही है. हमारी नज़र सिर्फ़ उत्तर प्रदेश के विकास पर टिकी है. पिछले 20 सालों में उत्तर प्रदेश गर्त में चला गया है. किसानों को दो जून की रोटी मिलना दूभर है, रोज़गार के अवसर ख़त्म हो चुके हैं. मानचेस्टर कहलाने वाले कानपुर की मिलें बंद हो चुकी हैं. लाखों लोग बेरोज़गार होकर दर-दर भटक रहे हैं. केंद्र सरकार ग़रीबों के लिए योजनाएं बनाकर उत्तर प्रदेश को करोड़ों रुपये के पैकेज भेजती रही, लेकिन वह पैसा ग़रीबों तक नहीं पहुंच पाया, सब हाथी का निवाला बनता गया. कभी सपा की सरकार में बैठे मंत्रियों और अफसरों ने खाया तो आज बसपा के मंत्रियों के घर पैसा गिनने की मशीनें लग चुकी हैं. जनता आधा पेट खाकर सो रही है. अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी तो वह मनरेगा के एक-एक पैसे का हिसाब लेकर रहेगी और भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे.

“कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के मुस्लिमों के लिए काफी कुछ किया है. पिछली सरकार में भी उनके लिए कई योजनाएं बनाई गईं. उनकी स्थिति में काफी हद तक सुधार आया है, यह कांग्रेस की देन है. पार्टी मुस्लिमों के उत्थान के लिए प्रयास कर रही है. वह उनकी शिक्षा एवं रोज़गार के लिए कड़ी नज़र रखे हुए है. कांग्रेस हर वह उपाय खोज रही है, जिससे दबे-कुचले लोगों को दो जून की रोटी नसीब हो सके, रोज़गार मुहैया हो सके. मनरेगा के माध्यम से काफी पैसा मिला, लेकिन प्रदेश की बेईमान सरकार ने केंद्रीय पैकेजों और मनरेगा के तहत आने वाला पैसा लूट लिया.”

मुस्लिम आरक्षण की राजनीति चरम पर है, कांग्रेस की नीति क्या रहेगी?

कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के मुस्लिमों के लिए काफी कुछ किया है. पिछली सरकार में भी उनके लिए कई योजनाएं बनाई गईं. उनकी स्थिति में काफी हद तक सुधार आया है, यह कांग्रेस की देन है. पार्टी मुस्लिमों के उत्थान के लिए प्रयास कर रही है. वह उनकी शिक्षा एवं रोज़गार के लिए कड़ी नज़र रखे हुए है. कांग्रेस हर वह उपाय खोज रही है, जिससे दबे-कुचले लोगों को दो जून की रोटी नसीब हो सके, रोजगार मुहैया हो सके. मनरेगा के माध्यम से काफी पैसा मिला, लेकिन प्रदेश की बेईमान सरकार ने केंद्रीय पैकेजों और मनरेगा के तहत आने वाला पैसा लूट लिया. भ्रष्ट मंत्रियों की माला पहने बैठी सरकार को जनता समझ चुकी है. उत्तम प्रदेश का ढिंढोरा पीटने वाली बसपा ने प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय किया. जिस प्रदेश से प्रधानमंत्री बनकर जाते हों, उसे जातिवाद के कैंसर ने घेर लिया है. जाति के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है. सदन में अच्छे लोग चुनकर नहीं पहुंच पा रहे हैं. दबंगों और बाहुबलियों का सिक्का चल रहा है. 16 मिनट के सत्र में प्रदेश के चार टुकड़े करने का विधेयक पेश कर दिया गया, इससे यहां की हालत बख़ूबी समझी जा सकती है. चुनाव में बसपा का दंभ टूटेगा, जनता उसे सज़ा ज़रूर देगी.

राहुल भी मुसलमानों का दामन पकड़ रहे हैं, वह उनके घर और मस्जिदों में गए, इसके पीछे क्या रणनीति है?

यह राहुल का अपना नज़रिया है, वह हर कौम के उत्थान के लिए कई सालों से दर-दर भटक रहे हैं, उनमें चाहे दलित हों, किसान हों, मज़दूर हों या अन्य दबा-कुचला वर्ग, वह सभी को बराबर का दर्जा देते हैं. राहुल सिर्फ़ विकास के लिए ऐसे लोगों से मिलते हैं, उनके घर जाकर पूछते हैं कि उन्हें क्या तकलीफें हैं. केंद्र की ओर से उनके लिए जो पैसा भेजा जा रहा है, उसका लाभ उन्हें मिल पा रहा है या नहीं. यह तो स्वर्गीय राजीव गांधी का भी कहना था कि राज्यों को केंद्र की ओर से भेजे गए एक रुपये में से मात्र 15 पैसे ही जनता तक पहुंच पाते हैं. पिता के पदचिन्हों पर चलने वाले राहुल भी उन्हीं बातों पर अमल कर रहे हैं कि जनता को किस तरह पूरा लाभ मिल सके और बिचौलियों से पैसा कैसे बचाया जाए.

बसपा की सोशल इंजीनियरिंग के बारे में आपका क्या नज़रिया है, क्या उसने सभी जातियों के लिए बराबर का धर्म निभाया?

बिल्कुल नहीं. बसपा केवल सरकारी खजाना लूटने का काम कर रही है. मायावती सरकार भ्रष्टों की जमात है. हर मंत्री किसी न किसी घोटाले या काले कारनामे में फंसा हुआ है. कई जेल में हैं, दर्जनों लोकायुक्त की जांच के दायरे में आ चुके हैं. सोशल इंजीनियरिंग ने मुट्ठी भर ठाकुरों, ब्राह्मणों, वैश्यों एवं मुस्लिमों के परिवारों और उनके रिश्तेदारों को ही फ़ायदा पहुंचाया. जनता को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं. प्रताड़ित लोगों की एफआईआर नहीं लिखी जाती. वे मुख्यमंत्री, मानवाधिकार आयोग और राज्यपाल तक चिट्ठी भेजते हैं, पर उनकी सुनी नहीं जाती. ऐसी सरकार को जनता ही सबक सिखा सकती है और अब वह समय आ गया है.

प्रदेश की क़ानून व्यवस्था के बारे में आपका क्या कहना है?

मायावती ने सत्ता संभालते समय प्रदेश को अन्याय, अपराध, भय एवं भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प लिया था, हुआ उसका उलटा. लोगों की एफआईआर तक नहीं लिखी जा रही है. हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है, लूट-खसोट जारी है, विकास रुका हुआ है. यह जनता के साथ धोखा है. बसपा ने नौकरशाही को ख़रीद रखा है, मीडिया को दबा रखा है, कोई कुछ बोल नहीं सकता. नौकरशाह नख-दंत विहीन हैं. योग्य पदों पर अयोग्य लोग ठेकेदार बनकर बैठे हैं. शासन की हनक और निष्पक्षता ग़ायब हो चुकी है. प्रशासन जनता के प्रति अपने कर्तव्य, ज़िम्मेदारी और जवाबदेही भुला बैठा है. जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री अपनी एक अदद सैंडिल हवाई जहाज से मंगवाए, उसकी हालत क्या होगी, समझना मुश्किल नहीं है.

बसपा के श्वेत पत्र के बारे में आपकी राय?

वह श्वेत पत्र नहीं, काला चिट्ठा है, झूठ का पुलिंदा है.

feedback@chauthiduniya.com

मेरी दुनिया.... हॉर्स ट्रेडर का नया हुनर

आरक्षण के कारण अन्य पिछड़ी जातियों में शत्रुता का भाव पैदा होगा. मुलायम सिंह यादव का विरोध भी इसी तरफ़ इशारा करता है.

आरक्षण के नाम पर मुसलमानों से धोखा

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

डॉ. क़मर तबरेज़

देश के संविधान में कुछ वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, ताकि सामाजिक तौर पर पिछड़े लोगों को बराबरी के अधिकार दिए जा सकें, उन्हें भी अन्य नागरिकों की तरह तरक्की के अवसर मिल सकें, क्योंकि इतिहास गवाह है कि हमारे यहां जाति और धर्म के नाम पर विभिन्न वर्गों और धर्मों के लोगों के साथ अन्याय होता रहा है. आज़ादी के बाद जब देश में लोकतांत्रिक सरकार बनी तो सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात कही गई. इसके मद्देनज़र दलितों और आदिवासियों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई, लेकिन कुछ उन वर्गों की उपेक्षा कर दी गई, जिनके भारतीय होने पर जरा भी संदेह नहीं किया जा सकता. कांग्रेस ने मुसलमानों के बीच में एक ऐसा समूह पैदा कर दिया, जो जानता तो सब है, लेकिन आम मुसलमानों को वही बात बताता है, जिसका आदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ़ से आता है. मुसलमानों को गुमराह करने और उन्हें पिछड़ा बनाए रखने में इस समूह का बहुत बड़ा हाथ है. हाल में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने ओबीसी के लिए पहले से लागू 27 प्रतिशत आरक्षण के अंदर अल्पसंख्यकों को साढ़े चार प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की और उसे मंत्रिमंडल से मंज़ूर भी करा लिया. इसके बाद पूरे देश में ढिंढोरा पीटा गया कि कांग्रेस ने ओबीसी कोटे के अंदर मुसलमानों को साढ़े चार प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है. मुसलमान ख़ुशियां मनाने लगे, मुसलमानों के बड़े-बड़े नेता, पत्रकार एवं विद्वान कांग्रेस का आभार व्यक्त करने लगे. अख़बारों ने लिखा कि यह आरक्षण मुसलमानों के पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास है. वैसा ही हुआ, जैसा कांग्रेस चाहती थी. वह मुसलमानों को आरक्षण के नाम पर धोखा देने में एक बार फिर कामयाब हो गई.

आज भी उर्दू अख़बारों से जुड़े पत्रकारों को पता नहीं है कि यह आरक्षण सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि देश के सभी अल्पसंख्यकों के लिए है, क्योंकि ख़बरों में मुसलमानों को साढ़े चार फ़ीसदी आरक्षण जैसे वाक्य प्रकाशित हो रहे हैं. उर्दू पत्रकारिता पर अफ़सोस होता है, क्योंकि कांग्रेस ने एक झूठ बोला और उर्दू पत्रकारों ने उसे फैलाना शुरू कर दिया. यही नहीं, जामिया उर्दू अलीगढ़ में एक समारोह के दौरान न केवल कांग्रेस सरकार के इस फ़ैसले का स्वागत किया गया, बल्कि मिठाइयां भी बांटी गईं. वास्तविकता यह है कि कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों को अलग से कोई आरक्षण नहीं दिया है, बल्कि उनकी प्लेट से कुछ निवाले छीनने का प्रयास किया है. ओबीसी कोटे के तहत देश के सभी पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण पहले से मिल रहा है, लेकिन अब उस कोटे में से अल्पसंख्यकों के लिए केवल साढ़े चार प्रतिशत आरक्षण अलग कर दिया गया है. पहले मुसलमान 27 प्रतिशत के अंदर आरक्षण हासिल करने के लिए अन्य पिछड़ों से मुक़ाबला करता था. अब यह 27 प्रतिशत घटकर साढ़े बाईस प्रतिशत रह गया है. वहीं दूसरी तरफ साढ़े चार प्रतिशत कोटे में मुसलमानों के लिए सिखों, ईसाइयों, बौद्धों और जैनियों से मुक़ाबला करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुसलमान इस स्थिति में नहीं हैं कि वे अन्य अल्पसंख्यकों से मुक़ाबला कर सकें.

कांग्रेस मुसलमानों को ख़ुशहाल देखना ही नहीं चाहती. अगर आप सत्ता में आए हैं तो संविधान ने आपको जनहित में कोई भी निर्णय लेने से कभी नहीं रोका है. अगर यूपीए सरकार मुसलमानों के मुहल्ले में स्कूल खोलना चाहे तो क्या कोई उसे ऐसा करने से मना कर देगा? अगर वह सरकारी पैसे का इस्तेमाल बेघर और भूमिहीन लोगों के लिए मकानों का निर्माण कराने में करना चाहती है तो क्या कोई उसे रोक देगा? हरगिज़ नहीं.

दूसरी ओर आरक्षण के कारण अन्य पिछड़ी जातियों में शत्रुता का भाव पैदा होगा. मुलायम सिंह यादव का विरोध भी इसी तरफ़ इशारा करता है. कांग्रेस के इस फ़ैसले से भाजपा को भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ दूसरों को भड़काने का मौक़ा मिल गया है. रंगनाथ मिश्र कमीशन और जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद देश के मुसलमान यह आस लगा बैठे थे कि शायद अब सरकार उन पर मेहरबान होगी, उनका पिछड़ापन दूर करने का प्रयास करेगी, उनके लिए शिक्षा और रोज़गार की व्यवस्था करेगी, लेकिन केंद्र की कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने मुसलमानों के पिछड़ेपन का मज़ाक़ उड़ाया है और उन्हें मूर्ख बनाने की कोशिश की है. मुसलमानों की ओर से जितनी नाराज़गी ज़ाहिर की जाए, कम है. कांग्रेस ने ऐसा इसलिए किया है, क्योंकि कुछ ही दिनों में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. पिछले चुनाव के अनुभवों ने यह साबित कर दिया था कि मुसलमानों का वोट जिस पार्टी को मिलेगा, वही सत्ता में आएगी. इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव में मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए कांग्रेस ने आरक्षण की चाल चली है.

दरअसल, राजनीतिक पार्टियों ने मुसलमानों को अब तक सिर्फ़ वोट बैंक के तौर पर ही इस्तेमाल किया है. इससे ज़्यादा मुसलमानों की इस देश में और कोई हैसियत नहीं है. अगर मुसलमानों से वोट देने का उनका अधिकार छीन लिया जाए तो देश में उनकी हैसियत शून्य के अलावा कुछ नहीं रह जाएगी. जब चुनाव का समय आता है तो सबको मुसलमान याद आने लगते हैं, मदरसों का दौरा शुरू होने लगता है, उलेमा और मिल्ली संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाक़ात करने का सिलसिला शुरू हो जाता है, ताकि पर्दे के पीछे कुछ दे-दिलाकर उन्हें इस्तेमाल करते हुए उनसे अपने पक्ष में बयान दिलाए जा सकें. क्या एक कमरे के अंदर कुछ मुट्ठी भर मुसलमानों को ख़रीद कर पूरे देश के मुसलमानों की ग़रीबी और बदहाली को दूर किया जा सकता है? हरगिज़ नहीं. इस बार भी ऐसा ही हुआ. मुसलमानों के कुछ जाने-पहचाने चेहरे कांग्रेस द्वारा किए गए एहसानों को महसूस कराने में लगे हुए हैं. वे चाहते हैं कि एक झूठ को सौ बार बोला जाए तो वह सच साबित हो जाएगा, लेकिन उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि हम इक्कीसवीं सदी के भारत में जी रहे हैं. आज के मुसलमानों को मूर्ख बनाना उतना आसान नहीं है, जितना पहले हुआ करता था.

दरअसल, कांग्रेस मुसलमानों को ख़ुशहाल देखना ही नहीं चाहती. अगर आप सत्ता में आए हैं तो संविधान ने आपको जनहित में कोई भी निर्णय लेने से कभी नहीं रोका है. अगर यूपीए सरकार मुसलमानों के मुहल्ले में स्कूल खोलना चाहे तो क्या कोई उसे ऐसा करने से मना कर देगा? अगर वह सरकारी पैसे का इस्तेमाल बेघर और भूमिहीन लोगों के लिए मकानों का निर्माण कराने में करना चाहती है तो क्या कोई उसे रोक देगा? हरगिज़ नहीं. अगर वह मुसलमानों के मुहल्ले में नालियों की उचित व्यवस्था करना चाहती है, सड़कें बनवाना चाहती है तो उसके लिए अलग से क़ानून बनाने की क्या ज़रूरत है? संविधान ने धर्म के नाम पर आरक्षण देने के लिए मना किया है, लेकिन पिछड़ेपन के नाम पर आरक्षण देने के लिए हरगिज़ मना नहीं किया. देश के मुसलमान आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए हैं. कांग्रेस उन्हें पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण देने की बात क्यों नहीं कर रही है, उसमें अल्पसंख्यक या मुसलमान शब्द क्यों जोड़ा जा रहा है?

tabrez@chauthiduniya.com

भ्रष्टाचार पर सियासत

भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ अन्ना हजारे के आंदोलन को लेकर मुस्लिम संगठनों के रहनुमाओं ने सियासी रोटियां सेंकनी शुरू कर दी हैं. एक तरफ़ पूरा देश भ्रष्टाचार से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ़ कुछ मुस्लिम संगठनों ने अन्ना हज़ारे के आंदोलन का विरोध करने का ऐलान किया. इन संगठनों ने मुसलमानों से आह्वान किया है कि वे अन्ना हजारे के आंदोलन से दूर रहें. हालांकि अन्ना अब उन पांच राज्यों में कांग्रेस का विरोध करने की बात कह रहे हैं, जहां विधानसभा चुनाव होने हैं. मुस्लिम संगठनों को अन्ना के तरीक़े पर आपत्ति है. उनका कहना है कि अन्ना भ्रष्टाचार को लेकर सिर्फ़ कांग्रेस को ही निशाना बना रहे हैं, जबकि भाजपा शासित राज्यों में भी भ्रष्टाचार चरम पर है. कर्नाटक और उत्तराखंड की सरकारें इसकी ताज़ा मिसालें हैं.

जमीयत-ए-उलेमा हिंद की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष मौलाना मुस्तक़ीम हसन आज़मी का कहना है कि हम भी भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन अन्ना हजारे ने विरोध का जो तरीक़ा अपनाया है, उससे तो यही लगता है कि यह किसी साज़िश का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से बड़ा मुद्दा सांप्रदायिक दंगों और आतंकवाद का है, जो देश के सामने एक बड़ी चुनौती है. आज़ादी के बाद से अब तक सांप्रदायिक दंगों में हज़ारों मुसलमानों की जानें जा चुकी हैं. आतंकवाद के नाम पर बेक़सूर मुसलमानों को जेल की सलाख़ों के पीछे डाल दिया गया और यह सिलसिला बदस्तूर जारी है, लेकिन अन्ना हजारे ने इसके बारे में कभी एक शब्द नहीं कहा. संगठन के महासचिव मौलाना हलीमुल्ला क़ाज़मी का कहना है कि अन्ना हज़ारे के साथ जुड़े लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सांप्रदायिक ताक़तों के लिए काम कर रहे हैं. इससे सांप्रदायिक ताक़तों का ही भला होगा, इसलिए उन्होंने उनके आंदोलन से दूरी बना ली. देखा गया है कि जब भी धर्मनिरपेक्ष सरकारों के ख़िलाफ़ इस तरह के आंदोलन चले हैं तो सांप्रदायिक ताक़तें ही सत्ता में आई हैं.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव अब्दुल सत्तार शेख़ का कहना है कि अन्ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं. मुंबई अमन कमेटी के फ़रीद शेख़ ने अन्ना के आंदोलन की निंदा करते हुए कहा कि जब भी कोई धर्मनिरपेक्ष सरकार मुसलमानों की भलाई के लिए काम करना चाहती है तो भ्रष्टाचार के नाम पर उसे कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है. अन्ना भी यही कर रहे हैं. जाने-माने फिल्म निर्माता-निर्देशक महेश भट्ट भी इन मुस्लिम संगठनों के साथ खड़े नज़र आते हैं. उन्होंने तो यहां तक कह डाला कि अगर अन्ना की मुहिम कामयाब हो गई तो देश एक बार फिर विभाजन की कगार पर पहुंच जाएगा. उनका कहना था कि यह आंदोलन भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि यह तो देश को बांटने की एक साज़िश है. उन्होंने अन्ना की तुलना कश्मीर के अलगाववादी नेता गिलानी से कर डाली. ट्वीटर पर अपने संदेश में महेश भट्ट ने लिखा, अगर गिलानी जैसा कोई शख़्स कश्मीर को भारत से अलग करने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठ जाए तो क्या आप उसे उचित ठहराएंगे? ग़ौरतलब है कि सैयद अली शाह गिलानी कश्मीर में सक्रिय हुर्रियत कांफ्रेंस के कट्टरपंथी धड़े के नेता हैं और लंबे समय से कश्मीर को अलग करने की मांग करते रहे हैं. महेश भट्ट ने अन्ना हजारे को गांधीवादी मानने से भी इंकार करते हुए कहा कि भ्रष्ट सिर्फ़ वह नहीं है, जो रिश्वत लेता है, बल्कि भ्रष्ट वह भी है, जो सांप्रदायिक उन्माद को बढ़ावा देता है और धर्म के नाम पर लोगों से भेदभाव करता है.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव अब्दुल सत्तार शेख़ का कहना है कि अन्ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं. मुंबई अमन कमेटी के फ़रीद शेख़ ने अन्ना के आंदोलन की निंदा करते हुए कहा कि जब भी कोई धर्मनिरपेक्ष सरकार मुसलमानों की भलाई के लिए काम करना चाहती है तो भ्रष्टाचार के नाम पर उसे कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है. अन्ना भी यही कर रहे हैं. जाने-माने फिल्म निर्माता-निर्देशक महेश भट्ट भी इन मुस्लिम संगठनों के साथ खड़े नज़र आते हैं.

कई ऐसे संगठन भी हैं, जो बेशक खुलकर अन्ना के समर्थन में सामने नहीं आए हैं, लेकिन वे उनके ख़िलाफ़ भी नहीं हैं. जमीयत उलेमा-ए-हिंद के सचिव एवं प्रवक्ता अब्दुल हमीद नोमानी कहते हैं कि ऐतराज़ अन्ना के विरोध के तरीक़े पर हो सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नहीं. जमीयत भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि जनता से जुड़ा भ्रष्टाचार का यह मुद्दा अब सियासी रंग ले चुका है. हक़ीक़त तो यही है कि आज पूरा देश भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हुआ है. अब वे हालात नहीं रहे हैं कि जब कोई पार्टी या संगठन यह सोचे कि उसने कोई बात कह दी और लोग आंख मूंदकर उस पर अमल शुरू कर देंगे. जनता में जागरूकता बढ़ी है. लोग जानते हैं कि कौन उनके हित की बात कह रहा है और कौन उन्हें सब्ज़बाग़ दिखाकर गुमराह कर रहा है.

फ़िरदौस ख़ान
firdaus@chauthiduniya.com

ज़मीन रखने की ऊपरी सीमा क़ानून द्वारा निर्धारित कर दी गई, पर खेती-बाड़ी की ज़मीन के सिवाय अन्य मकान या जायदाद के संबंध में ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई.

महावीर प्रसाद आर मोरारका

पूंजी की निर्धारित सीमा

निजी संपत्ति पूंजीवाद का मूल स्तंभ है. इसे मिटाना ही होगा. इस श्रेणी में प्रधानत: दो ही संपत्तियों का समावेश होता है– (1) ज़मीन जायदाद, (2) पूंजी. भारत सरकार ने जबसे समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपना ध्येय घोषित किया है, प्रथम कक्षा के लिए कई संशोधन हुए हैं, नए क़ानून बने हैं. खेती-बाड़ी की ज़मीन एक व्यक्ति निर्धारित सीमा से ज़्यादा नहीं रख सकता. यह क़ानून अलग-अलग राज्यों में, प्राय: सारे भारत में ही बन गया है. जहां एक जमींदार के पास हज़ारों एकड़ भूमि होती थी, वहां आज क़ानूनन 30 या 50 एकड़ भूमि से ज़्यादा एक व्यक्ति या एक परिवार रख नहीं सकता. उसकी सारी अतिरिक्त भूमि कुछ मुआवज़ा देकर या बिना मुआवज़ा दिए उससे ले ली गई है या ली जा रही है. यह बड़ा भारी क्रांतिकारी परिवर्तन है. वे पूंजीवादी, जिनके पास सैकड़ों वर्षों से हज़ारों एकड़ भूमि क़ब्ज़े में चली आ रही थी, अब संत्रस्त हो रहे हैं. समान वित्त वितरण की दिशा में यह एक ठोस क़दम है.

ज़मीन रखने की ऊपरी सीमा क़ानून द्वारा निर्धारित कर दी गई, पर खेती-बाड़ी की ज़मीन के सिवाय अन्य मकान या जायदाद के संबंध में ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई. कोई भी एक व्यक्ति एक ही शहर में सैकड़ों मकानों का मालिक हो सकता है और मनचाहा भाड़ा जनता से वसूल कर सकता है. सौभाग्यवश शासन ने भाड़ा नियमन क़ानून बना रखा है. उसके प्रभाव से मकान मालिक स्वेच्छा से चाहे जिस हद तक भाड़ा नहीं बढ़ा सकते, पर फिर भी नए-नए मकानों में किराया बढ़ाने की जो अवधि है, वह अनुचित ढंग से ऊंची है. मकानों की क़ीमत भी काफी बढ़ी हुई है, अतएव जिस किसी जमींदार ने आज से 15 या 20 वर्ष पूर्व अपनी खेती-बाड़ी की ज़मीन बेचकर शहरों में मकान बनवा लिए या ख़रीद लिए, वे अपने आपको ज़्यादा बुद्धिमान और सौभाग्यशाली समझने लगे हैं. कारण स्पष्ट है कि इस बारे में सरकार की नीति अभी तक निश्चित नहीं हुई है. उसे समाजवादी व्यवस्था क़ायम करनी भी है और जैसा चलता है, वैसे चलने देना भी है. कृषि के लायक़ भूमि पर सीमा निर्धारित कर दी गई, पर पूंजी की कोई सीमा निश्चित नहीं हुई. कारण?

एक पूंजीपति के पास ज़्यादा ज़मीन होना ज़्यादा पूंजी के मुक़ाबले में ज़्यादा ख़तरनाक क्यों समझा गया? कारण, जमींदार, जागीरदार या राजा-महाराजा गिनती के थे. अत: इनका हक़ हड़प लेने या समाजवादी व्यवस्था को लागू करने के बहाने से आसानी से सारी ज़मीन हस्तगत कर ली गई. अगर पूंजी का राष्ट्रीयकरण हो या सीमा निर्धारित की जाए तो बहुत भारी जनसंख्या पर इसका असर पड़ेगा. प्रधानत: संसद, राज्यसभा के बहुत से सदस्यों पर भी असर पड़े बिना नहीं रहेगा. भारत इतना ज़्यादा ग़रीब देश है कि अगर ज़मीन की ऊपरी सीमा के अनुमान से ही पूंजी की सीमा निर्धारित की जाए तो ऊपरी सीमा लगभग 50 हज़ार रुपये की होगी. फिर क़ानून का यह रूप होगा कि कोई व्यक्ति अपने लिए या अपने परिवार के लिए 50 हज़ार से ज़्यादा न रख सके, बाक़ी पूंजी उसे राष्ट्र को दे देनी होगी. यह एक ऐसा क़दम है, जिसके लिए कठोर से कठोर समाजवादी भी तत्काल तैयार नहीं होगा, क्योंकि जहां तक ज़मीनें हस्तगत करने का सवाल था, इन पूंजीपतियों को व्यक्तिगत क्षति नहीं होती थी. जमींदारी उन्मूलन के अंतर्गत दिए गए मुआवज़े ने पूंजीपतियों की श्रेणी में वृद्धि ही की है. लिहाज़ा ज़मीन के एवज में प्राप्त धन का किराया जमींदारों को और अधिक मिल सकता है, कम से कम ऐसी आशा है. इसीलिए पूंजीपतियों के साथ इन विगत जमींदारों का बल भी पूंजी की सीमा निर्धारण में बाधक है.

जब पूंजी की सीमा निर्धारित करने का प्रश्न आता है तो आधी प्रजा, खासकर शिक्षित वर्ग नाराज़ होकर कहने लगेंगे कि यह तो सोवियत रूस का साम्यवाद है. बड़ा अत्याचार है, ऐसा नहीं होना चाहिए. समान वित्त वितरण में इसीलिए बाधा उत्पन्न हो रही है. मान लें, राष्ट्र ऐसा क़ानून बनाने को तैयार हो भी जाए, तो क्या वह सुचारू रूप से चल सकता है? क्या वह लागू हो सकेगा? क्यों नहीं, जहां हर व्यक्ति को आजकल अपनी संपूर्ण संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है, हर साल संपत्ति कर के आंकड़े भरकर भेजने पड़ते हैं, वहां कुल संपत्ति की ऊपरी सीमा क़ानून द्वारा आराम से बांधी जा सकती है. हां, प्रत्येक प्रगतिशील अच्छे क़ानून के लागू करने में शुरू-शुरू में जो बाधाएं आती हैं, इसमें भी आएंगी. लोग थोड़ा-बहुत धन चोरी-छिपे रख लेंगे, ऐसी संभावना हो सकती है. लेकिन जब जमा पूंजी एक निर्धारित सीमा से अधिक रखी नहीं जा सकती तो वह धन भी ख़र्च करना होगा. संपत्ति के इस सीमा निर्धारण का अर्थ यह नहीं है कि लोगों के कमाने की शक्ति के बारे में भी कोई लक्ष्मण रेखा खींच दी जाएगी. कमाने और व्यवसाय करने के क्षेत्र तो फिर भी खुले ही रहेंगे. इस सीमाबंदी का नतीजा तो यह होगा कि लोग उस जमा पूंजी को दबाकर मृत धन न होने देंगे. यदि कमाया हुआ धन ख़र्च होता गया, तो वह कई लोगों के हाथ से गुजरेगा और रुपये की इस गति से धन धीरे-धीरे अनेक भागों में बंटकर अनेक लोगों तक पहुंच जाएगा. रही वारिसदार के सौभाग्य और दुर्भाग्य की बात, सो उस बारे में भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं. राजस्थानी कहावत के अनुसार, पूत सपूत तो क्यों धन संचे, इन वारिसदारों के लिए भी सही मार्ग निर्धारित हो सकेगा.

जब निर्धारित सीमा से अधिक धन काम में लाया ही नहीं जा सकेगा तो निश्चय ही धन जमा करके गाड़ कर रखने की मनोवृत्ति भी समाप्त हो जाएगी. धन या संपत्ति का सबसे बड़ा दुरुपयोग उसको जमा रखना है. अगर किसी व्यक्ति के पास धन है और वह काम में आता है तो भले ही असमान वित्त वितरण रहे, पर राष्ट्र के लिए वह पूंजी कुछ न कुछ कार्य तो करती रहेगी. एक न एक दिन जब राष्ट्र की इच्छा होगी, उसका राष्ट्रीयकरण हो ही जाएगा. पर जो व्यक्ति सोना-चांदी जवाहरात इकट्ठे करके भूमि में गाड़ कर रखते हैं या अपार धन संपत्ति के खजाने भरकर रखते हैं, वे सही मायने में देश के बड़े शत्रु हैं. क़ानून द्वारा सोना-चांदी, जवाहरात या अन्य बहुमूल्य धातु या चीजें भरकर रखना अपराध घोषित हो जाना चाहिए. भारत में जितनी दरिद्रता है, उसे देखते हुए लोग सोना- चांदी या जवाहरात भरकर रखें, यह अशोभनीय है. निजी संपत्ति का एक अंग यानी ज़मीन की मालिकी धीरे-धीरे या एक झटके के साथ समाप्त की जा रही है या मिट चुकी है. दूसरे अंग यानी पूंजी को मिटाने का एकमात्र प्रयत्न सीधे करों द्वारा ही है, जिनका उपयोग अभी तक सही ढंग से नहीं हो पाया है. पूंजी को भी एक झटके के साथ समान स्तर पर लाया जा सकता है. वैसा करने में शायद बहुत कम लोगों को दर्द हो.

आदमी को सबसे बड़ा दर्द है प्रतिस्पर्धा की वजह से. अगर किसी के पास दोनों वक्त पेट भर खाने को भी न हो और उसे निश्चय ही यह मालूम हो कि दूसरे किसी व्यक्ति के पास भी पेट भर खाने को नहीं है तो वह उतना दु:खी कदापि नहीं होगा, जितना दु:खी एक लखपति अपने पड़ोसी को करोड़पति देखकर होता है. मानव की पशुवृत्ति प्रतिस्पर्धात्मक है, इसलिए वह समदु:खी के साथ राहत अनुभव करता है. जहां उसे उन्नतिशील या समृद्ध व्यक्ति मिले तो अपने को हीन समझ कर वह तत्काल दु:खी हो जाता है. यदि यहां ऐसा नियम बना दिया जाए कि कोई भी व्यक्ति 50 हज़ार से ज़्यादा संपत्ति नहीं रख सकेगा, तो एक लाख वालों को या कम-ज़्यादा वालों को, किसी को भी इतना क्षोभ नहीं होगा, जितना असमान वित्त वितरण से हो रहा है. तात्पर्य यही है कि सब अपना-अपना छोड़ने को तत्पर हो सकते हैं, बशर्ते कि किसी भी दूसरे के पास उनसे ज़्यादा न छोड़ा जाए. इन सब अतिरिक्त करों की अंतिम परिणति समान वित्त वितरण है. यह उद्देश्य जरा भी सफल होता दृष्टिगोचर होता तो वे लोग भी, जिनको कर देने पड़ रहे हैं, संभवत: इतने असंतुष्ट नहीं होते. उनके असंतोष का मूल कारण यही सोच है कि हमसे करों के रूप में भारी रकमें ली जा रही हैं और सीधे या टेढ़े मार्ग से भारी से भारी पूंजी सरकारी नौकरों या कर्मचारियों के यहां इकट्ठी हो रही है और आज के पूंजीपति या उद्योगपति हम हैं, कल हमारी जगह ये होने वाले हैं. इसी ईर्ष्या या द्वेष के वशीभूत होकर भारत का तथाकथित पूंजीवादी यदि समाजवाद का दिल से हिमायती हो, तो भी विरोध ही करेगा. क़ानून ऐसे बने हुए हैं कि बनाने के पूर्व ही उनके उल्लंघन के मार्ग खुले छोड़ दिए जाते हैं. आज भारत में ज़्यादा से ज़्यादा काबिल वही वकील-बैरिस्टर समझा जाता है, जो क़ानून उल्लंघन करने का सरल से सरल मार्ग बता सके. आयकर का भूत इतना भयावह हो गया है कि क्या वकील, क्या डॉक्टर, क्या अन्य आदरणीय पेशे वाले, सभी बिना उचित रिकॉर्ड के अपनी फी के बदले में ब्लैक की रकम नि:संकोच लेना चाहते हैं. अच्छे-अच्छे महानुभाव यह शर्त रख देते हैं. जहां क़ानून के रक्षकों का यह हाल है, वहां देश का उत्थान या प्रगति हो भी तो कैसे? इस सारी कुबुद्धि की जड़ वही असमान वित्त वितरण है. एक बार समान वित्त वितरण संभव हो जाए और समाजवादी अर्थव्यवस्था सही अर्थ में लागू हो जाए तो न रुपये लेने का ही आकर्षण रहेगा, न क़ानून ही भंग होंगे.

feedback@chauthiduniya.com

महावीर प्रसाद आर मोरारका का जन्म 12 अगस्त, 1919 को नवलगढ़ (झुंझनू) राजस्थान में हुआ था. उद्योगपति, स्वप्नदृष्टा और लेखक से कहीं अधिक वह उदात्त मानवीय मूल्यों के संवाहक थे. उनकी गणना भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में की जाती है.

सौमित्र मोहन

बालश्रम ख़त्म किया जा सकता है

भारत में 14 साल तक के बच्चों की आबादी पूरी अमेरिकी आबादी से भी ज़्यादा है. कुल श्रम शक्ति का लगभग 3.6 फ़ीसदी हिस्सा 14 साल से कम उम्र के बच्चों का है. प्रत्येक दस बच्चों में से 9 काम करते हैं. ये बच्चे लगभग 85 फ़ीसदी पारंपरिक कृषि गतिविधियों में कार्यरत हैं, जबकि 9 फ़ीसदी से कम उत्पादन, सेवा और मरम्मती कार्यों में लगे हैं. सिर्फ़ 0.8 फ़ीसदी कारखानों में काम करते हैं. आम तौर पर बाल मज़दूरी अविकसित देशों में व्याप्त विभिन्न समस्याओं का नतीजा है. केंद्र सरकार राज्यों के सहयोग से बाल मज़दूरी ख़त्म करने की दिशा में तेज़ी से प्रयासरत है. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना (एनसीएलपी) जैसे महत्वपूर्ण क़दम उठाए हैं. इस परियोजना ने कई अहम कार्य किए. हज़ारों बच्चों को सुरक्षित बचाया, विशेष स्कूलों में उनका पुनर्वास किया. वहां पाठ्यक्रम ऐसे होते हैं कि इन बच्चों को मुख्य धारा के विद्यालयों में प्रवेश लेने में किसी तरह की परेशानी न हो. विशेष विद्यालयों में न सिर्फ़ बुनियादी शिक्षा दी जाती हैं, बल्कि बच्चों की रुचि के मुताबिक़ व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है. इस परियोजना के तहत बच्चों के लिए नियमित भोजन, चिकित्सकीय सहायता और एक सौ रुपये मासिक वजीफ़े की व्यवस्था है. इन प्रयासों से अब तक हज़ारों बच्चे मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं, फिर भी यह समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है. लाखों बच्चे अभी भी बाल मजदूरी कर रहे हैं. इस परियोजना से इतनी जागरूकता तो आई है कि अब हर कोई जानने लगा है कि 14 साल तक के बच्चों से काम कराना एक अपराध है, लेकिन इसकी जांच-पड़ताल का कोई उपाय नहीं है. ऐसे बच्चे न तो स्कूल जाते हैं और न इनके जन्म का कोई प्रामाणिक रिकॉर्ड होता है. इसीलिए ये कहीं से भी अपने जन्म प्रमाणपत्र का इंतज़ाम कर लेते हैं और लोगों को उसे मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता.

लोगों को भी लगता है कि बच्चों को काम करने की छूट देने या कारखानों में उनके काम करने पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि माता-पिता द्वारा काम पर लगाए जाने वाले बच्चों की तादाद काफ़ी अधिक है. इन बच्चों को छोटी उम्र में ही काम पर लगा दिया जाता है, जिससे इन पर नकारात्मक असर पड़ता है. असल में इन विशिष्ट स्कूलों में दिए जाने वाले व्यवसायिक प्रशिक्षणों में भी कुछ ख़ामियां हैं. इसके लिए धन का अलग से आवंटन नहीं होता, जिसके कारण इसे चलाने में कई मुश्किलें आती हैं. बाल मज़दूरी ख़त्म करने और व्यवसायिक प्रशिक्षण का लक्ष्य हासिल करने के लिए सबसे पहले उक्त पहलुओं को समझना बेहद ज़रूरी है. व्यवसायिक प्रशिक्षण के दौरान उत्पादित सामानों का विपणन और प्रचार यदि ठीक ढंग से हो तो उसकी लागत पर आने वाले ख़र्च को हासिल किया जा सकता है. वैसे तो बालश्रम अधिनियम (निषेध एवं विनियमन) बन चुका है, लेकिन अभी उसे ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया है. बालश्रम को बढ़ावा देने वाले लोग समाज के ग़रीब तबके से आते हैं, इसलिए उन्हें हिरासत में लेने या दंडित करने के प्रति भी हमारी कोई रुचि नहीं दिखती. जहां लोग बाल मज़दूरी से परिचित होते हैं, वे इस अपराध से बच निकलने में सफल हो जाते हैं. जिन बाल मज़दूरों को मुक्त कराया जाता है, उनका पुनर्वास समय पर नहीं हो पाता, नतीजतन वे फिर उसी दलदल में फंस जाते हैं.

ऐसे में इसके ख़िलाफ़ कड़े क़दम उठाने की आवश्यकता है. पुनर्वास के लिए दी जाने वाली बीस हज़ार रुपये की धनराशि बढ़ाई जाए, बेहतर पुनर्वास का ख़ाका बनाया जाए और विशेष स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाए. बालश्रम से निपटने की दिशा में न सिर्फ़ नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है, बल्कि इसके लिए लागू विभिन्न परियोजनाओं को वित्तीय सहायता आवंटित करने की जाए.

(लेखक आईएएस अधिकारी हैं, इस आलेख में व्यक्त विचार उनके अपने हैं, जिनका सरकार से कोई संबंध नहीं है.)

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

सर्वश्रेष्ठ पत्र

अंग्रेजी में संबोधन क्यों?

आज़ादी के क़रीब 65 साल बाद भी देश के शासक वर्ग में अंग्रेजी का वर्चस्व क़ायम है, जबकि यहां अंग्रेजी जानने-समझने वालों की संख्या दो प्रतिशत से अधिक नहीं है. राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा देश-विदेश में अधिकांश संबोधन अंग्रेजी में ही किए जाते हैं. नेता वोट मांगते समय तो हिंदी बोलते हैं, लेकिन बाद में अंग्रेजी में बात करते हैं. हिंदी का इस्तेमाल न करना क्या राष्ट्रभाषा और लोकशाही का अपमान नहीं है? रूस, जर्मनी, जापान और चीन ने अपनी भाषा को अपना कर ही उन्नति की है.

शिवकुमार फ़ैजाबादी, फ़ैजाबाद, उत्तर प्रदेश.

गौ हत्या पर गहन विश्लेषण

चौथी दुनिया में प्रकाशित आलेख-कब लगेगा गौ हत्या पर प्रतिबंध पढ़ा. लेखिका ने बहुत ही नाज़ुक विषय पर सही विश्लेषण किया है. उन्होंने इस लेख में इतिहास के उन बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला है, जिनमें बताया गया है कि मुस्लिम शासकों ने सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए गौ हत्या पर रोक लगा रखी थी. मुस्लिम शासकों के बाद जब देश में अंग्रेजों का शासन आया तो उन्होंने अपनी ज़रूरत के लिए गाय और सुअर के मांस का प्रचलन शुरू किया. ऐसा करके उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों में कटुता पैदा करने का प्रयास किया. साथ ही उन्हें इन पशुओं के मांस से आमदनी भी होने लगी. हमारे देश में गौ हत्या में मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू शामिल हैं. वे धन कमाने के लिए ऐसा करते हैं. सरकार को गौ हत्या पर सख्ती से रोक लगानी चाहिए.

-शंकर शर्मा, *बेगूसराय, बिहार.*

नीयत साफ़ नहीं

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजनीतिक दलों की नीयत साफ़ नहीं है. मसलन भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यूपीए की केंद्र सरकार को तो पानी पी-पीकर कोसते नज़र आते हैं, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर उन्हें सांप सूंघ जाता है. नेताओं को समझना चाहिए कि जनता मूर्ख नहीं है. वह सब जानती है कि कौन कितना भ्रष्टाचारी है.

-हिमांशु, *दिल्ली.*

पहले संविधान का अध्ययन कीजिए

विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने मुस्लिमों को आरक्षण देने के संबंध में धर्म के आधार पर ऐतराज़ जताया. लगता है, उन्होंने भारतीय संविधान का अध्ययन नहीं किया है. उन्हें मालूम होना चाहिए कि भारतीय संविधान की धारा 341 के अंतर्गत नियम 1950 में एसटी और एससी को जो आरक्षण दिया गया है, वह धर्म के आधार पर नहीं है तो और क्या है?

-मो. रफ़ीक़ चौहान, *ई-मेल से.*

मैं अन्ना हूं

मैं अन्ना हूं
मैं भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ हूं
मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई
की ग़रीबी की आवाज़ हूं
स्विस बैंक में बंद
मैं देश का हिसाब हूं
हां, मैं राष्ट्रवाद हूं
मैं ग्रामीण भी हूं
मैं शहरी भी हूं
मैं राष्ट्र का प्रहरी भी हूं
जनचेतना का शंखनाद हूं
हां, मैं राष्ट्रवाद हूं
मैं शिवाजी हूं, मैं राणा प्रताप हूं
मैं हैदर हूं, मैं टीपू हूं
इस मिट्टी से निकला
इस मिट्टी के लिए मर गया
हां, मैं राष्ट्रवाद हूं
मैं जहीर हूं, मैं कलाम हूं
मैं बिस्मिल्लाह, अब्दुल हमीद
मंच पर बैठे आमिर की गुहार हूं
जो बच गए वे इक़बाल हैं
अब उनके लिए काल हूं,
हां, मैं राष्ट्रवाद हूं

-रश्वेत श्रिंखल, *जेएनयू, नई दिल्ली.*

मिलावट का काला कारोबार

बिहार सहित देश के अमूमन सभी राज्यों में मिलावट का काला कारोबार चल रहा है. स्थिति यह है कि खाद्य पदार्थों, खाद, कीटनाशक और दवाओं में मिलावट देखने को मिल रही है. जनता मिलावटी वस्तुएं ख़रीदने के लिए मजबूर है. मुनाफ़ा बटोरने की प्रवृत्ति के कारण मानवीय संवेदना शून्य होती जा रही है. आकर्षक पैकिंग में घटिया सामान बेचा जा रहा है. जब तक सरकारें मिलावटख़ोरी को रोकने के लिए सख्ती नहीं बरतेंगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं है.

-प्रताप नारायण सिंह, *बेगूसराय, बिहार.*

राजकमल प्रकाशन समूह

चौथी दुनिया में प्रकाशित सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को राजकमल प्रकाशन की ओर से 700 रुपए की किताबें दी जाएंगी.

राजकमल प्रकाशन की किसी भी पुस्तक की समीक्षा चौथी दुनिया को भेजें. हर महीने की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा को 1100 रुपए की पुस्तकें दी जाएंगी.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें:

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

जन लोकपाल बिल के साथ-साथ सरकारी बिल पर बहस की जा चुकी है. संसद की स्थायी समिति ने इसे देखा है.

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

देश का विश्वास टूटने मत दीजिए

वर्ष 2009 में एक बड़ी घटना हुई. चौथी दुनिया ने रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट छाप दी और सरकार से कहा कि अगर यह रिपोर्ट झूठी है तो वह कहे कि यह रिपोर्ट झूठी है. उस रिपोर्ट को लेकर राज्यसभा में चार-पांच दिनों तक काफ़ी हंगामा होता रहा. राज्यसभा के सांसदों ने हमारे ख़िलाफ़ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखा और हमने उस विशेषाधिकार हनन के नोटिस का जवाब भी दिया. एक तरफ़ राज्यसभा ने हमारे ख़िलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखा, वहीं दूसरी तरफ अगले ही दिन लोकसभा में 20 से ज़्यादा सांसद चौथी दुनिया हाथ में लेकर खड़े हो गए और उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव डाला और कहा कि हम यह सदन नहीं चलने देंगे, अगर रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट सदन में रखने का आश्वासन आप अभी नहीं देते हैं तो. प्रधानमंत्री को वह आश्वासन देना पड़ा और रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट सदन में रखी गई. यह रिपोर्ट सरकार दो साल से संसद के किसी भी सदन में रखने से बच रही थी. हमने उस समय राज्यसभा के सदस्यों से कहा था कि आप सही तरीक़े से कोई भी बात क्यों नहीं उसकी तार्किक परिणति तक पहुंचा पाते हैं? इसमें हमने राज्यसभा के सदस्यों से कुछ तीखी बातें भी कही थीं.

हमारे मन में उस समय एक सवाल उठा था. राज्यसभा की परिकल्पना एक ऐसे सदन के रूप में की गई है, जो लोकसभा द्वारा की गई ग़लतियों को सुधारेगा और देश को बताएगा कि दरअसल क्या होना चाहिए. राज्यसभा का इस्तेमाल देश के बुद्धिजीवियों, समझदार लोगों और उनके लिए होगा, जो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन जिनका बहुत ज़्यादा वक्त देश के लिए सोचने और समझने में निकल जाता है. अब राज्यसभा में क्या हो रहा है, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कहते. किस तरह सदस्य आते हैं, यह भी हम नहीं कहते, लेकिन लोकपाल विधेयक पर हुई बहस ने बहुत सारी चीजें देश के लोगों के सामने साफ़ कीं. शिवानंद तिवारी ने राज्यसभा में बहस के दौरान कहा कि अब राज्यसभा में किस-किस तरह के लोग आते हैं. उनका इशारा था कि राज्यसभा में लोग पैसे के बल पर आ जाते हैं. उन्होंने धनपति या पैसे वाला शब्द का इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा कि ऐसे लोग आ जाते हैं, जिनके आने से राज्यसभा की गरिमा कम होती है. राज्यसभा में पार्टियां ऐसे लोगों को भी भेज देती हैं, जिन्हें वे कहीं एडजस्ट नहीं कर पातीं. राज्यसभा में ऐसे लोग भी आ जाते हैं, जो कभी लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सकते.

इस बार तो राज्यसभा ने एक इतिहास ही बना दिया. राज्यसभा का एक सदस्य प्रधानमंत्री है, जिसने प्रधानमंत्री होने के बाद लोकसभा का चुनाव लड़ा ही नहीं और उसके पहले जब लोकसभा का चुनाव लड़ा तो हार गया. इंदिरा जी के समय तक, बल्कि कहें कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय तक आम तौर पर यह माना जाता था कि आप प्रधानमंत्री भले ही राज्यसभा का सदस्य होते हुए बन जाएं, लेकिन आपको सीधे चुनाव में यानी लोकसभा का चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री के पद पर अपनी दावेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए. लेकिन मनमोहन सिंह ने न कभी चुनाव लड़ने के बारे में सोचा और न कांग्रेस पार्टी ने उनसे कहा कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ें और नैतिक रूप से प्रधानमंत्री पद पर अपनी दावेदारी सुनिश्चित करें. एक हर्ष की बात है कि राहुल गांधी राज्यसभा में आ सकते थे, लेकिन वह नहीं आए. उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और उसके सदस्य बने. सोनिया गांधी भी राज्यसभा में आ सकती थीं, लेकिन वह राज्यसभा में नहीं आईं, लोकसभा की सदस्य बनीं. लेकिन क्यों मनमोहन सिंह को चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी या सोनिया गांधी ने आज तक नहीं कहा, यह रहस्य की बात है. राज्यसभा धीरे-धीरे अपना महत्व खोती जा रही है. राज्यसभा के सदस्यों, जिनमें पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल हैं, राज्यसभा चलाने वाले पीठासीन अधिकारी, उप सभापति और अंत में सभापति के आचरण से भी राज्यसभा की गरिमा घटती और बढ़ती है.

लोकपाल पर बहस के दौरान हमने देखा कि जहां बहुत सारे सदस्यों ने तार्किक बातें रखीं, वहीं कई सदस्यों ने अतार्किक बातें भी रखीं. सत्तारूढ़ दल ने राज्यसभा का इस्तेमाल कुछ इस तरह किया, मानों वह भ्रष्टाचार के समर्थन में खड़ा है. भ्रष्टाचार ख़त्म होगा या नहीं, यह अलग चीज है. शायद इसका फ़ैसला देश के लोग करेंगे और जब वे ख़ुद अपनी मानसिकता बना लेंगे कि उन्हें भ्रष्टाचार सहन नहीं करना है तो वे ऐसे लोगों को चुनकर भेजेंगे, जो उनकी इस आकांक्षा को पूरा करें. पर अभी तो राज्यसभा के सदस्य सामूहिक तौर पर भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ते नहीं दिखे. कांग्रेस पार्टी का एक रुख़, भारतीय जनता पार्टी का दूसरा रुख़ और छोटी-छोटी पार्टियों का तीसरा रुख़. क्या कहें, यह मानने का दिल नहीं करता कि राज्यसभा के सदस्य अक्ल में कम हैं या समझदारी में कम हैं. तो फिर यही मानने का मन करता है कि राज्यसभा के सदस्य और सभापति, सबने एक ही फ़ैसला कर लिया था कि लोकपाल बिल के ऊपर सार्थक बहस नहीं होनी है और राज्यसभा भ्रष्टाचार से सीधे-सीधे लड़ती नहीं दिखाई देनी है. एक और महत्वपूर्ण बात है. जब राज्यसभा में कोई सदस्य पहुंचता है तो पहले आम तौर पर यह माना जाता था कि वह सिर्फ़ अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि एक ऐसी सभा का सदस्य हुआ है, जो पूरे देश के बारे में विचार करती है और वहां पहुंचने वाले सदस्य विभिन्न पार्टियों से आते हैं, लेकिन नक्शा उनके सामने पूरे देश का होता है. राज्यसभा के बारे में तो यह अवधारणा बहुत दिनों तक रही कि यहां आने वाले लोग अपनी पार्टी की क्षुद्र लाइन से प्रभावित नहीं होते, बल्कि देश को सामने रखकर बहस करते हैं, बात करते हैं, सलाह देते हैं. इसके उदाहरण राज्यसभा के इतिहास में भरे पड़े हैं.

देश के लोग अपेक्षा तो कर रहे थे, लेकिन सभी जानते थे कि जैसे ही घड़ी की सुइयां बारह का अंक पार करेंगी, यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा. राजनीति प्रसाद, जो आरजेडी के राज्यसभा सदस्य हैं, वह काग़ज़ सदन में फाड़कर फेकेंगे, यह बात एक चैनल पहले ही बता चुका था. ये सारी सूचनाएं कौन दे रहा था? स्वयं राज्यसभा के लोग. अफ़सोस इस बात का है कि पहली बार हमें संसद देश को दर्द देने वाले सवाल यानी भ्रष्टाचार से लड़ती नज़र नहीं आई.

भूपेश गुप्ता साहब के बयान, राजनारायण जी के भाषण, सबसे महत्वपूर्ण कांग्रेस पार्टी में रहते हुए चंद्रशेखर जी द्वारा देश के सबसे बड़े पूंजीपति घराने के ख़िलाफ़ चलाया गया अभियान राज्यसभा के इतिहास के स्वर्णिम पन्ने हैं. जब हम राज्यसभा की पुरानी बहसें देखते हैं तो ऐसे सदस्य हमें कम नज़र आते हैं, जो पार्टी लाइन के ऊपर राज्यसभा को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते रहे हों, बल्कि ज़्यादातर ऐसे लोग मिलते हैं, जो राज्यसभा को बहुत गंभीरता से चलाने की कोशिश करते रहे हैं. पर लोकपाल बिल पर बहस के दौरान जिस तरीके का व्यवहार राज्यसभा के सदस्यों ने किया. केवल व्यवहार ही नहीं किया, बल्कि क्या व्यवहार करने जा रहे हैं, इसकी जानकारी भी वे पत्रकारों को देते रहे. एक टीवी चैनल तो बार-बार एसएमएस दिखाता रहा और कहता रहा कि अब राज्यसभा में यह होने वाला है और वही हुआ. अपने प्रचार के लोभ में कई सांसदों ने राज्यसभा की गरिमा का भी ख्याल नहीं रखा. आख़िर में हद तब हो गई, जब राज्यसभा के सभापति माननीय हामिद अंसारी साहब ने यह इच्छा नहीं दिखाई कि इस बहस का कोई तार्किक परिणाम निकले. पूरा देश देख रहा था और हर आदमी अपेक्षा कर रहा था कि हामिद अंसारी साहब राज्यसभा को तब तक चलाएंगे, जब तक इस बहस की तार्किक परिणति वोट में न दिखाई दे, लेकिन हामिद साहब ने एक थोड़े से शोरगुल का आधार लेकर राज्यसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया. राज्यसभा के बहुत सारे लोग यह कह रहे थे कि हम सारी रात बैठने के लिए तैयार हैं, पर उनके ऊपर सभापति महोदय ने कोई ध्यान नहीं दिया.

देश के लोग अपेक्षा तो कर रहे थे, लेकिन सभी जानते थे कि जैसे ही घड़ी की सुइयां बारह का अंक पार करेंगी, यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा. राजनीति प्रसाद, जो आरजेडी के राज्यसभा सदस्य हैं, वह काग़ज़ सदन में फाड़कर फेकेंगे, यह बात एक चैनल पहले ही बता चुका था. ये सारी सूचनाएं कौन दे रहा था? स्वयं राज्यसभा के लोग. अफ़सोस इस बात का है कि पहली बार हमें संसद देश को दर्द देने वाले सवाल यानी भ्रष्टाचार से लड़ती नज़र नहीं आई. संसद बहुत सारी चीजों से लड़ती नज़र नहीं आती है, लेकिन कम से कम नाटक ज़रूर करती है, दिखाती है कि उसे चिंता है. लेकिन अब वह पर्दा भी राज्यसभा ने हटाने की कोशिश की. अलग-अलग भाषण सबके अच्छे थे. अरुण जेटली ने अच्छा भाषण दिया, सीताराम येचुरी ने अच्छा भाषण दिया, शिवानंद तिवारी ने अच्छा भाषण दिया, अभिषेक मनु सिंघवी ने अच्छा भाषण दिया, राम जेठमलानी ने अच्छा भाषण दिया, लेकिन अगर पूरी तस्वीर को देखें तो पाएंगे कि सारे भाषण मिलकर कोई एक दिशा तय नहीं करते. मेरे जैसे लोगों को, जो राज्यसभा से बहुत अपेक्षा करते हैं, लोकपाल बिल पर हुई बहस देखकर बहुत निराशा हुई. देश में बहुतों को निराशा हुई. एक अपील करना चाहते हैं राज्यसभा के सदस्यों और सभापति से कि आप अपने भीतर अगर लोकसभा से ज़्यादा गंभीरता ला सकते हैं तो ले आइए और देश के लोगों के मन में इस विश्वास को मत टूटने दीजिए कि आप उन समझदार लोगों में से हैं, जिनके ऊपर देश का भरोसा है. आप ऐसे लोग हैं, जो अगर कुछ न कर सकें, लेकिन ग़लत बात के ख़िलाफ़ अपना हाथ ज़रूर खड़ा कर सकते हैं. आशा है, हमारा भरोसा आप कायम रखेंगे.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

अन्ना और लोकपाल

पिछले अप्रैल महीने से सिविल सोसाइटी की एक टीम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आंदोलन कर रही है. संसद में भी इस आंदोलन के पक्ष-विपक्ष में बहस हो रही है. सरकार की परेशानी बढ़ गई है. यह एक अलग तरह का आंदोलन है. यह जाति, धर्म एवं क्षेत्र आदि के आधार पर किए जाने वाले आंदोलनों से भिन्न है. यह आंदोलन सारे भारत में हो रहा है, जबकि जाति, धर्म एवं क्षेत्र आदि के मुद्दों पर होने वाले आंदोलन किसी एक क्षेत्र विशेष तक सीमित रहते हैं, जिन्हें दबाना सरकार के लिए बड़ी बात नहीं होती है. अन्ना हजारे का आंदोलन केवल भ्रष्टाचार के विरुद्ध नहीं है, बल्कि यह एक क़ानून यानी लोकपाल बिल का हिस्सा है, जो कि साठ के दशक से लटका हुआ है. संसद के पास समय की कमी के कारण इसे पारित नहीं किया जा सका, लेकिन इस बार संसद के पास समय की कमी नहीं है. इसलिए कोई बहाना नहीं बनाया जा सकता. यह आंदोलन एक तरह से लोकतंत्र का विस्तार है. इस आंदोलन के माध्यम से संसद के क़ानून बनाने के एकाधिकार में हस्तक्षेप किया जा रहा है. इसे लोकतंत्र के क्षेत्र का बढ़ना ही कहा जा सकता है. वैसे अन्ना हजारे को कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं. मैं भी संत या अध्यात्म से जुड़े लोगों पर विश्वास नहीं करता हूं. ये लोग दबंग और असहिष्णु होते हैं. इनकी अनशन करने की लालसा भी उबाऊ है. यह एक ऐसा हथियार है, जो अपना असर खोता जा रहा है, लेकिन फिर भी इसे होने दो.

एक तरफ़ आम आदमी को 32 रुपये प्रतिदिन पर जीवित रहने की बात की जाती है तो दूसरी तरफ़ एक सांसद को लाखों रुपये दिए जाते हैं. चुनाव में भी ये सांसद करोड़ों रुपये ख़र्च करते हैं, जिसमें काले धन का हिस्सा भी काफी होता है. ऐसे में ये लोग भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ मुहिम कैसे चला सकते हैं. बेशक लोकपाल और सीबीआई को सरकार के नियंत्रण से स्वतंत्र होना चाहिए.

अब हम लोग इस प्रक्रिया के अंतिम चरण में हैं. जन लोकपाल बिल के साथ-साथ सरकारी बिल पर बहस की जा चुकी है. संसद की स्थायी समिति ने इसे देखा है. सभी दलों की बैठक हो चुकी है और कई बैठकें बैकडोर से भी हो गई हैं. कई सारे मसौदे बांटे जा चुके हैं और अंतिम मसौदा संसद में पेश किया जा चुका है. नागरिक वर्ग इस बात को स्वीकार करता है कि संसद वैध है, क्योंकि इसे जनता द्वारा चुना गया है, लेकिन उसे इस बात का भरोसा नहीं है कि राजनीतिक व्यवस्था या सही मायनों में कार्यकारिणी भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ कोई क़दम उठाएगी. कांग्रेस ने देश पर सबसे अधिक समय तक शासन किया है, इसलिए वर्तमान स्थिति के लिए सबसे अधिक ज़िम्मेदार वही है, लेकिन दूसरे दलों को भी पाक-साफ नहीं कहा जा सकता है. सभी किसी न किसी स्तर पर भ्रष्टाचार के लिए ज़िम्मेदार हैं. सभी एक-दूसरे को भ्रष्ट कहते हैं. भाजपा कांग्रेस को भ्रष्ट कहती है और कांग्रेस भाजपा को.

अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या संसद, जो कि राजनीतिक व्यवस्था का हृदय है और जिसे चुनाव द्वारा वैधता प्रदान की गई है, पर इस बात का भरोसा किया जा सकता है कि वह ख़ुद भ्रष्टाचार को मिटाने वाला बिल पारित कर सकती है. जनता का उत्तर यही होगा कि संसद पर इस बात के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है. यही कारण है कि अन्ना हजारे के आंदोलन के साथ इतने अधिक लोग जुड़ते हैं, जिन्होंने पहले क़ानून बनाने का अधिकार नेताओं को दे रखा था. भारतीय संसद के काम करने के अपने तरीक़े हैं, जिसका पालन भी किया जाना चाहिए, लेकिन यहां सवाल उठता है कि क्या संसद सही मायनों में जनता का प्रतिनिधित्व करती है या केवल अपने अधिकारों की रक्षा करने में रुचि रखती है. वैसे भी भारतीय सांसद को जितना वेतन, भत्ता, सुविधाएं और अधिकार हासिल है, उतना किसी अन्य देश के सांसद को नहीं मिलता है. प्रति व्यक्ति आय की तुलना में तो इन्हें दी गई सुविधाएं बहुत अधिक हैं.

एक तरफ़ आम आदमी को 32 रुपये प्रतिदिन पर जीवित रहने की बात की जाती है तो दूसरी तरफ़ एक सांसद को लाखों रुपये दिए जाते हैं. चुनाव में भी ये सांसद करोड़ों रुपये ख़र्च करते हैं, जिसमें काले धन का हिस्सा भी काफी होता है. ऐसे में ये लोग भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ मुहिम कैसे चला सकते हैं. बेशक लोकपाल और सीबीआई को सरकार के नियंत्रण से स्वतंत्र होना चाहिए. सीबीआई के दुरुपयोग के बारे में कोई शक नहीं है, लेकिन टीम अन्ना जिस तरह लोकपाल को सबसे शक्तिशाली संस्था बनाना चाहती है, वह भी सही नहीं है. कोई भी संस्था इतनी शक्तिशाली नहीं होनी चाहिए, जिससे बाद में उससे ख़तरा होने लगे. लोकपाल और सीबीआई को संसद के प्रति ज़िम्मेदार होना चाहिए. संसद के प्रति ज़िम्मेदार होने का मतलब यह नहीं है कि वे सरकार या कार्यकारिणी के प्रति ज़िम्मेदार हों. संसद और सरकार एक नहीं है, दोनों अलग-अलग संस्थाएं हैं. लोकपाल के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त स्थायी समितियां बनाई जा सकती हैं. अब प्रश्न यह है कि क्या सरकार अपने लोकपाल बिल को संसद से पारित कराएगी या प्रदर्शन को मुद्दा बनाकर इस बिल को फिर टाल देगी कि अभी उसके पास समय नहीं है. क्या इस मुद्दे पर भी संसद में फूट पड़ेगी या फिर एकजुट होकर जवाब दिया जाएगा.

feedback@chauthiduniya.com

अनुमानों के अनुसार, अमेरिकी सेना द्वारा तैनात क़रीब 650 कुत्तों में से पांच प्रतिशत से अधिक में युद्ध की भयावह यादों से संबंधित विकृति विकसित हो रही है.

सूचना का अधिकार — चौथी दुनिया की पहल

सूचना मिलने के बाद क्या करें

सूचना अधिकार क़ानून के इस्तेमाल और सूचना मिलने के बाद एक आवेदक को समझदारी से क़दम उठाना चाहिए, ताकि उसे किसी प्रकार की दिक्कत न हो, साथ ही उसका काम भी हो जाए. कभी-कभी आवेदक को आरटीआई का इस्तेमाल करने पर धमकी भी मिलती है या उसे फ़र्ज़ी मामले में फंसा दिया जाता है. दरअसल, ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि भ्रष्ट अफसर या व्यक्ति नहीं चाहते कि उनका पर्दाफाश हो. नतीजतन, ऐसे लोग किसी भी क़ीमत पर गुप्त सूचनाएं सार्वजनिक नहीं होने देना चाहते. इसके लिए वे साम, दाम, दंड, भेद का भी सहारा लेने से नहीं चूकते. यहीं पर आवेदक को थोड़ी समझदारी दिखानी होती है. निडरता अच्छी बात है, लेकिन बेवजह ख़ुद को मुसीबत में डालना भी ठीक नहीं होता. आरटीआई आवेदक या कोई भी आदमी जो इस क़ानून का इस्तेमाल करना चाहता है, चौथी दुनिया के इस स्तंभ द्वारा शुरू किए गए अभियान से जुड़ सकता है, अपनी बात रख सकता है. हम आपको बताएंगे कि ऐसे अधिकारियों से कैसे निपटना है, उनसे क्या पूछना है और कैसे पूछना है. बात करते हैं कि सूचना मिलने के बाद क्या करना चाहिए? यदि आपने आरटीआई के माध्यम से किसी भ्रष्टाचार या ग़लत कार्य का पर्दाफ़ाश किया है तो आप सतर्कता एजेंसियों या सीबीआई से इस बारे में शिक़ायत कर सकते हैं. इसके अलावा आप एफआईआर भी करा सकते हैं, लेकिन देखा गया है कि सरकार दोषी के विरुद्ध लगातार शिक़ायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करती. यद्यपि कोई चाहे तो सतर्कता एजेंसियों पर भी शिक़ायत की वर्तमान स्थिति के बारे में आरटीआई के तहत सवाल पूछकर दबाव अवश्य बना सकता है. इसके अलावा ग़लत कार्यों का पर्दाफ़ाश मीडिया के ज़रिए भी किया जा सकता है. एक बात तय है कि इस प्रकार सूचनाएं मांगने और ग़लत कार्यों का पर्दाफ़ाश होने से अधिकारियों में यह स्पष्ट संदेश जाता है कि अमुक क्षेत्र के लोग अधिक सावधान हो गए हैं और भविष्य में इस प्रकार की कोई ग़लती पूर्व की भांति छुपी नहीं रहेगी. पूरा तंत्र इतना सड़-गल चुका है कि यदि हम सभी अकेले या मिलकर प्रयत्न नहीं करेंगे तो यह कभी नहीं सुधरेगा. यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन हमें ऐसा एक रणनीति बनाकर और जोख़िम कम करके करना होगा. आप आगे आएं और किसी भी मुद्दे पर आरटीआई आवेदन दाख़िल करें.

साधारणतय: कोई आप पर एकदम हमला नहीं करेगा. पहले वह आपकी ख़ुशामद करेगा, ताकि आप अपना आवेदन वापस ले लें. आप जैसे ही कोई असुविधाजनक आवेदन डालते हैं, कोई आपके पास बड़ी विनम्रता के साथ उस आवेदन को वापस लेने की विनती करने आएगा. आपको उस व्यक्ति की गंभीरता और स्थिति का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए. यदि आप उसे काफ़ी गंभीर मानते हैं तो अपने 15 मित्रों को भी तुरंत उसी कार्यालय में वही सूचना मांगने के लिए आरटीआई आवेदन डालने को कहें. बेहतर होगा, यदि ये 15 मित्र भारत के विभिन्न भागों से हों. अब आपके देश भर के 15 मित्रों को डराना किसी के लिए भी मुश्किल होगा. यदि वे उन 15 में से किसी एक को भी डराते हैं तो आप और लोगों से अर्जियां दाख़िल कराएं. इससे यह सुनिश्चित होगा कि आपको वांछित जानकारी मिलेगी और आप जोख़िमों को कम कर सकेंगे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप

(इंदिरा आवास योजना का विवरण)

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

महोदय,
मेरा नाम.................है. मैं.......................पंचायत के............गांव का निवासी हूं. मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है. इसके बावजूद अभी तक मुझे इंदिरा आवास योजना के तहत घर आवंटित नहीं किया गया है. इस संबंध में सूचना के अधिकार के तहत निम्नलिखित सूचनाएं दें:-

1. सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार क्या मैं इंदिरा आवास योजना का हकदार हूं? यदि नहीं, तो क्यों?
2. यदि हां, तो अब तक मुझे इंदिरा आवास योजना का आवंटन क्यों नहीं किया गया? मुझे इंदिरा आवास योजना का लाभ मिले, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किन अधिकारियों/कर्मचारियों की है? उनके नाम एवं पद बताएं.
3. मेरी ग्राम पंचायत में पिछले पांच वर्षों में कुल कितने लोगों को इस योजना के तहत घर आवंटित किए गए? उनकी सूची निम्नलिखित विवरणों के साथ उपलब्ध कराएं:-
क. लाभार्थी का नाम
ख. आवंटन की तारीख
ग. किस आधार पर आवंटित किया गया
घ. ग्रामसभा की जिस बैठक में लाभार्थी का चयन किया गया, उसके उपस्थिति रजिस्टर की प्रमाणित प्रति दें.
4. क्या उपरोक्त सभी आवंटन बीपीएल सूची के आधार पर किए गए? उपरोक्त पंचायत की बीपीएल सूची की प्रमाणित प्रति दें.
5. इंदिरा आवास योजना के आवंटन से संबंधित सभी शासनादेशों/निर्देशों/नियमों की प्रमाणित प्रति दें.

मैं आवेदन शुल्क के रूप में.......रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.
या
मैं बीपीएल कार्डधारक हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नंबर..........है.
यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित न हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम और पता अवश्य बताएं.
भवदीय
नाम..................
पता..................
फोन नंबर..............
संलग्नक..........
(यदि कुछ हो तो)

ज़रा हट के

कौवे के इशारे

आपने कौवे को कांव-कांव करते ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या कभी उसके इशारे देखे हैं? नहीं देखे, तो हम बताते हैं कि कौवे की प्रजाति के पक्षी रावेन बात करने के लिए मनुष्यों की तरह इशारे करते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों ने अपने शोध में पाया है. जैसे मनुष्य चीजों को दिखाने के लिए इशारे करते हैं, रावेन भी अपने पंखों से वैसे ही इशारे करते हैं. सालों पहले वैज्ञानिकों ने यह पता लगा लिया था कि रावेन, कौवे और मैगपिज अन्य पक्षियों के मुक़ाबले बहुत ज़्यादा तेज दिमाग़ वाले होते हैं. शोधकर्ता सिमोन पिका ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है, जबकि रावेन को मनुष्यों की तरह इशारे करते हुए देखा गया है. ऐसी बातें जंगली जीवों में बहुत कम नज़र आती हैं. सिमोन पिका जर्मनी के मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर ओरनिथोलाजी में जीव विज्ञानी हैं. लाइव साइंस ने पिका के हवाले से लिखा है कि रावेन को मनुष्यों की तरह इशारे करते हुए देखने के लिए उनके दल ने जंगलों की ख़ूब खाक छानी. उन्होंने कहा कि अब वह अपने दल के साथ रावेन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य इशारों की जांच-पड़ताल करेंगे. फ़िलहाल उनके शोध के अनुसार, रावेन भी चीजों की ओर इंगित करने के लिए मानव की तरह इशारे करते हैं.

कुत्तों की त्रासदी

इस बात से तो सभी वाक़िफ़ हैं कि कुत्ते इंसान से भी अधिक संवेदनशील होते हैं, लेकिन आप इस बात से वाक़िफ़ नहीं होंगे कि वे मानसिक रोग के भी शिकार हो जाते हैं. युद्ध प्रभावित इराक और अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिकी सेना के साथ तैनात कुत्ते युद्ध की भयावह यादों से संबंधित विकृति का शिकार हो रहे हैं. जानवरों के व्यवहार के विशेषज्ञ डॉ. वाल्टर एफ बर्गट जूनियर के इस दावे के बाद ये विचार दरकिनार हो गए हैं कि हिंसा का सामना करने के बाद केवल सैनिक ही ऐसी विकृति से प्रभावित होते हैं. अनुमानों के अनुसार, अमेरिकी सेना द्वारा तैनात क़रीब 650 कुत्तों में से पांच प्रतिशत से अधिक में युद्ध की भयावह यादों से संबंधित विकृति विकसित हो रही है. इनमें से आधे कुत्तों को सेवा से हटाए जाने की संभावना है. डॉ. बर्गट टेक्सास के सैन एंटोनियो में लैकलैंड वायुसेना अड्डा स्थित मिलिटी वर्किंग डॉग हास्पिटल में व्यवहार चिकित्सा विभाग के प्रमुख हैं. कुत्तों में इस स्थिति का पता लगाने वाले वह पहले चिकित्सक हैं. बर्गट ने अमेरिकी सेना के लिए काम कर रहे कुत्तों में केनाइन पीटीएसडी की समस्या विकसित होने का दावा किया है. पशुओं में व्यवहारगत समस्या के बारे में बहुत पहले से पता लगाया जा चुका है, लेकिन केनाइन पीटीएसडी की अवधारणा केवल 18 माह पुरानी है और इस पर बहस चल रही है.

ज़्यादा चालाक कौन

आम तौर पर मनुष्य को सभी जीवों से ज़्यादा समझदार माना जाता है, लेकिन हाल में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक़, केकड़े हमसे कहीं ज़्यादा चालाक होते हैं. वे अपनी ओर आने वाले किसी भी प्राणी के बारे में भांप लेते हैं कि वह दोस्त है या दुश्मन. जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलाजी में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि आस्ट्रेलिया के विजन सेंटर के अनुसंधानकर्ताओं ने पाया कि अपनी साधारण आंखों के बावजूद केकड़े आसानी से ताड़ लेते हैं कि उनकी ओर आ रहा प्राणी उनके लिए चुनौती है, दोस्त है या यूं ही पास से गुजरने वाला कोई जीव. वैज्ञानिकों ने बताया कि केकड़े की दृष्टि बेहद कमज़ोर होती है. इस परिस्थिति में भी वे न हार मानते हैं और न व्यामोह के शिकार होते हैं. वे ऐसा करना अभ्यास से सीखते हैं और मनुष्य भी इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है. उदाहरण के लिए एक बार आदत हो जाने पर हम एयरकंडीशनर की आवाज़ नज़रअंदाज़ करना शुरू कर देते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
कुछ व्यक्तिगत मामलों में उलझनें बढ़ जाने से आपके मन में अस्थिरता रहेगी. करियर में कुछ बदलाव या फेरबदल की आशंका है. जिन अधिकारियों का आपको समर्थन मिल रहा है, फ़िलहाल वे पर्दे के पीछे छुप गए हैं. यदि आप किसी कारोबार से जुड़े हैं तो वहां भी मनोवांछित सफलता न मिलने के कारण बेचैनी बढ़ सकती है.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
धार्मिक क्रियाओं में मन लगा रहेगा. एक से भले अनेक हैं, पर सबसे पहले एक ही आदमी होता है, जो सबको अपने पीछे चलने के लिए बाध्य करता है. आपके अंदर एक नया उत्साह और काम करने का जज़्बा क़ायम रहेगा. यही एक ऐसा तरीक़ा है, जब आप एक साथ कई प्रकार के कार्यों को पूरा करने में कामयाब हो जाते हैं.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
उलझनें बरक़रार रहेंगी और निर्णय लेना सहज नहीं होगा. परिवार के छोटे सदस्यों और शुभचिंतकों के बर्ताव के कारण आपका मन कुछ हद तक चिंताग्रस्त रहेगा. कार्यक्षेत्र में भी आप बहुत अधिक सक्रिय नहीं हो पाएंगे.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
सप्ताह के आरंभ में मानसिक अंतर्द्वंद्व जारी रहेंगे. चंद दिनों की शोहरत कोई शोहरत नहीं होती. शोहरत वही है, जो हमेशा बनी रहे. लगातार परिश्रम करने के बाद हफ्ते के मध्य में आपको अपने कार्यों में अभीष्ट सिद्धि का हर्ष मिल रहा है. आपके व्यक्तिगत जीवन में प्रेम और रोमांस का जो दौर चल रहा है, उसमें भी प्रगाढ़ता आएगी. अच्छे समय का सदुपयोग करें.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
जो भी कार्य उत्साहपूर्वक करेंगे, उसी में सफलता मिलेगी. सत्ता, तख्त और सिंहासन अपनी जगह पर रहते हैं, पर महत्वाकांक्षा बार-बार चढ़ती उतरती रहती है. आपके द्वारा इस हफ्ते जो भी काम किए जाएंगे, उनमें आपका आत्मविश्वास और कुशल रणनीति का प्रदर्शन साफ दिखाई देगा.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
प्रयासों के बावजूद अल्प संतोष हाथ लगेगा. विचार एवं दृष्टिकोण सुधारने से ही सफलता और प्रतिष्ठा मिलती है. आर्थिक लाभ में रुकावट आने से मन में कुछ चिंता रहेगी. एक ओर आप अपने निजी जीवन की समस्याओं से ग्रस्त हैं, वहीं आपके कारोबार का गिरता हुआ स्तर भी एक प्रश्नचिन्ह बनकर सामने आ रहा है.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
सुखद समाचारों का आगमन होगा और भाग्यवर्द्धक अवसर भी आएंगे. कारोबार या आजीविका में आ रहे उतार-चढ़ाव के मद्देनज़र आपको इस हफ्ते का मध्य धैर्यपूर्वक व्यतीत करना होगा. जो काम करने के लिए आपकी सेवाओं को निर्धारित किया गया था, अब उस पर वरिष्ठ अधिकारियों का निर्णय बदल गया है.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
हफ्ते के आरंभ में ग्रहों की चाल बेशक आपके लिए अनुकूल न हो, पर आपका इरादा अनुकूल होना ज़रूरी है. आपको थोड़े-बहुत परिश्रम से ही किसी अच्छे लाभ की आशा रखनी होगी. हफ्ते के मध्य के बाद आप किसी शुभचिंतक या दोस्त के सामने अपनी योजना रख सकते हैं, जिससे कार्यक्षेत्र में विस्तार हो सके.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
कुछ आर्थिक चिंतन व्यग्र करेंगे. कारोबार में अच्छे परिणाम मिलने के बावजूद अभी आपका मानसिक स्तर ज़्यादा मज़बूत नहीं हो पाया. आपको यह सोचकर चलना चाहिए कि रातोंरात कोई भी अमीर नहीं बन सकता. जो कुछ भी आपने अभी तक हासिल किया है, वह लोगों के लिए आकर्षण का एक केंद्र बिंदु है.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
कुछ ऐसे कारणों से आपका मन अशांत और उदासीन रहेगा, जिसके बारे में आप पहले कभी भी सोच नहीं पाए. कार्यक्षेत्र में जिस काम को करने से आपकी ख्याति बढ़नी चाहिए थी, आपको यश मिलना चाहिए था, वह संभव नहीं हो पाया. इसके पीछे विरोधियों और शत्रुओं का षड्यंत्र भी हो सकता है.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
अनेक प्रकार की योजनाओं पर एक साथ विजय पाना कठिन होगा. कुछ ज़रूरी काम रुक जाने से आपका मन चिंताग्रस्त रह सकता है. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अपने ही लोगों का रूखा व्यवहार या विश्वासपात्र मित्र की बेरुखी.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
विविध प्रकार की चेष्टाओं से लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा. परिवारीजनों एवं मित्रों की उपलब्धियों से आप प्रसन्न और उत्साहित रहेंगे. किसी अन्य की सफलता आपकी अपनी सफलता हो सकती है. यदि आप कोई नया काम करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए अवसर अनुकूल होता नज़र आ रहा है.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

प्रधानमंत्री यूसुफ रज़ा गिलानी ने संसद में कहा कि अगर कोई समझता है कि वह संसद के प्रति जवाबदेह नहीं है तो यह उसकी ग़लती है और यह सरकार को किसी हालत में मंजूर नहीं है.

पाकिस्तान

सरकार और सेना आमने-सामने

राजीव कुमार

पाकिस्तान में सरकार और सेना के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. हालांकि सरकार भी यह कोशिश कर रही है कि इस विवाद का ख़ुलासा न हो, इसलिए जैसे ही मीडिया में ख़बर आई कि सरकार सेना प्रमुख एवं आईएसआई प्रमुख को हटाना चाहती है तो प्रधानमंत्री गिलानी ने विरोध में अपना बयान जारी किया कि ऐसी अफवाह सरकार को अस्थिर करने के लिए फैलाई जा रही है. उनका कहना था कि अगर सरकार की ऐसी मंशा होती तो जनरल कियानी और लेफ्टिनेंट जनरल अहमद पाशा को सेवा विस्तार क्यों दिया जाता. सेना प्रमुख ने भी कहा कि सरकार के साथ उनका कोई विवाद नहीं है और न सेना ने सत्ता पर कब्जा करने के लिए किसी तरह का कोई षड्यंत्र किया था. दूसरी ओर इन दिनों पाकिस्तान में जैसा माहौल चल रहा है, उससे तो यही लगता है कि सरकार को इस बात का डर है कि सेना कभी भी लोकतांत्रिक तरीक़े से चुनी गई सरकार के लिए ख़तरा उत्पन्न कर सकती है.

प्रधानमंत्री यूसुफ रज़ा गिलानी ने संसद में कहा कि अगर कोई समझता है कि वह संसद के प्रति जवाबदेह नहीं है तो यह उसकी ग़लती है और यह सरकार को किसी हालत में मंजूर नहीं है. गिलानी ने कहा कि राज्य के अंदर राज्य की इजाज़त नहीं दी सकती है और सभी संस्थाएं संसद के प्रति जवाबदेह हैं, कोई भी क़ानून से ऊपर नहीं है. हालांकि गिलानी ने किसी भी संस्था का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा सेना और आईएसआई की तरफ़ ही था, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी कोई अन्य संस्था नहीं है, जिसके बारे में ऐसा कहने की ज़रूरत महसूस हो. पाकिस्तानी नेता सेना से डरते हैं. वे हमेशा इस बात से भयभीत रहते हैं कि सेना किसी भी समय उन्हें सत्ता से बेदख़ल कर सकती है. इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि गिलानी के बयान का समर्थन विपक्षी पार्टियों ने भी किया. संसद में विपक्ष के नेता चौधरी निसार ख़ान ने कहा कि हर विपक्षी पार्टी सरकार को गिराने की साजिश करती है, लेकिन हम सरकार का साथ दे रहे हैं. उन्होंने सदन को यक़ीन दिलाते हुए कहा कि उनकी पार्टी किसी भी गैर संवैधानिक बदलाव का हिस्सा नहीं बनेगी. इसका मतलब साफ है कि विपक्ष को भी सेना की ओर से विद्रोह की आशंका है.

विपक्षी पार्टियों को पता है कि जब तक देश में लोकतंत्र है, तभी तक उनका अस्तित्व है. अगर सेना का शासन स्थापित हो गया तो फिर न सत्ता में आने के बारे में सोच सकती हैं और न विपक्ष में बैठने के. इसलिए अभी यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में केवल सेना और सरकार के बीच टकराव नहीं है, बल्कि सेना और नेताओं के बीच भी टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है. संसद में इस मुद्दे पर एकजुटता है कि सेना को संसद के दायरे में ही रहना चाहिए. न केवल प्रधानमंत्री गिलानी, बल्कि राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारी भी सेना द्वारा सत्ता पर कब्जा करने की आशंका से डरे हुए हैं और जनता को विश्वास में लेने की कोशिश कर रहे हैं. पाकिस्तान के संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना की जयंती पर दिए गए संदेश में ज़रदारी ने कहा कि जनता को ताक़त और डर की वजह से बदलाव की इजाज़त नहीं देनी चाहिए. सत्ता परिवर्तन मतदान के ज़रिए होना चाहिए. बात बिल्कुल साफ है कि ज़रदारी को अभी भी सेना द्वारा सत्ता हथियाने का डर है.

राजनीतिक दल सेना को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर सेना भी अपनी ताक़त दिखाने की तैयारी में जुटी हुई है. सेना प्रमुख जनरल अशफाक परवेज कियानी और आईएसआई प्रमुख अहमद शुजा पाशा ने कहा है कि अगर सरकार उन्हें उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाती है तो वे न्यायालय में जाएंगे. कियानी ने तो अपने कमांडरों के साथ मिलना-जुलना भी शुरू कर दिया है. उन्होंने सैन्य अधिकारियों के साथ कई बैठकें कीं. हालांकि उन बैठकों में क्या बात हुई, इसका ख़ुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इस समय तो यही उम्मीद की जा सकती है कि कियानी अपनी ताक़त परख कर रहे हैं. राष्ट्रपति जरदारी द्वारा दिए गए आधिकारिक भोज में कियानी का न पहुंचना भी इस बात की ओर संकेत करता है कि पाकिस्तान में स्थितियां सरकार के अनुकूल नहीं है. दुबई से लौटे ज़रदारी ने यह भोज चीन के शीर्ष राजनयिक देई बिंगुआ के सम्मान में दिया था, जिसमें शामिल होने वालों की सूची में कियानी का भी नाम था. पाकिस्तान में सेना और सरकार, दोनों ही सत्ता के लिए अपनी ताक़त का इस्तेमाल कर रही हैं. सरकार लोकतंत्र का हवाला देकर, जनता को उसकी शक्ति के बारे में जागरूक और सांसदों को एकजुट करके अपनी सत्ता बरक़रार रखने का प्रयास कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ़ सेना प्रमुख कियानी अपने अधिकारियों से मिलकर अपनी स्थिति का जायज़ा ले रहे हैं. अगर कियानी को लगा कि अधिकारी उनके साथ हैं और उनके द्वारा लिए गए फ़ैसले को मंज़ूरी दे देंगे तो फिर वह सरकार के ख़िलाफ़ कमर कस लेंगे. यदि कियानी अपनी स्थिति से संतुष्ट न हुए तो वह अपने विरुद्ध की गई कार्रवाई के ख़िलाफ़ न्यायालय जाएंगे. गुप्त ज्ञापन से संबंधित विवाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने जब राष्ट्रपति से जवाब मांगा तो उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 248 का हवाला देते हुए जवाब देने से मना कर दिया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि राष्ट्रपति को इस मामले में कोई छूट नहीं मिलने वाली है. इससे ज़रदारी और सर्वोच्च न्यायालय के बीच तनातनी बढ़ गई है. सेना को इसका भी फ़ायदा मिल सकता है. पाकिस्तान में कभी भी कुछ हो सकता है. वहां किसी भी घटना को अप्रत्याशित नहीं कहा जा सकता. अब यह समय ही तय करेगा कि वहां लोकतंत्र मज़बूत है या सेना. वैसे जिस सरकार पर सेना का डर हावी हो, उससे कितनी उम्मीद की जा सकती है.

feedback@chauthiduniya.com

इराक के इरादे नेक नहीं

राजीव रंजन तिवारी

अमेरिका एवं अन्य पश्चिमी देश मानते हैं कि उनके संयुक्त ऑपरेशन से इराक की आंतरिक दशा पहले की अपेक्षा ठीक हो गई है, लेकिन बीते दिनों वहां हुए धमाकों ने यह संदेश दिया कि इराक के इरादे अब भी नेक नहीं हैं. इसके लिए मुख्य रूप से इराक की अंदरूनी सियासत को ज़िम्मेदार माना जा रहा है, जो अमेरिकी कूटनीति की वजह से पैदा हुई थी. यह अलग बात है कि अमेरिकी नेता और उसके राजनयिक इराकी नेताओं को आपसी तालमेल के ज़रिए मसले को सुलझाने की हिदायत दे रहे हैं, पर हक़ीक़त कुछ और है. तक़रीबन आठ वर्ष बाद इराक से अमेरिकी सैनिकों की विदाई हो गई है, पर यह नहीं लगता कि वहां की दशा सुधरने वाली है. पड़ोसियों से बिगड़े रिश्तों और संक्रमित सामाजिक संरचना ने इराक को धीरे-धीरे उसी राह पर धकेलना शुरू कर दिया है, जो देर से ही सही, पर रसातल की ओर जाती है. ग़ौरतलब है कि पिछले दिनों इराक से आख़िरी अमेरिकी सैन्य टुकड़ी के निकलने की तैयारी के दौरान राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि वाशिंगटन हमेशा अच्छे दोस्त की तरह इराक के साथ खड़ा रहेगा. 2003 में इराक में घुसी अमेरिकी सेना की आख़िरी टुकड़ी बीते 17 दिसंबर को स्वदेश वापस लौटी. 2007 में एक वक़्त ऐसा भी आया, जब इराक में 1,70,000 अमेरिकी सैनिक थे. आठ साल तक चले युद्ध में 4,500 अमेरिकी जवान मारे गए और 32,000 घायल हुए. अरबों डॉलर के इस युद्ध ने अमेरिका में एक राजनीतिक बहस भी छेड़ दी.

अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही ओबामा ने ऐलान किया कि वह इराक से सेना वापस बुलाएंगे. उसी पर अमल करते हुए उन्होंने इराक से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला लिया. इराकी प्रधानमंत्री नूरी कमाल अल मलिकी के साथ एक साझा प्रेस कांफ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यहां तक कहा कि आने वाले वर्षों में इराक की अर्थव्यवस्था भारत और चीन से भी ज़्यादा तेजी से बढ़ेगी, इराक फिर से अग्रणी तेल उत्पादक देश बनने की राह पर है. दरअसल, अमेरिका के लिए यही काफी है कि इराक फिर से ख़ुशहाली के दिन देखे. हालांकि इसमें अमेरिका का अपना स्वार्थ है, पर फ़िलहाल इराक के प्रति अमेरिका की सोच सकारात्मक कही जाएगी. अमेरिकी सेना ने 13 दिसंबर, 2003 को इराक के तत्कालीन राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को पकड़ा और तीन साल बाद उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया. सद्दाम को मारने और इराक में अमेरिकी सेना के घुसने पर बहस अब भी होती है. यदि इराक एक सफल राष्ट्र नहीं बन सका तो यह बहस अमेरिका पर भी कई आरोप लगाएगी. इराक अब भी कई चुनौतियों से जूझ रहा है. देश के उत्तरी इलाक़े में कुर्दों की अपनी स्वायत्त सरकार है. कुर्द इलाक़ा ईरान और सीरिया की सीमा से सटा है और तेल संपदा से भरपूर है. इराक उसे अपना बताता है, जबकि कुर्द ख़ुद को इराक से अलग मानते हैं. देश की सुरक्षा एजेंसियां आंतरिक सुरक्षा बहाल रखने में कुछ हद तक सक्षम हैं, लेकिन सीमा को सुरक्षित रखने लायक़ अनुभव और संख्या इराक के पास नहीं है तथा 2020 तक भी इराक अपनी जल, थल एवं वायु सीमा की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं हो पाएगा.

अलकायदा अब भी इराक के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है. 2006 एवं 2007 के भारी ख़ूनख़राबे के बाद सुन्नियों के हिंसक हमलों में कमी आई है, जो अमेरिकी प्रयास से संभव हो सका. सुन्नी उग्रपंथियों और अमेरिका के बीच सहयोग के बाद ही इराक अलकायदा के निशाने पर है. यहां हमले, अपहरण, हत्याएं और धमाके आम बात हैं. देश में दीगर संप्रदायों के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है. देश में अब तक लोकतांत्रिक ढांचा भी ठीक से खड़ा नहीं हो सका है. राजनीतिक दलों के आपसी मतभेदों के चलते देश में 2010 से अब तक न तो कोई गृह मंत्री है और न रक्षा मंत्री. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक़ , इराक दुनिया का आठवां सबसे भ्रष्ट देश है. आठ साल के युद्ध में क़रीब एक लाख लोगों को गंवाने वाले इराक की सामाजिक स्थिति काफी दयनीय है. क़रीब 25 फ़ीसदी जनता बेहद ग़रीब है, महिलाओं की स्थिति भी अच्छी नहीं है और कट्टरपंथी ताक़तों का प्रभाव बढ़ा है. क़रीब 18 लाख लोग आज भी विस्थापितों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं. इसमें कोई शक नहीं कि इराक का भला तेल से ही होगा, लेकिन 2003 से अब तक इराक में तेल उद्योग को लेकर कोई क़ानून नहीं बना. तेल से होने वाली आय को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच खींचतान मची हुई है. इराक अगर तेल उद्योग के लिए सही संरचना बना दे तो एक दशक के भीतर देश में बड़े सकारात्मक बदलाव दिखने लगेंगे. सद्दाम और इराक विरोधी अभियान के तहत अमेरिका ने इराकी जनता के बीच आपसी फूट डाली. सद्दाम हुसैन के दौर में सांप्रदायिक बैर कम था, जबकि शियाओं की अगुवाई वाली सरकार अरब के सुन्नियों को सांप्रदायिक बैर का ज़िम्मेदार ठहराती है. इसके अलावा पड़ोसियों से भी इराक को परेशानी हो सकती है. सीरिया में पिछले नौ माह से प्रदर्शन हो रहे हैं. अगर सीरिया से लोग विस्थापित होकर इराक आए तो बगदाद के लिए भारी मुश्किलें पैदा होंगी. इराक सरकार पर आरोप है कि वह ईरान के शियाओं के प्रभाव में है. इराक़ की मौजूदा अंदरूनी सियासी हालत भी बेहद ख़राब है. राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक-दूसरे पर तरह-तरह के आरोप लगा रहे हैं. पिछले दिनों बगदाद एवं आसपास के शहरों में जो धमाके हुए, उनके पीछे भी यही सियासी उथल-पुथल है. बहरहाल, हर दृष्टिकोण से बर्बाद हो चुके इराक में फ़िलहाल सुधार की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है.

feedback@chauthiduniya.com

देश का पहला इंटरनेट टीवी

हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक

- दो टूक-संतोष भारतीय के साथ
- ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
- पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
- स्पेशल रिपोर्ट
- नायाब हैं हम-उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
- साई की महिमा

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv

उन्हें मलाल है कि सरकार और प्रशासन ने कभी लोकगायकों की सुध नहीं ली. काम की तलाश में उन्हें घर से बेघर होना पड़ता है.

सबका मालिक एक

शिरडी ही साई बाबा है और साई बाबा ही शिरडी, एक-दूसरे का प्रत्यक्ष पर्यायवाची होने के साथ-साथ यह आध्यात्मिक भी है. साई शब्द के उच्चारण से आशा और आदर का भाव उत्पन्न होता है. साई बाबा को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है. ऐसा माना जाता है कि साई बाबा 1858 में औरंगाबाद से एक शादी समारोह में शिरडी आए थे. उन्होंने सबसे पहला शिविर खंडूबा मंदिर में लगाया था. वर्तमान समय में यह मंदिर श्री साई बाबा संस्थान के सामने स्थित है. आरंभ में खंडूबा मंदिर के पुरोहित भगत महालसापति थे. उन्होंने साई बाबा का स्वागत किया, आओ साई कहकर. साई एक संत के रूप में जाने जाते हैं. पश्चिम महाराष्ट्र स्थित शिरडी भारत का प्रमुख धार्मिक स्थान है. कोई भी श्री साई बाबा की पृष्ठभूमि के बारे में बहुत अधिक नहीं जानता है. साई बाबा ने महालसापति से कहा था कि उनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन उन्हें बड़ा किसी मुस्लिम फकीर ने किया था. साई लोगों के घर-घर जाकर उनसे अल्ला मालिक कहकर भिक्षा मांगा करते थे. बहुत सारे लोग उन्हें बाबा कहकर बुलाते थे. बाबा प्रत्येक व्यक्ति से रात-दिन, सप्ताह के सातों दिन ईश्वर का स्मरण करने के लिए कहा करते थे, जिसे नामसप्तक के नाम से जाना जाता है. बाबा का कहना था कि दाकूरनाथ, विट्ठल और रणछोड़ (सभी कृष्ण के नाम), ये सब भी शिरडी में निवास करते हैं.

शिरडी में सबसे प्रमुख समाधि मंदिर है, जिसका निर्माण भगवान विट्ठल ने किया था. इस मंदिर का वास्तविक नाम भुट्टीवाड़ा है. गोपाल भुट्टी बाबा के बहुत बड़े उपासक थे. बाबा ने भुट्टी से कहा था, मैं एक दिन वापस यहां रहने के लिए आऊंगा. साई बाबा की मृत्यु 15 अक्टूबर, 1918 को हुई. वर्तमान समय में शिरडी में साई बाबा की सफेद संगमरमर की समाधि और एक बड़ी सी मूर्ति है. इस सर्वोत्तम मूर्ति की रचना मुंबई के मूर्तिकार भाहू साहब तलिम ने 1954 में की थी. भगवान विट्ठल की मूर्ति को शिरडी स्थित दीक्षित वाड़ा संग्रहालय में रखा गया है. श्री साई बाबा संस्थान एक विशाल प्रशासकीय इमारत और आध्यात्मिक मंदिर है. यहां स्थित शांति निवास में श्री साई वेंगमे कर्कशा नामक एक पुस्तकालय भी है. समाधि मंदिर में साई बाबा की समाधि है. प्रवेश स्थान से समाधि मंदिर की दूरी लगभग 800 मीटर है. यहां आए तीर्थयात्रियों के विश्राम के लिए अनेक बेंच लगाई गई हैं. मंदिर में भक्तों की भीड़ हमेशा रहती है. मंदिर में चार बार आरती होती है. सुबह 5.15 पर होने वाली कक्कड़ आरती सबसे प्रमुख है. शिरडी में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार गुरु पूर्णिमा, दशहरा और रामनवमी हैं. इन त्योहारों के समय समाधि मंदिर 24 घंटे के लिए खुला रहता है.

श्री साई बाबा अपने जीवन के अंतिम क्षणों में द्वारकामाई में ही ठहरे थे. द्वारकामाई एक पुरानी उबड़-खाबड़ मस्जिदनुमा कोठी थी, यहां बैठकर वह लोगों की समस्याओं, बीमारियों और चिंताओं को दूर करते थे. साई बाबा इसी द्वारकामाई में आकर रहने लगे. उनका मानना था कि सबका मालिक एक है. द्वारकामाई के प्रथम तल पर बाबा की फोटो और एक बड़ा पत्थर रखा है, जिस पर बाबा बैठा करते थे. यहां पर दो कमरे हैं. पहले कमरे में रथ और दूसरे में पालकी रखी है. पत्थर का एक चौकोर स्टूल भी है, जिसका इस्तेमाल बाबा नहाने के लिए करते थे. द्वारकामाई मस्जिद समाधि मंदिर के प्रवेश द्वार के दाईं ओर स्थित है. गुरुस्थान एक छोटा सा मंदिर है. इसमें शिवलिंग और साई बाबा की तस्वीर है. इस मंदिर में गुरुवार और शुक्रवार को बड़ी संख्या में भक्तजन आते हैं. यह वह स्थान है, जहां साई बाबा ने पहली बार शिरडी में बाल योगी के रूप में प्रवेश किया था. इसीलिए इसे गुरुस्थान के रूप में जाना जाता है. यहां एक छोटी सी मस्जिद भी है. मंदिर के प्रवेश द्वार पर शिवलिंग और नंदी का चित्र बना हुआ है. इसके अलावा मंदिर में बारह ज्योर्तिलिंगों के भी चित्र लगे हैं. द्वारकामाई से थोड़ी ही दूरी पर साई बाबा की चावड़ी है. इस स्थान का प्रयोग बाबा सोने के लिए करते थे. चावड़ी दो भागों में विभाजित है. चावड़ी के पहले हिस्से में बाबा की एक बहुत बड़ी फोटो लगी है, वहीं दूसरे हिस्से में लकड़ी का पलंग और सफेद कुर्सी रखी है. अब्दुल बाबा की झोपड़ी से कुछ ही दूर मारुति मंदिर है. इस मंदिर में साई बाबा देवीदास (बाल योगी) के साथ सत्संग के लिए आते थे. देवीदास इस मंदिर में साई बाबा के आगमन से दस-बारह साल पहले से रह रहे थे. इसके अलावा यहां शिरडी शनि, गणपति और शंकर नाम से मंदिर भी हैं. गुरुस्थान से थोड़ी सी दूरी पर लेंडी बाग है. इसे स्वयं बाबा ने बनाया था. वह हर रोज यहां स्वयं पानी दिया करते थे. बाबा ने इस बाग को नुल्लाहा नाम दिया. इस बाग में बाबा सुबह-शाम नीम के पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए आते थे. इस बाग में आठ जगहों पर संगमरमर के पत्थरों से बने दीपगृह (नंदा दीप) हैं. यहां एक तरफ पीपल का पेड़ है, दूसरी ओर नीम का. खंडूबा मंदिर मुख्य मार्ग पर स्थित है. इसी मंदिर में पुजारी महालसापति ने साई बाबा का स्वागत आओ साई कहकर किया था. इस मंदिर में खंडूबा, बानाई और महलसाई की मूर्तियां हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

लोकगीत चौपालों से ग़ायब हो रहे हैं

लोक गायिकी

लोकगीत गाने वालों को लोक गायक कहा जाता है. लोकगीत से आशय है लोक में प्रचलित गीत, लोक रचित गीत और लोक विषयक गीत. कजरी, सोहर और चैती आदि लोकगीतों की प्रसिद्ध शैलियां हैं. त्योहारों पर गाए जाने वाले मांगलिक गीतों को पर्व गीत कहा जाता है. ये गीत रंगों के पावन पर्व होली, दीपावली, छठ, तीज एवं अन्य मांगलिक अवसरों पर गाए जाते हैं. विभिन्न ऋतुओं में गाए जाने वाले गीतों को ऋतु गीत कहा जाता है. इनमें कजरी, चतुमार्सा, बारहमासा, चइता और हिंडोला आदि शामिल हैं. इसी तरह अलग-अलग काम-धंधे करने वालों के गीतों को पेशा गीत कहा जाता है. ये गीत लोग काम करते वक्त गाते हैं, जैसे गेहूं पीसते समय महिलाएं जांत-पिसाई, छत की ढलाई करते वक़्त थपाई और छप्पर छाते वक़्त छवाई गाते हैं. इसी तरह गांव-देहात में अन्य कार्य करते समय सोहनी और रोपनी आदि गीत गाने का भी प्रचलन है. विभिन्न जातियों के गीतों को जातीय गीत कहा जाता है. इनमें नायक और नायिका की जाति का वर्णन होता है. इसके अलावा कई राज्यों में झूमर, बिरहा, प्रभाती, निर्गुण और देवी-देवताओं के गीत गाने का चलन है. ये गीत क्षेत्र विशेष की सांस्कृतिक धरोहर हैं, जिनसे वहा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है.

फ़िरदौस ख़ान

शहरीकरण ने लोक मानस से बहुत कुछ छीन लिया है. चौपालों के गीत-गान लुप्त हो चले हैं. लोक में सहज मुखरित होने वाले गीत अब टीवी कार्यक्रमों में सिमट कर रह गए हैं. फिर भी गांवों में, पर्वतों एवं वन्य क्षेत्रों में बिखरे लोक जीवन में अभी भी इनकी महक बाक़ी है. हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में पारंपरिक लोकगीतों और लोककथाओं के बिंब-प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं, जबकि मौजूदा आधुनिक चकाचौंध के दौर में शहरों में लोकगीत अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं. संचार माध्यमों के अति तीव्र विकास एवं यातायात की सुविधा के चलते प्रियतम की प्रतीक्षा में पल-पल पलकें भिगोती नायिका अब केवल प्राचीन काव्यों में ही देखी जा सकती है. सारी प्रकृति संगीतमय है. इसके कण-कण में संगीत बसा है. मनुष्य भी प्रकृति का अभिन्न अंग है, इसलिए संगीत से अछूता नहीं रह सकता. साज़ और सुर का अटूट रिश्ता है. साज़ चाहे जैसे भी हों, संगीत के रूप चाहे कितने ही अलग-अलग क्यों न हों, अहम बात संगीत और उसके प्रभाव की है. जब कोई संगीत सुनता है तो यह सोचकर नहीं सुनता कि उसमें कौन से वाद्यों का इस्तेमाल हुआ है या गायक कौन है या राग कौन सा है या ताल कौन सी है. उसे तो केवल संगीत अच्छा लगता है, इसलिए वह संगीत सुनता है यानी असल बात है संगीत के अच्छे लगने की, दिल को छू जाने की. संगीत भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है. भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब लोकगीतों में झलकता है. यह देश की सांस्कृतिक धरोहर होने के साथ-साथ प्रचार-प्रसार का सशक्त माध्यम भी है.

लोकगीत जनमानस को लुभाते रहे हैं. 80 वर्षीय कुमार का कहना है कि वर्षा ऋतु का आख्यान गीत आल्हा कभी जन-जन का कंठहार होता था. वीर रस से ओतप्रोत आल्हा जनमानस में जोश भर देता था. कहते हैं कि अंग्रेज अपने सैनिकों को आल्हा सुनवा कर ही जंग के लिए भेजा करते थे. हरियाणा के कलानौर में लोकगीत सुनाकर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे राजस्थान के चुरू निवासी लोकगायक वीर सिंह कहते हैं कि लोकगायकों में राजपूत, गूजर, भाट, भोपा, धानक एवं अन्य पिछड़ी जातियों के लोग शामिल हैं. वे रोज़ी-रोटी की तलाश में अपना घर-बार छोड़कर दूरदराज़ के शहरों एवं गांवों में निकल पड़ते हैं. वह बताते हैं कि लोकगीत हर मौसम एवं हर अवसर विशेष पर अलग-अलग महत्व रखते हैं. इनमें हर ऋतु का वर्णन मनमोहक ढंग से किया जाता है. दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद चांदनी रात में चौपालों पर बैठे किसान ढोल-मंजीरे की तान पर उनके लोकगीत सुनकर झूम उठते हैं. फ़सल की कटाई के वक़्त गांवों में काफ़ी चहल-पहल देखने को मिलती है. फ़सल पकने की ख़ुशी में किसान कुसुम-कलियों से अठखेलियां करती बयार, ठंडक और भीनी-भीनी महक को अपने रोम-रोम में महसूस करते हुए लोक संगीत की लय पर नाचने लगते हैं. वह बताते हैं कि किसान उनके लोकगीत सुनकर उन्हें बहुत सा अनाज दे देते हैं, लेकिन वह पैसे लेना ज़्यादा पसंद करते हैं. अनाज को उठाकर घूमने में उन्हें काफ़ी परेशानी होती है. वह कहते हैं कि युवा वर्ग सुमधुर संगीत सुनने के बजाय कानफोड़ू संगीत को ज़्यादा महत्व देता है. शहरों में अब लोकगीत-संगीत को चाहने वाले लोग नहीं रहे. दिन भर गली-मोहल्लों की ख़ाक छानने के बाद उन्हें बामुश्किल 50 से 60 रुपये ही मिल पाते हैं. उनके बच्चे भी बचपन से ही इसी काम में लग जाते हैं. चार-पांच साल की खेलने-पढ़ने की उम्र में उन्हें घड़ुवा, बैंजू, ढोलक, मृदंग, पखावज, नक्कारा, सारंगी एवं इकतारा आदि वाद्य बजाने की शिक्षा शुरू कर दी जाती है. यही वाद्य उनके खिलौने होते हैं.

दस वर्षीय बिरजू ने बताया कि लोकगीत गाना उसका पुश्तैनी पेशा है. उसके पिता, दादा और परदादा को भी यह कला विरासत में मिली थी. इस लोकगायक ने पांच साल की उम्र से ही गीत गाना शुरू कर दिया था. इसकी मधुर आवाज़ को सुनकर किसी भी मुसाफ़िर के क़दम ख़ुद ब ख़ुद रुक जाते हैं. इसके सुर एवं ताल में भी ग़ज़ब का सामंजस्य है. मानसिंह ने इकतारे पर हीर-रांझा, सोनी-महिवाल, शीरी-फ़रहाद एवं लैला-मजनूं के क़िस्से सुनाते हुए अपनी उम्र के 55 साल गुज़ार दिए. उन्हें मलाल है कि सरकार और प्रशासन ने कभी लोकगायकों की सुध नहीं ली. काम की तलाश में उन्हें घर से बेघर होना पड़ता है. उनकी जिंदगी ख़ानाबदोश बनकर रह गई है. ऐसे में दो वक़्त की रोटी का इंतज़ाम करना पहाड़ से दूध की नहर निकालने से कम नहीं है. उनका कहना है कि दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण बच्चे शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं से महरूम रहते हैं. सरकार की किसी भी जनकल्याणकारी योजना का लाभ उन्हें नहीं मिलता. साक्षरता, प्रौढ़ शिक्षा, वृद्धावस्था पेंशन एवं इसी तरह की अन्य योजनाओं से वे अनजान हैं. वह कहते हैं कि रोज़गार की तलाश में दर-दर की ठोंकरे खाने वाले लोगों को शिक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. अगर रोज़गार मिल जाए तो उन्हें पढ़ना भी अच्छा लगेगा. वह बताते हैं कि लोक संपर्क विभाग के कर्मचारी कई बार उन्हें सरकारी समारोह या मेले में ले जाते हैं और पारिश्रमिक के नाम पर 200 से 300 रुपये तक दे देते हैं, लेकिन इससे कितने दिन गुज़ारा हो सकता है. आख़िर रोज़गार की तलाश में भटकना ही उनकी नियति बन चुका है.

कई लोक गायकों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई. भूपेन हजारिका और कैलाश खैर इसकी बेहतरीन मिसालें हैं. असम के सादिया में जन्मे भूपेन हजारिका ने बचपन में एक गीत लिखा और दस साल की उम्र में उसे गाया. बारह साल की उम्र में उन्होंने असमिया फिल्म इंद्रमालती में काम किया था. उन्हें 1975 में सर्वोत्कृष्ट क्षेत्रीय फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 1992 में सिनेमा जगत के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के सम्मान से नवाज़ा गया. इसके अलावा उन्हें 2009 में असोम रत्न और संगीत नाटक अकादमी अवॉर्ड और 2011 में पद्मभूषण जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया. कैलाश खैर ने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई और लोकगीतों को विदेशों तक पहुंचाया, मगर सभी लोक गायक भूपेन हजारिका और कैलाश खैर जैसे क़िस्मत वाले नहीं होते. ऐसे कई लोक गायक हैं, जो अनेक सम्मान पाने के बावजूद बदहाली में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं. राजस्थान के थार रेगिस्तान की ख़ास पहचान मांड गायिकी को बुलंदियों तक पहुंचाने वाली लोक गायिका रुक्मा उम्र के सातवें दशक में बीमारियों से लड़ते-लड़ते ज़िंदगी की जंग हार गईं. बीती 20 जुलाई को उनकी मौत के साथ ही मांड गायिकी का एक युग भी समाप्त हो गया. थार की लता के नाम से प्रसिद्ध रुक्मा ज़िंदगी के आख़िरी दिनों तक पेंशन के लिए कोशिश करती रहीं, लेकिन यह सरकारी सुविधा उन्हें नसीब नहीं हुई. वह मधुमेह और ब्लड प्रेशर से पीड़ित थीं, लेकिन पैसों की कमी के कारण वक़्त पर दवाएं नहीं ख़रीद पाती थीं. उनका कहना था कि वह प्रसिद्ध गायिका होने का ख़ामियाज़ा भुगत रही हैं. सरकार की तरफ़ से उन्हें कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली. हालत इतनी बदतर है कि बीपीएल में भी उनका नाम शामिल नहीं है. विधवा और विकलांग पेंशन से भी वह वंचित हैं. सरकारी बाबू सोचते हैं कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है.

रुक्मा ने विकलांग होते हुए भी देश-विदेश में सैकड़ों कार्यक्रम पेश कर मांड गायिकी की सरताज मलिका रेशमा, अलनजिला बाई, मांगी बाई और गवरी देवी के बीच अपनी अलग पहचान बनाई. बाड़मेर के छोटे से गांव जाणकी में लोक गायक बसरा ख़ान के घर जन्मी रुक्मा की सारी ज़िंदगी ग़रीबी में बीती. रुक्मा की दादी अकला देवी एवं माता आसी देवी थार इलाक़े की ख्यातिप्राप्त मांड गायिका थीं. गायिकी की बारीकियां उन्होंने अपनी मां से ही सीखीं. केसरिया बालम आओ नी, पधारो म्हारे देस...उनके इस गीत को सुनकर श्रोता भाव विभोर हो उठते थे. उन्होंने पारंपरिक मांड गायिकी के स्वरूप को बरक़रार रखा. उनका मानना था कि पारंपरिक गायिकी से खिलवाड़ करने से उसकी नैसर्गिक मौलिकता ख़त्म हो जाती है. विख्यात रंगमंच कर्मी मल्लिका साराभाई ने उनके जीवन पर डिस्कवरी चैनल पर वृत्तचित्र प्रसारित किया था. विदेशों से भी संगीतप्रेमी उनसे मांड गायिकी सीखने आते थे. ऑस्ट्रेलिया की सेरहा मेडी ने बाडमेर के गांव रामसर में स्थित उनकी झोपड़ी में रहकर उनसे संगीत की शिक्षा ली और फिर गुलाबी नगरी जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित थार महोत्सव में मांड गीत प्रस्तुत कर ख़ूब सराहना पाई. रुक्मा की ज़िंदगी के ये यादगार लम्हे थे. अब उनकी छोटी बहू हनीफ़ा मांड गायिकी को ज़िंदा रखने की कोशिश कर रही हैं. एक तरफ़ सरकार कला संस्कृति के नाम पर बड़े-बड़े समारोहों का आयोजन कर उन पर करोड़ों रुपये पानी की तरह बहा देती है, वहीं दूसरी तरफ़ देश की कला-संस्कृति को विदेशों तक फैलाने वाले कलाकारों को गुरबत में मरने के लिए छोड़ देती है.

रुक्मा ने विकलांग होते हुए भी देश-विदेश में सैकड़ों कार्यक्रम पेश कर मांड गायिकी की सरताज मलिका रेशमा, अलनजिला बाई, मांगी बाई और गवरी देवी के बीच अपनी अलग पहचान बनाई. बाड़मेर के छोटे से गांव जाणकी में लोक गायक बसरा ख़ान के घर जन्मी रुक्मा की सारी ज़िंदगी ग़रीबी में बीती. रुक्मा की दादी अकला देवी एवं माता आसी देवी थार इलाक़े की ख्यातिप्राप्त मांड गायिका थीं. गायिकी की बारीकियां उन्होंने अपनी मां से ही सीखीं.

firdaus@chauthiduniya.com

अनंत विजय

ख़त्म होता नक्सलियों का ख़ौफ़

जन लोकपाल बिल पर सरकार और टीम अन्ना के बीच जारी बवाल, रिटेल में विदेशी निवेश पर सरकार, उसके सहयोगी दलों एवं विपक्ष केबीच मचे घमासान और गृहमंत्री चिदंबरम पर एक के बाद एक लग रहे आरोपों के बीच देश में कई अहम ख़बरें गुम सी हो गईं. हर दिन या तो अन्ना हजारे कोई ऐलान करते हैं या कांग्रेस का कोई नेता अन्ना पर हमला करता है या किसी न किसी वजह से संसद में हंगामा हो जाता है या अदालत कोई ऐसा फ़ैसला सुना देती है या फिर कोई और टिप्पणी कर देता है, जो सुर्ख़ियां बनकर मीडिया में छा जाता है. देश भर में हुए हालिया उप-चुनावों के नतीजों के कई गंभीर निहितार्थ निकले, जिन पर मीडिया में न तो मंथन हो पाया और न ढंग से उस पर चर्चा हो सकी. अख़बारों में कहीं किसी कोने-अंतरे में वैसी ख़बरें दब गईं और न्यूज चैनलों में तो तवज्जो ही नहीं मिल पाई. अगर हम उड़ीसा विधानसभा के लिए हुए उपचुनावों के नतीजों का विश्लेषण करें तो साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि वहां माओवादियों का असर कम होना शुरू हो गया है. जिन इलाकों में माओवादियों को लंबे समय से आदिवासियों से हर तरह का समर्थन मिल रहा था, वहां भी अब वे लगभग बेअसर होने लगे हैं.

उड़ीसा के आदिवासी बहुल जिले नवरंगपुर के उमरकोट विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नज़र डालें तो नक्सलियों के समर्थन में आ रही इस कमी को साफ तौर पर परिलक्षित किया जा सकता है. चुनाव के ऐन पहले माओवादियों ने नक्सल प्रभावित उमरकोट विधानसभा में आदिवासियों को चुनाव का बहिष्कार करने का फरमान जारी कर दिया, लेकिन नक्सलियों के उस फरमान को धता बताते हुए आदिवासियों ने बड़ी संख्या में मतदान किया. चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, पचहत्तर फीसदी से ज़्यादा आदिवासियों ने वोट डाले. इसी विधानसभा के छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे रायगढ़ इलाके में, जो दशकों से माओवादियों का गढ़ माना जाता है, सबसे ज़्यादा मतदान हुआ. गौरतलब है कि यह वही रायगढ़ है, जहां माओवादियों ने एक जनसभा के दौरान बीजू जनता दल के विधायक जगबंधु मांझी की नृशंस तरीके से हत्या कर दी थी. मांझी की मौत के बाद हुए इस उपचुनाव में नक्सलियों द्वारा बहिष्कार के फरमान के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में मतदान होना नक्सलियों के कमजोर पड़ने की निशानी है. इस पूरे इलाके में जबरदस्त मतदान का फायदा सत्तारूढ़ बीजू जनता दल के उम्मीदवार को हुआ, जिसने तकरीबन बीस हजार वोटों से जीत हासिल की. माओवादियों ने चुनाव के बहिष्कार के साथ-साथ बीजू जनता दल के खिलाफ भी अपनी राय जाहिर की थी, जो लगभग बेअसर रही.

उपचुनावों के नतीजों और नक्सलियों द्वारा चुनाव के बहिष्कार के अलावा भी उड़ीसा में काफी कुछ घटित हो रहा है, जिसे अगर रेखांकित किया जाए तो माओवादियों के लगातार कमजोर होते जाने की तस्वीर सामने आती है. माओवादियों के वरिष्ठ नेता किशन जी को जब पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था तो माओवादियों ने दो दिनों के बंद का ऐलान किया था. उस बंद का भी कोई असर उड़ीसा और झारखंड के कई इलाकों में देखने को नहीं मिला. मलकानगिरी, जो उड़ीसा का सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, में यह बंद लगभग बेअसर रहा. आदिवासी इलाकों के लड़के-लड़कियां अपने स्कूल-कॉलेज पहुंचे. बंद के दौरान छात्रों का ऐसा व्यवहार अब तक इस इलाकेमें कभी नहीं देखा गया था. मलकानगिरी जैसे नक्सलियों के गढ़ में तो बंद के ऐलान के बाद कर्फ़्यू जैसे हालात हो जाते थे. सड़कों पर सन्नाटा और पूरे इलाके में कामकाज ठप. नक्सलियों का खौफ इतना ज़्यादा था कि बंद के दौरान मां-बाप अपने बच्चों को घर से बाहर तक नहीं निकलने देते थे. यही हाल झारखंड के डाल्टनगंज और पलामू जिलों में देखने को मिला. दो दिन के बंद के दौरान स्कूल-कॉलेजों में छात्र पहुंचे, लोग सड़कों पर निकले, अपने कार्यालय पहुंचे, सड़कों पर गाड़ियां चलीं. सबसे आश्चर्यजनक बात तो उड़ीसा के नुआपाड़ा में देखने को मिली. वहां नक्सलियों ने यातायात बंद करने के लिए पेड़ काटकर सड़क पर डाल दिया था. स्थानीय नागरिकों ने नक्सलियों से डरे बगैर पेड़ हटाकर सड़क को यातायात के लिए खोल दिया. पहले यह काम सुरक्षाबल करते थे. स्थानीय जनता के इस कदम को भी नक्सलियों के घटते प्रभाव के तौर पर देखा गया.

दरअसल यह सब दो वजहों से हो रहा है. एक तो राज्य और केंद्र सरकार ख़ामोशी के साथ मिलकर इन इलाकों में नक्सलियों का प्रभाव कम करने की दिशा में काम कर रही हैं, जिसके थोड़े-बहुत नतीजे अब दिखाई देने लगे हैं. नक्सल प्रभावित इलाकों में केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर समग्र विकास के प्रयास किए. आदिवासियों को सत्ता के भय से मुक्त किया और उनके शोषण पर लगाम लगाकर उनका विश्वास हासिल करने में आंशिक सफलता भी हासिल की. अर्द्धसैनिक बलों ने नक्सल प्रभावित इलाकों में आदिवासियों का विश्वास जीतने के फॉर्मूले पर काम किया और बहुत हद तक सफलता भी पाई. सरकार के रणनीतिकारों का मानना है कि आदिवासियों का जितना भरोसा सरकार या सत्ता पर बढ़ेगा, उतना ही नक्सलियों को समर्थन मिलना कम होगा. नक्सलियों को समर्थन मिलना कम होने की एक और वजह है, जो सामाजिक है, वह यह कि अब इस आंदोलन में आपराधिक तत्वों का प्रवेश हो गया है, जो आंदोलन के नाम पर इलाके में वसूली करते हैं, पैसे वालों का अपहरण करके फिरौती वसूलते हैं. इस तरह की भी कई ख़बरें सामने आईं, जिनमें पता चला कि माओवादियों ने लड़कियों को जबरन अपने साथ रखकर उनसे बलात्कार किया. सिद्धांतों एवं विचारों का स्थान लूटपाट और चोरी-डकैती ने ले लिया. जबरन हफ्ता वसूली, फिरौती, लड़कियों एवं महिलाओं के साथ बढ़ती बदसलूकी, आंदोलन के नाम पर हत्या जैसी वारदातों ने आम जनता के मन में नक्सलियों के प्रति नफरत का भाव पैदा कर दिया. जो आदिवासी नक्सलियों को तन-मन-धन से समर्थन दे रहे थे, वे अब डर से समर्थन देने लगे, लेकिन डर, ख़ौफ या भय से मिला समर्थन ज़्यादा दिनों तक चलता नहीं है और जैसे ही मौका मिलता है, वही समर्थन विरोध का स्वर बनकर खड़ा हो जाता है. माओवादियों के साथ भी वही हुआ. जैसे ही आदिवासी इलाकों की जनता का माओवादियों से मन टूटा और राज्य सत्ता में भरोसा कायम हुआ, वैसे ही विरोध के स्वर उठने लगे और फिर जब भी मौका मिला, विरोध या तो मुखर या मौन के रूप में सामने आया. अब जरूरत इस बात की है कि इस बदलाव की अहमियत को समझते हुए राज्य सत्ता आदिवासियों का भरोसा तो जीते ही, उनके दिलों को भी जीतने की कोशिश करे, ताकि नक्सल समस्या का जड़ से अंत किया जा सके, लेकिन ऐसा लगता है कि लोकपाल के शोरगुल में इस देश के शासक वर्ग और जनता, दोनों का इस समस्या से ध्यान लगभग हट सा गया है. नक्सलवाद हमारे देश के लिए एक ऐसी समस्या है, जो लगभग नासूर की शक्ल अख़्तियार कर चुकी है.

ऐसे में इस समस्या में अगर थोड़ा भी सकारात्मक बदलाव दिखाई देता है तो उसका प्रचार-प्रसार होना चाहिए. इसका फायदा यह होगा कि नक्सल प्रभावित दूसरे इलाकों में सरकार के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ेगा और नक्सलियों के प्रति भरोसा घटेगा. भरोसे की इसी बढ़त-घटत में इस समस्या का समाधान निकलेगा, लेकिन केंद्र में सरकार चला रही कांग्रेस पार्टी अपनी कामयाबियों को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील ही नहीं है. कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जनता से संवाद नहीं कर पा रहे हैं, अपनी कामयाबियों को जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं. पहले पार्टी ने अपने उन दर्जन भर नेताओं की एक सूची जारी की थी, जो मीडिया में पार्टी का पक्ष रखेंगे, लेकिन उन नेताओं का कहीं अता-पता नहीं है. नतीजा यह हुआ कि सरकार के प्रयत्नों से समाज में जो सकारात्मक बदलाव आए, उनका प्रचार नहीं हो सका. वहीं विपक्ष और टीम अन्ना ने बढ़-चढ़कर सरकार की नाकामियों को मीडिया के जरिए जनता तक पहुंचाया. अभी हाल में दस युवा मंत्रियों को सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने का जिम्मा दिया गया, लेकिन ये युवा मंत्री भी गाहे-बगाहे ही नज़र आते हैं. नतीजा यह हो रहा है कि सरकार की उपलब्धियां जनता तक नहीं पहुंच पा रही हैं. लंबे समय से नक्सलियों का बड़ा हमला नहीं हुआ है, किशन जी को मारकर नक्सलियों की कमर तोड़ दी गई, लेकिन इन कामयाबियों को नक्सल इलाकों में पहुंचा कर वहां की जनता का विश्वास जीतने का प्रयास नहीं किया जा रहा है. गरीबों के लिए भोजन की गारंटी देने वाला ऐतिहासिक कानून आने वाला है, जिसका बड़ा फायदा जंगलों में रहने वालों को होगा, यह बात भी उन इलाकों में नहीं पहुंच पा रही है. यूपीए सरकार अपने पहले कार्यकाल में अपनी हर छोटी-बड़ी उपलब्धि का ढिंढोरा पीटती नज़र आती थी, लेकिन अब वह आलस्य में डूबी नज़र आ रही है. वक्त आ गया है कि सरकार के कर्ताधर्ता सत्ता के मद से बाहर निकलें और जनता से संवाद स्थापित करें, ताकि नक्सलवाद की समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके.

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

अदम गोंडवी : आम आदमी का शायर

संजय सक्सेना

शब्द-शब्द संघर्ष करने वाले साहित्य जगत के शिल्पकार रामनाथ सिंह उर्फ़ अदम गोंडवी नहीं रहे. ग़ुरबत में ज़िंदगी गुज़ार कर साहित्य की सेवा करने वाले अदम गोंडवी ने अभाव में ज़िंदगी के ताप को महसूस कराने के लिए अपने गांव आटा परसपुर (गोंडा, उत्तर प्रदेश) की ओर से साहित्यानुरागियों का ध्यान खींचने के लिए क़लम को तलवार बनाते हुए कहा था,

आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को.

इन पंक्तियों के रचियता और गाहे-बगाहे इसे गुनगुनाने वाले रामनाथ ने इन पंक्तियों की रचना उस समय की थी, जब उनका गांव दबंगों से भयाक्रांत था. दबंग जब तब ग़रीबों की बहू-बेटियों को उठा ले जाने को अपना हक़ समझते थे. आम जनता की वेदनाओं को शब्दों में पिरोकर व़ाले गोंडवी की मौत पर सभी ने शोक व्यक्त किया. शोक व्यक्त करने वालों में वे लोग तो थे ही, जो गोंडवी को अपना आदर्श मानते थे, ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं थी जिनका साहित्य जगत से कुछ लेना-देना नहीं था. ऐसे लोगों में नेताओं और नौकरशाहों की संख्या अधिक थी, जो ऐसे मौक़ों पर प्रेस नोट के माध्यम से दुख व्यक्त कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं. अदम गोंडवी को पीजीआई में इलाज तक तब उपलब्ध हो पाया था, जब पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने हस्तक्षेप किया. गोंडवी लीवर संबंधी बीमारी से पीड़ित थे.

अंत समय तक वह अपने घर वालों को हिदायत देते रहे कि उनके इलाज के लिए सरकार का मुंह न देखा जाए. उन्होंने सरकारी मदद लेने से इंकार कर रखा था. अदम की इच्छानुसार उनका अंतिम संस्कार उनके गांव में ही किया गया.

वर्ष 1973 में उनके गांव के दलित हरख़ू की बेटी कृष्णा के साथ शर्मसार कर देने वाली घटना हुई थी और डर के कारण पूरा गांव मौन था. उस समय अदम मुखर होकर अपनी बात कहने में लगे थे. उनकी कविता आग उगल रही थी और इसकी तपिश भारत ही नहीं बीबीसी हिंदी सेवा लंदन तक जा पहुंची थी. बीबीसी ने गोंडवी की इस कविता को (जो कविता नहीं चश्मदीद गवाह बन प्रस्फुटित हुई थी) विश्व भर में फैलाया.

वर्षों तक हिंदी साहित्य की सेवा के बाद बीते 18 दिसंबर को प्रातकाल: सवा पांच बजे लखनऊ पीजीआई में आख़िरी सांस लेने वाले रामनाथ की छवि गंवई कवि की थी. वह अपने गांव के यथार्थ के बारे में कहा करते थे-

फटे कपड़ों में तन ढाके गुज़रता है जहां कोई
समझ लेना वो पगडंडी अदम के गांव जाती है

आज़ादी के बाद 22 अक्टूबर, 1947 में गोंडा ज़िले के छोटे से गांव आटा परसपुर में जन्मे अदम गोंडवी कभी अपनी जड़ों से दूर नहीं हुए. यही वजह थी कि खेती-किसानी करते हुए भी वह अपनी रचनाओं के ज़रिये जनआक्रोश और पीड़ा को शब्दों में पिरोते रहे. शहरी चकाचौंध से दूर धूल के ग़ुबार व खेत-खलिहान के बीच क़लम को तलवार की तरह धार देने वाले गोंडवी फक्कड़ स्वभाव के जनकवि थे. कवि सम्मेलनों में गोंडवी मंच पर होते तो श्रोताओं की फ़रमाइश का सिलसिला मुश्किल से थमता था. उनकी रचनाओं की धार और मार का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि 1980-90 के दशक में उनकी रचनाएं जन आंदोलनों में छाई रहती थीं. उनकी रचना यह रचना आज भी लोगों की ज़ुबान पर छाई रहती है.

सौ में सत्तर आदमी फ़िलहाल जब नाशाद है
दिल पर रखकर हाथ कहिए देश क्या आज़ाद है
कालू भुने प्लेट में, विह्स्की गिलास में
उतरा है रामराज विधायक निवास में

कवि नरेश सक्सेना कहते हैं कि अदम गोंडवी की गिनती उन कवियों में होती थी, जिनकी ख्याति जन-जन में थी. जनता के संघर्ष को लेकर चलने वाले कवि अदम गोंडवी सहज भाव से हमारे जीवन व हमारे चिंतन में प्रवेश कर जाते थे. उनका निधन हमारे समय की बहुत बड़ी क्षति है. यह जनसंघर्ष की भी बहुत बड़ी क्षति है.

इलाज के लिए गोंडवी को हुई मुश्किलों से शायर मुनव्वर राना के दिल को काफ़ी ठेंस लगी. वह अपने जज्बात को रोक नहीं पाए और बोले-इस मुल्क में परंपरा है मांगने की, मांगोगे तो पद्मश्री मिल जाएगा और नहीं मांगोगे तो इलाज भी नहीं मिलेगा. अदम सरकार के दरबार में सलामी देने नहीं जाते थे. वह जिस सम्मान के हक़दार थे, उसका दसवां हिस्सा भी उन्हें नहीं मिला. आदमी को सम्मान नहीं मिलता तो वह अपने आप को ख़त्म करने लगता है, जैसा गोंडवी जैसे तमाम ख़ुद्दार लोगों के साथ होता है.

feedback@chauthiduniya.com

आज़ादी के बाद 22 अक्टूबर, 1947 में गोंडा ज़िले के छोटे से गांव आटा परसपुर में जन्मे अदम गोंडवी कभी अपनी जड़ों से दूर नहीं हुए. यही वजह थी कि खेती-किसानी करते हुए भी वह अपनी रचनाओं के ज़रिये जनआक्रोश और पीड़ा को शब्दों में पिरोते रहे. शहरी चकाचौंध से दूर धूल के ग़ुबार व खेत-खलिहान के बीच क़लम को तलवार की तरह धार देने वाले गोंडवी फक्कड़ स्वभाव के जनकवि थे.

किताब मिली

पुस्तक का नाम: 21 श्रेष्ठ कहानियां

लेखक: अमरकांत

प्रकाशक: डायमंड बुक्स

मूल्य: 110 रुपये

यह किताब कथाकार अमरकांत की 21 कहानियों का संग्रह है.

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.

चौथी दुनिया
एफ-2, सैक्टर-11, नोएडा-201301
ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

ब्राईट® की सभी के लिए उपयोगी पुस्तकें

FROM THE HOUSE OF : BRIGHT® Career's® BOOKS | COMPETITION REFRESHER | SCIENCE REFRESHER | G.K. GENERAL KNOWLEDGE REFRESHER

BRIGHT PUBLICATIONS®
Publishers of INDIA'S LARGEST SELLING Competition & School Books
2767, Kucha Chellan, Darya Ganj, New Delhi-110 002 (India) —— (ESTD. 1968)
Ph.: 011-64632226 & 3226, 23282226 & 3226 Fax: 011-23269227 Telefax: 64633226
E-mail: sales@brightpublications.com | Web Site: http://www.brightpublications.com

FOR VPP ORDERS, SEND ₹ 25/- AS ADVANCE & FOR FREE CATALOGUE WRITE TO US

इस कॉम्पैक्ट कार का नाम है अक्वा, लेकिन विदेशों में यह पायरस सी के नाम से जानी जाएगी. यह प्रति लीटर 35.4 किलोमीटर का माइलेज देगी.

मारुति की नई पेशकश

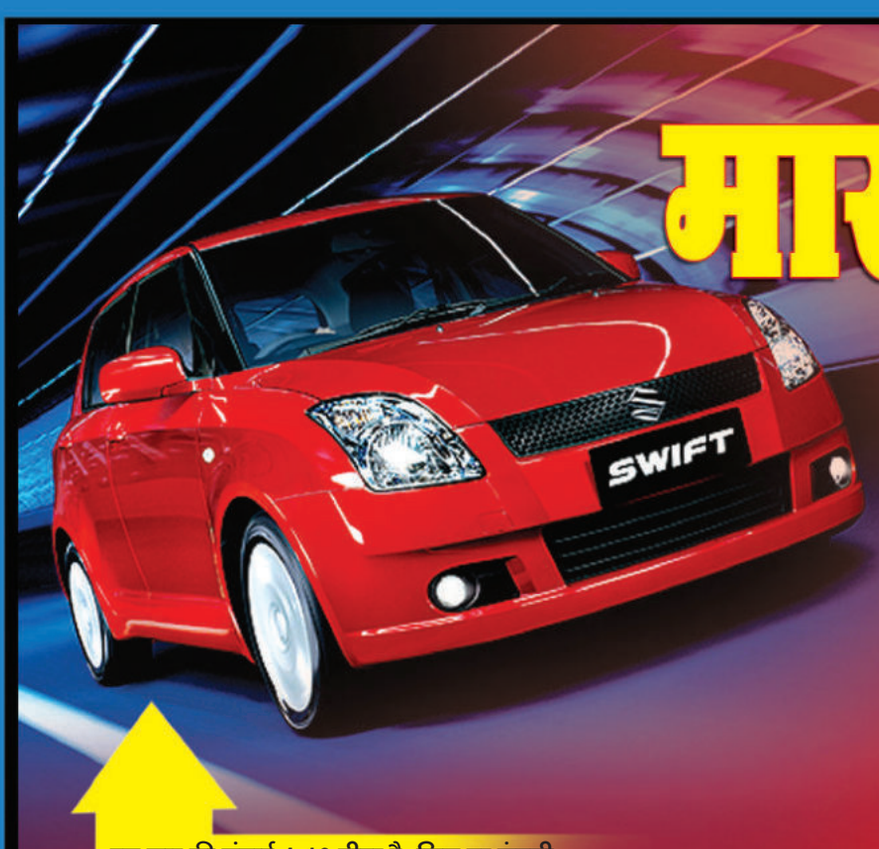

इस कार की लंबाई 4.16 मीटर है, जिस पर कंपनी को 22 फ़ीसदी एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है.

अगर आप मारुति की पॉपुलर सेडान स्विफ्ट डिज़ायर ख़रीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए एक ख़ुशख़बरी है कि कंपनी डिज़ायर का सस्ता विकल्प उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है. बताया जाता है कि कंपनी इसे लांच करने से पहले इसकी लंबाई घटाएगी, जिससे एक्साइज ड्यूटी में भारी बचत होगी. फ़िलहाल इस कार की लंबाई 4.16 मीटर है, जिस पर कंपनी को 22 फ़ीसदी एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है, लेकिन कार की लंबाई घटाने के बाद कंपनी को 10 फ़ीसदी एक्साइज ड्यूटी देनी होगी. इससे कंपनी को कुल 56 हज़ार रुपये की बचत होगी. सूत्रों का कहना है कि कंपनी ने अपनी नई डिज़ायर का परीक्षण उत्पादन शुरू कर दिया है. नई डिज़ायर पर कंपनी को भारत में छोटी कारों को उत्पाद शुल्क में मिलने वाली छूट का लाभ भी मिलेगा. कहा तो यह भी जा रहा है कि नई डिज़ायर को भारत में उतारने से पहले इसका निर्यात लैटिन अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया को किया जाएगा.

भारत में इसकी लांचिंग को लेकर कंपनी की तरफ़ से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं बताया गया है. स्विफ्ट डिज़ायर के मौजूदा मॉडलों की दिल्ली में एक्स-शोरूम क़ीमत 4.88 लाख से 7.07 लाख रुपये के बीच है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

नोकिया एन-9 यानी पैसा वसूल

नोकिया के मोबाइल फोन न केवल उपयोगिता, बल्कि यूजर कंफर्ट की दृष्टि से भी बेहतर होते हैं. भारत में इस कंपनी की सफलता का राज यही है. नोकिया के एन-8 ने भारत में जितनी हलचल मचाई, उतनी एन-9 ने तो नहीं, लेकिन यह भी कुछ कम नहीं है. नोकिया एन-9 की सबसे बड़ी ख़ासियत है कि यह पोलीकार्बन के एक पीस से बना है. इसलिए इसमें कहीं भी जोड़ नहीं दिखता. इसके अंदर ओएमएपी 3630 प्रोसेसर है और ताक़तवर जीपीयू भी. इन सबका फ़ायदा यह है कि इसमें एक साथ कई सारे काम हो सकते हैं. इसमें भी आईफोन की तरह 16 और 32 जीबी की स्टोरेज क्षमता है. इसकी स्क्रीन 3.9 इंच की है, जो वक्राकार है, जिससे तस्वीर देखने में आसानी होती है. नोकिया ने स्क्रीन पर काफी मेहनत की है और इसे लेमिनेटेड टेक्नोलॉजी का सहारा दिया, जो इसे आईफो-4 की स्क्रीन की तरह बनाता है. नोकिया ने इसमें एन-8 की तरह 12 मेगा पिक्सल का कैमरा तो नहीं दिया है, लेकिन 8 मेगा पिक्सल का दमदार कैमरा दिया है, जिसका लेंस 28 एमएम का है और उसमें डुएल एलईडी फ्लैश भी है. इसमें कार्ल जाइस टेसर ऑप्टिक्स है, जिसके सहारे यह शानदार वीडियो रिकॉर्डिंग करता है. ख़ास बात यह है कि इसमें स्टीरियो साउंड भी है. जहां तक बैट्री की बात है, इसकी बैट्री 24 घंटे चल सकती है, चाहे आप दर्जनों ईमेल भेजें या फिर आधा घंटा नेट सर्फिंग करें. इसका वज़न 135 ग्राम है, जो ज़्यादा नहीं है. इसका लुक और परफॉर्मेंस सभी कुछ बेहतरीन है. इसमें म्यूज़िक क्वालिटी शानदार है. इसकी क़ीमत 32,000 रुपये है.

इसकी स्क्रीन 3.9 इंच की है, जो वक्राकार है, जिससे तस्वीर देखने में आसानी होती है. नोकिया ने स्क्रीन पर काफी मेहनत की है और इसे लेमिनेटेड टेक्नोलॉजी का सहारा दिया, जो इसे आईफो-4 की स्क्रीन की तरह बनाता है. नोकिया ने इसमें एन-8 की तरह 12 मेगा पिक्सल का कैमरा तो नहीं दिया है, लेकिन 8 मेगा पिक्सल का दमदार कैमरा दिया है.

सबसे बड़ी टीवी निर्माता कंपनी

सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने जापानी कंपनी सोनी की पूरी हिस्सेदारी ख़रीदने का ऐलान किया है. इन दोनों कंपनियों ने मिलकर एलसीडी डिस्पले की एक कंपनी बनाई थी. अब सोनी ने अपना हिस्सा सैमसंग को बेचने का मन बनाया है.

कोरियाई कंपनी सैमसंग अब दुनिया की सबसे बड़ी टेलीविज़न निर्माता कंपनी बन गई है. दरअसल, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने जापानी कंपनी सोनी की पूरी हिस्सेदारी ख़रीदने का ऐलान किया है. इन दोनों कंपनियों ने मिलकर एलसीडी डिस्पले की एक कंपनी बनाई थी. अब सोनी ने अपना हिस्सा सैमसंग को बेचने का मन बनाया है. यह सौदा 94 करोड़ डॉलर में हुआ और इसके बाद सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी टीवी निर्माता कंपनी बन गई. सोनी के लिए यह बिज़नेस घाटे का सौदा साबित हुआ. पिछले सात सालों से यह संयुक्त उपक्रम घाटे में चल रहा था.

30 पैसे में एक किलोमीटर!

महिंद्रा एंड महिंद्रा की यह इलेक्ट्रिक कार सिर्फ़ 3 रुपये में 9.60 किलोमीटर की दूरी तय करेगी यानी 30 पैसे में एक किलोमीटर. यह पहले लांच हुई इलेक्ट्रिक कार रेवा की उत्तराधिकारी है.

पेट्रोल की बढ़ती क़ीमतों के बाद अब हर कोई कार चलाने से पहले बहुत कुछ सोचने लगा है. ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज देने वाली कारों की तलाश बढ़ गई है. ऐसे में एक कार सामने आई है, जिसका माइलेज के मामले में कोई सानी नहीं है.

महिंद्रा एंड महिंद्रा की यह इलेक्ट्रिक कार सिर्फ़ 3 रुपये में 9.60 किलोमीटर की दूरी तय करेगी यानी 30 पैसे में एक किलोमीटर. यह पहले लांच हुई इलेक्ट्रिक कार रेवा की उत्तराधिकारी है. इस कार में रेवा से कहीं ज़्यादा ख़ूबियां हैं. यह एक बार चार्ज होने के बाद 180 किलोमीटर तक चलेगी. इसमें चार लोग बैठ सकते हैं और यह 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है. इस तरह शहर में चलाने के लिए यह एक बेहतरीन कार है. इसमें न तो प्रदूषण का ख़तरा है और न किसी तरह का शोर.

सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली कार

जापानी कार निर्माता कंपनी टोयोटा ने सबसे अधिकतम माइलेज देने वाली कार बनाई है. यह हाईब्रिड कार कंपनी ने पिछले दिनों टोक्यो में लांच की. यह कार अन्य कारों को ज़बरदस्त टक्कर देगी. इस कॉम्पैक्ट कार का नाम है अक्वा, लेकिन विदेशों में यह पायरस सी के नाम से जानी जाएगी. यह प्रति लीटर 35.4 किलोमीटर का माइलेज देगी. इससे पहले टोयोटा की ही कार पायरस ने 32 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज देने का रिकॉर्ड बनाया था. टोयोटा की योजना पहले साल में 12,000 कारें बनाने की है. कंपनी अधिक माइलेज देने वाली 10 नई कारें लांच करने की योजना भी बना रही है. टोयोटा मोटर ने अक्वा की क़ीमत रखी है, 16 लाख 90 हज़ार येन यानी 11,45,000 रुपये.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

अलविदा 2011

शीर्ष भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को भले ही विभिन्न टूनमिंट्स में हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन वह मानती हैं कि उनकी चोटों को देखते हुए 2011 उनके लिए अच्छा रहा. साइना ने हाल में दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि बीता साल (2011) शानदार था. 2011 उनके लिए भले ही चुनौतीपूर्ण रहा हो, क्योंकि उन्होंने टखने की चोट से वापसी की, लेकिन फिर चार फाइनल खेले और जापान ओपन के सेमी फाइनल तक पहुंचीं. हां, उन टूनर्मिंट्स में जीत दर्ज नहीं कर पाईं और फाइनल में हार गईं. इसलिए लोग सोचते हैं कि यह निराशाजनक है, लेकिन वह सचमुच अच्छा खेलीं. वह चीन में सत्र की अंतिम विश्व सुपर सीरीज के फाइनल में एक गेम से आगे थीं, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा. साइना कहती हैं कि वह अपने प्रयास से ख़ुश थीं. उन्होंने कहा, मैं इस बात से ख़ुश हूं कि मैंने सत्र का अंत अच्छे टूनमिंट से किया, जिसमें अच्छे मैच जीते और फाइनल मैच भी कठिन रहा. इसमें थोड़ी रणनीति की समस्या रही, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने सुपर सीरीज के फाइनल में अच्छा खेल दिखाया.

सानिया की मर्ज़ी

भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा का ध्यान 2012 की शुरुआत में साल के पहले ग्रैंड स्लेम ऑस्ट्रेलियन ओपन में बेहतर प्रदर्शन करने पर लगा हुआ है, जिसके लिए वह कड़ी मेहनत कर रही हैं. सानिया ने 2012 की अपनी योजनाओं के बारे में कहा, मेरा ध्यान ऑस्ट्रेलियन ओपन पर है, जिसके लिए मैं कड़ा अभ्यास कर रही हूं. हालांकि इस टूनर्मिंट के लिए अभी काफी समय है और इस दौरान कुछ भी हो सकता है. ख़ुद से जुड़े विवादों के बारे में पूछे जाने पर सानिया ने कहा कि वह लोगों की बातों की परवाह नहीं करती हैं और उन्हें जो अच्छा लगता है, वही करती हैं. सानिया ने कहा, मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देती कि लोग क्या कह रहे हैं. उनकी अपनी सोच है और मेरी अपनी. मैं कभी विवादों पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती कि मैं क्या पहनती हूं, किससे शादी करती हूं. पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से अपने निकाह के सवाल पर सानिया ने कहा कि संबंधों में नागरिकता कोई मायने नहीं रखती. यह दो लोगों की शादी की बात है, चाहे उनकी नागरिकता कुछ भी हो. दो लोगों के बीच नागरिकता कहां से आ जाती है.

गर्लफ्रेंड से बॉक्सिंग

फ्लायड मेवैदर आजकल अपनी गर्लफ्रेंड से बॉक्सिंग पर उतारू हैं. वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल वेल्टरवेट चैंपियन फ्लायड मेवैदर को पिछले दिनों लास वेगास की एक अदालत ने अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड पर हमला करने के आरोप में तीन महीने कैद की सज़ा सुनाई है. क्लार्क काउंटी कोर्ट की प्रवक्ता मैरी एन प्राइस के मुताबिक़, मुक्केबाज़ मेवैदर को अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड जोसी हैरिस के शोषण और उसके घर में लूटपाट करने का दोषी पाया गया. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि न्यायाधीश मेलिसा सारागोसा ने इस मुक्केबाज़ को छह महीने की सज़ा सुनाई, जिसमें 90 दिन उन्हें जेल में बिताने होंगे. अगर वह दोबारा गिरफ्तार होते हैं या अपनी सज़ा पूरी नहीं कर पाते तो उन्हें अपनी सज़ा के शेष तीन माह भी जेल में बिताने होंगे. इसके अलावा मेवैदर को 100 घंटे की समाजसेवा और घरेलू हिंसा के ख़िलाफ़ चलने वाले कार्यक्रम में एक साल तक हिस्सा लेना होगा. गत सितंबर में जोरदार प्रदर्शन करते हुए मेवैदर ने लास वेगास में वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल वेल्टरवेट टाइटल अपने नाम किया था.

जाते-जाते डोपिंग

राष्ट्रीय डोपिंग निरोधी संस्था (नाडा) ने प्रतिबंधित दवाओं के सेवन की दोषी पाए जाने पर एशियाई खेलों में दो स्वर्ण पदक जीतने वाली अश्विनी अकुंजी सहित छह एथलीटों पर एक वर्ष का प्रतिबंध लगाने की घोषणा की. नाडा के इस फ़ैसले के बाद अकुंजी और बाक़ी एथलीटों का लंदन ओलंपिक में हिस्सा लेने का सपना धरा रह गया. अकुंजी के अलावा मनदीप कौर, सिनी जोंस, मैरी तियाना थॉमस, प्रियंका पवार और जुआन मुर्मू पर प्रतिबंध लगाया गया. नाडा की अनुशासनात्मक समिति के प्रमुख दिनेश दयाल ने कहा कि इन खिलाड़ियों ने किसी अंतरराष्ट्रीय आयोजन के दौरान प्रतिबंधित दवाइयों का सेवन नहीं किया था, लिहाज़ा इनके ख़िलाफ़ थोड़ा नरम रवैया दिखाया गया है. इस तरह की ग़लती साबित होने पर कम से कम दो वर्ष का प्रतिबंध लगाया जाता है. नाडा के महानिदेशक राहुल भटनागर ने कहा कि ये एथलीट अपीलीय समिति के सामने इस सज़ा के ख़िलाफ़ अपील कर सकती हैं, लेकिन इन खिलाड़ियों के वकीलों का कहना है कि कोई भी अपील करने से पहले वे सज़ा से संबंधित नाडा के फ़ैसले की प्रति पर ग़ौर करना चाहेंगे.

खेल मंत्रालय का पेंच

वर्ल्ड हॉकी सीरीज (डब्लूएसएच) को खेल मंत्रालय ने ध्यान चंद स्टेडियम तो उपलब्ध करा दिया है, लेकिन इसे उसने निजी संस्था के आयोजन का दर्जा दिया है. स्टेडियम देने के बदले मंत्रालय कामर्शियल रेट पर किराया वसूलेगा.

हाल में खेल मंत्री अजय माकन ने मंत्रालय के अधीन आने वाले दिल्ली के स्टेडियमों को सरकारी स्कूल-कॉलेजों के लिए खोलने की घोषणा की. खेल आयोजन के लिए उन्हें महज़ एक हज़ार रुपये प्रतिदिन किराया चुकाना होगा, लेकिन इसकी भरपाई मंत्रालय कॉरपोरेट या निजी संस्थाओं के आयोजन पर मोटी वसूली के ज़रिए करेगा. डब्लूएसएच को 10 हज़ार रुपये प्रतिदिन किराए के अलावा बिजली, पानी, एसी, सफाई, पार्किंग एवं इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड का ख़र्च देना होगा. इसके अलावा लाइव कवरेज के लिए 25 हज़ार रुपये प्रतिदिन के साथ स्टेडियम में बैनर लगाने के भी चार्ज देने होंगे. माकन ने यह भी कहा कि ओलंपिक क्वालीफायर तक वह हॉकी इंडिया और आईएचएफ के विलय के मामले को तूल नहीं देना चाहते हैं. भारत ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर जाए, इसके बाद वह इस मामले में दख़ल देंगे. उन्होंने कहा कि विलय का विरोध आईओए और आईएचएफ ने किया, जबकि मंत्रालय आईएचएफ को निर्देश नहीं दे सकता है. नेशनल चैंपियनशिप कराने के लिए भी खेल संघों को पांच हज़ार रुपये प्रतिदिन किराया देना होगा. निजी स्कूलों-विश्वविद्यालयों को स्टेडियमों के लिए मोटी रकम देनी होगी.

लॉबिंग हरगिज नहीं: आनंद

हॉकी के जादूगर मेजर ध्यान चंद और क्रिकेट के बादशाह सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिए जाने की देशव्यापी बहस के बीच चार बार के शतरंज विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने कहा कि वह इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए कोई लॉबिंग नहीं करेंगे. आनंद ने केंद्र सरकार द्वारा खिलाड़ियों को भी भारत रत्न दिए जाने के फ़ैसले का स्वागत करते हुए कहा, यदि यह सम्मान मुझे मिलेगा तो मैं गर्व महसूस करूंगा, लेकिन मैं इसके लिए कोई लॉबिंग नहीं करूंगा. विश्व चैंपियन ने अपने प्रायोजक एनआईआईटी के कार्यक्रम में इस सम्मान के लिए किसी खिलाड़ी के नाम का सुझाव देने से भी इंकार कर दिया. उन्होंने कहा कि इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय का पैनल बेहतर जानता है. मालूम हो कि भारत रत्न के लिए ध्यान चंद और सचिन का नाम सबसे आगे है, जबकि भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआई) ने निशानेबाज़ अभिनव बिंद्रा के नाम की सिफारिश की है. कुश्ती जगत से गुरु हनुमान का नाम इस पुरस्कार के लिए उठा है. आगामी मई में मास्को में विश्व चैंपियनशिप के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी इजरायल के बोरिस गेलफांद के लिए आनंद ने कहा, उन्हें हराना काफी मुश्किल काम है. हम दोनों एक-दूसरे के खेल को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन यह एक मुश्किल मुक़ाबला होगा. हालांकि विशेषज्ञ कह रहे हैं कि मैं दावेदार हूं, लेकिन मैं इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

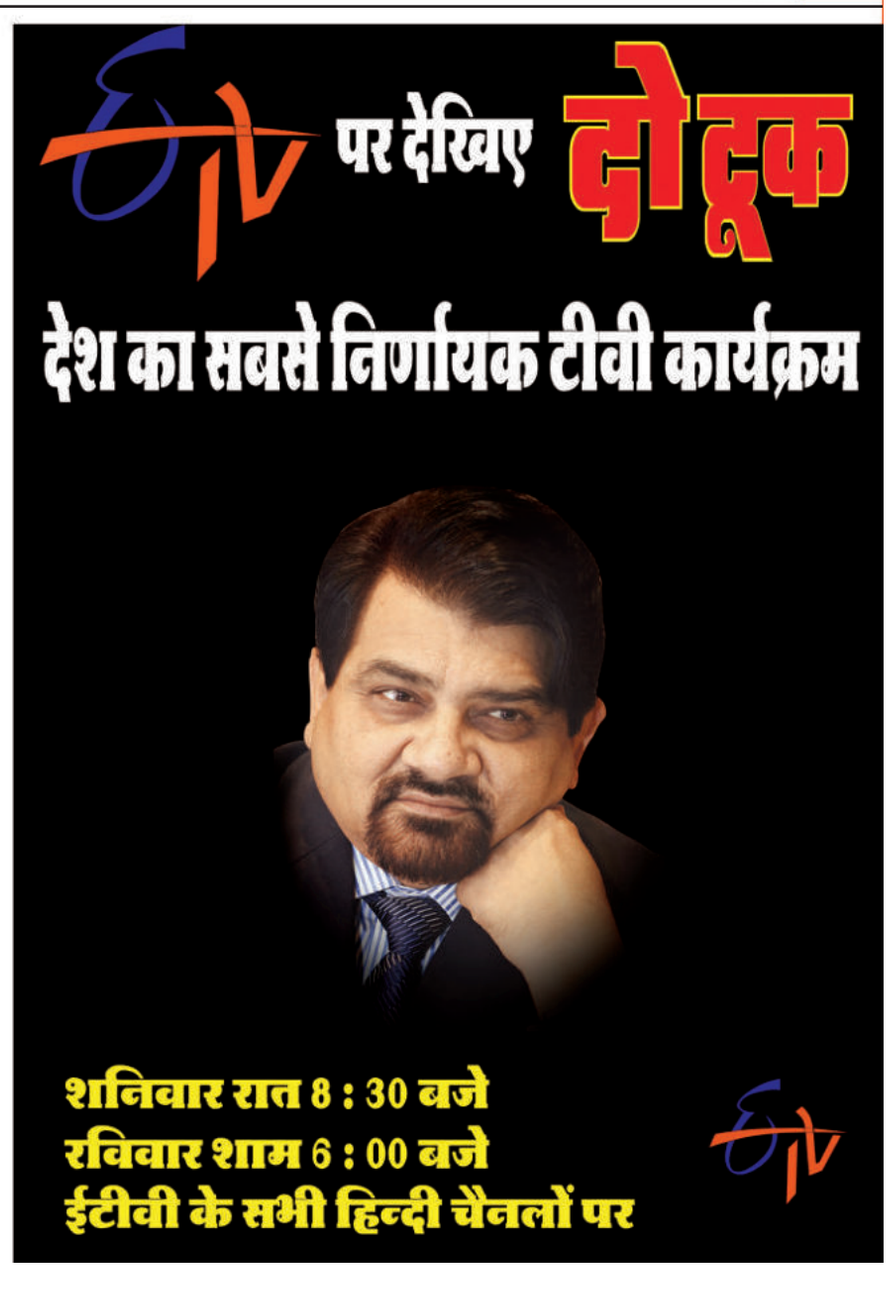

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 09 जनवरी–15 जनवरी 2012

डबल रोल का चांस मिलने पर कंगना बेहद एक्साइटेड हैं. वह कहती हैं, यह सच है कि मैं तनु वेड्स मनु के सीक्वल में डबल रोल कर रही हूं, लेकिन इस बारे में ज़्यादा बता नहीं सकती.

कंगना का डबल रोल

बॉलीवुड फिल्मों में हीरोइनों के हाथ स्ट्रांग रोल्स कम लगते हैं. ऐसे में कंगना को डबल रोल मिलना एक बड़ी बात माना जा रहा है. हालांकि सभी मान रहे हैं कि उनके टैलेंट पर शक नहीं किया जा सकता और वह इस चैलेंज में सफल रहेंगी. फ़िलहाल कंगना ख़ुशी मना रही हैं. दरअसल, तनु वेड्स मनु के सीक्वल में उन्हें डबल रोल के लिए साइन किया गया है. इंडस्ट्री के जानकार बताते हैं कि डबल रोल वाले ज़्यादातर चांस एक्टरों पर लिए जाते हैं. अमिताभ बच्चन, शाहरुख ख़ान, सलमान ख़ान, शाहिद कपूर, अनिल कपूर एवं गोविंदा जैसे अभिनेता ऐसे रोल बख़ूबी निभा चुके हैं. जबकि अभिनेत्रियां इस मामले में अभी पीछे हैं. अगर उनके डबल रोल की बात की जाए तो चालबाज़ में श्रीदेवी, संगीत में माधुरी दीक्षित, दुश्मन एवं कुछ खट्टी कुछ मीठी में काजोल, ओम शांति ओम एवं चांदनी चौक टू चाइना में दीपिका पादुकोण और वाट्स योर राशि में प्रियंका चोपड़ा जैसे गिने-चुने नाम हैं. डबल रोल का चांस मिलने पर कंगना बेहद एक्साइटेड हैं. वह कहती हैं, यह सच है कि मैं तनु वेड्स मनु के सीक्वल में डबल रोल कर रही हूं, लेकिन इस बारे में ज़्यादा बता नहीं सकती, लेकिन ओरिजनल फिल्म के मुक़ाबले यह सीक्वल बड़ा और बेहतर होने वाला है. लिहाज़ा मैं इसे अपने लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रही हूं. कंगना इन दिनों कृष-3 की शूटिंग भी कर रही हैं. फिल्म में कंगना का रोल एक सुपर गर्ल का है और इस रोल के लिए उन्होंने एक महीने में अपना वजन पांच किलो तक कम किया है.

सोनम अभय से ख़फ़ा नहीं

आपसी मनमुटाव की वजह से अलग हुए सोनम कपूर और अभय देओल एक बार फिर राजकुमार संतोषी की फिल्म में साथ नज़र आएंगे. इसे दोनों के लिए अच्छा माना जा रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सोनम अपने और अभय के बीच किसी भी तरह के मनमुटाव से इंकार करती हैं. उनका कहना है कि जो कुछ भी हुआ था, वह उनके डैड अनिल कपूर और अभय के बीच था. सोनम ने कहा, अभय बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं. ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा के वक़्त मैं उनके साथ थी. हालांकि उन्होंने इस बात से इंकार नहीं किया कि अपने डैड के ख़िलाफ़ किए गए ख़राब रिमार्क से उन्हें दुःख हुआ. बकौल सोनम, अभय का रिमार्क मुझे बहुत ख़राब लगा, लेकिन यह अभय और मेरे डैड के बीच की बात है. सोनम ने अपने करियर की शुरुआत से लेकर अब तक अलग-अलग तरह के रोल्स किए हैं. जहां उनकी डेब्यू फिल्म सांवरिया में ड्रामा नज़र आया, वहीं आई हेट लव स्टोरीज जैसी रोमांटिक मूवी भी उनके हिस्से में आई. अब वह एक्शन फिल्म प्लेयर्स में दिखेंगी. इस बारे में सोनम का कहना है कि उन्हें तरह-तरह के रोल करना अच्छा लगता है. उन्हें तब बेहद अच्छा लगता है, जब निर्देशकों को उनमें अलग-अलग रोल करने की काबिलियत नज़र आती है.

कृष का सीक्वल और शौर्या

राकेश रोशन कृष के सीक्वल के लिए अभिनेत्री तलाश रहे थे. काफी खोजबीन के बाद उनकी तलाश शौर्या चौहान पर जाकर ख़त्म हो गई. दरअसल, फिल्म में नेगेटिव रोल के लिए उन्हें एक हॉट एक्ट्रेस की तलाश थी और टीवी होस्ट एवं मॉडल शौर्या चौहान के रूप में उनकी यह तलाश पूरी हो गई. ग़ौरतलब है कि शौर्या साड्डा अड्डा से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली थीं, लेकिन अब उनकी डेब्यू फिल्म रितिक के साथ होगी. फिल्म से जुड़े सूत्रों के मुताबिक़, कृष टीम एक सेक्सी एक्ट्रेस चाहती थी, जो इस नेगेटिव रोल को कर सके. शौर्या इंडस्ट्री में स्टंट एवं ग्लैमरस गर्ल के तौर पर फेमस हैं. ज़ाहिर है, वह रोशन के लिए परफेक्ट एक्ट्रेस हैं. डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने उन्हें ज़्यादा वर्कआउट करने की सलाह दी है. यही वजह है कि इन दिनों वह जिमनास्टिक की ट्रेनिंग ले रही हैं. बहरहाल, शौर्या फिल्म में ग्लैम इफेक्ट दिखा पाती हैं या नहीं, यह तो रिलीज के बाद पता चलेगा.

प्रियंका का एलबम

ख़ुद की पब्लिसिटी कैसे करनी है, अगर यह आपको सीखना है तो प्रियंका चोपड़ा से मिल लीजिए. आजकल वह इसी काम में जोरों से लगी हुई हैं. वह जल्द ही अपना एक एलबम लांच करने वाली हैं. यही वजह है कि इन दिनों वह हर किसी के सामने अपने एलबम का गुणगान करने लगती हैं. हाल में जब वह कुणाल कोहली की फिल्म तेरी मेरी प्रेम कहानी की शूटिंग लंदन में कर रही थीं तो वह सेट पर न बैठकर अपने दोस्त गोल्डी बहल के पास चली जातीं और हर समय उनसे अपने एलबम पर ही डिस्कस करतीं. इसके अलावा वह सेट पर एक्टर अली जाफर को भी अपने एलबम के बारे में बता-बताकर पका चुकी हैं. यही हाल फिल्म बर्फी की शूटिंग के दौरान था, जहां वह रणबीर कपूर से घंटों अपने एलबम के बारे में बात करती रहती थीं. प्रियंका का कहना है कि उनके सारे दोस्त बहुत अच्छे हैं और वे उनके एलबम में दिलचस्पी ले रहे हैं. प्रियंका, सच तो यह है कि आपने अपना पीआर करने का अच्छा तरीक़ा ढूंढ निकाला है. अब देखना यह है कि आप सफल कितनी होंगी.

हाल में जब वह कुणाल कोहली की फिल्म तेरी मेरी प्रेम कहानी की शूटिंग लंदन में कर रही थीं तो वह सेट पर न बैठकर अपने दोस्त गोल्डी बहल के पास चली जातीं और हर समय उनसे अपने एलबम पर ही डिस्कस करतीं.

रॉबर्ट डी नीरो भारत आएंगे

हॉलीवुड स्टारों के भारत आने का सिलसिला लगातार जारी है. पिछले दिनों अनिल कपूर के गेस्ट बनकर आए टॉम क्रूज के बाद अबकी बारी रॉबर्ट डी नीरो की है. हालांकि नीरो के होस्ट अनुपम खेर हैं. ग़ौरतलब है कि अनुपम ने पिछले दिनों नीरो के साथ एक हॉलीवुड फिल्म में काम किया है. ख़बर है कि नीरो 2012 की शुरुआत में मुंबई आएंगे. इस दौरान वह अनुपम खेर के एक्टिंग इंस्टीट्यूट जाएंगे और वहां स्टूडेंट्स से मिलेंगे. हालांकि जब इस बारे में अनुपम खेर से बात की गई तो उन्होंने ज़्यादा जानकारी देने से इंकार कर दिया और कहा, मैं फ़िलहाल सिर्फ़ यही बता सकता हूं कि रॉबर्ट डी नीरो ने मुझसे मुंबई आने का प्रॉमिस किया है. ग़ौरतलब है कि रेजिंग बुल, गॉडफादर,टेक्सी ड्राइवर जैसी बेहतरीन फिल्मों के नायक रॉबर्ट डी नीरो से अनुपम पिछले कई दिनों से मिलना चाहते थे.

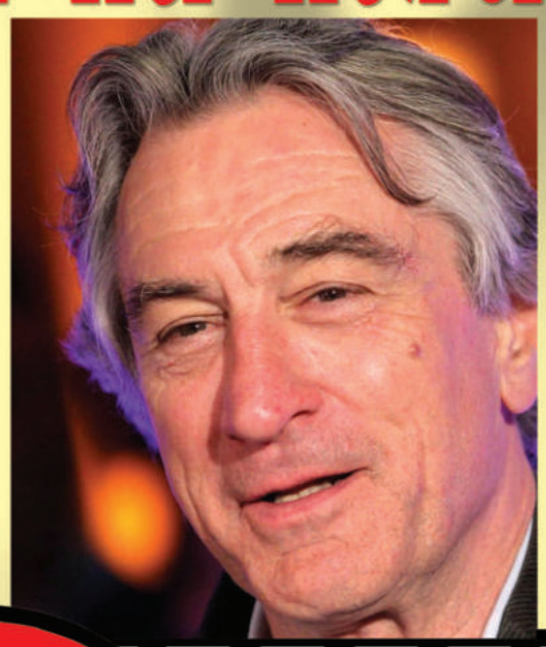

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

फिल्म प्रीव्यू

घोस्ट

मणिरत्नम, केतन मेहता एवं विशाल भारद्वाज से निर्देशन की एबीसीडी सीखने और फिल्म साथिया के दौरान शाद अली को टेक्निकल सपोर्ट देने वाली पूजा बतौर निर्देशक अपनी पहली फिल्म घोस्ट को लेकर खासी उत्साहित हैं. वह कहती हैं, मैं दर्शकों को डराने के लिए पूरी तरह तैयार हूं. यह मेरी पहली फिल्म है, इसलिए शुरुआत के तौर पर मैं छोटे बजट की फिल्म बनाना चाहती थी. घोस्ट का प्रोडक्शन बड़ा है, लेकिन मैं ऐसी कहानी से करियर शुरू करने की ख्वाहिशमंद थी, जिसके लिए कलाकार खोजने में दिक्कत न आए. सो, मैंने मंझोले कलाकारों के हिसाब से यह कहानी लिखी. लेकिन फिल्म का जोनर हॉरर ही क्यों? इस सवाल पर पूजा ने कहा कि इस सब्जेक्ट की मांग आज भी वैसी बनी हुई है, जैसी कुछ साल पहले थी. प्रदर्शन से पहले सस्पेंस फिल्म की स्टोरी बताना किसी फिल्म मेकर को अच्छा नहीं लगता, लेकिन पूजा बताती हैं, सयाली ने डॉ. सुहानी का कैरेक्टर प्ले किया है, शाइनी को आप डिटेक्टिव विजय सिंह की भूमिका में देखेंगे. सुहानी जिस अस्पताल में काम करती है, उसमें एक के बाद एक कत्ल हो रहे हैं.

ऐसे में विजय वहां केस सुलझाने आता है और फिर कहानी क्या रंग लेती है, यह आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा. अपनी नौकरानी से बलात्कार के आरोपी शाइनी को बतौर हीरो लेना पूजा के लिए आसान नहीं था, लेकिन भरत भाई द्वारा शाइनी का नाम सुझाने के बाद पूजा की समस्या हल हो गई. वह कहती हैं, मुझे लगता है कि यह भरत भाई का अपना अनुभव था, क्योंकि विवाद में आने के बाद हमारी इंडस्ट्री ने उनका साथ छोड़ दिया था. वैसे मुझे एक ऐसा एक्टर चाहिए था, जो अभिनय में उम्दा होने के अलावा अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक भी हो, इसलिए शाइनी के नाम का सुझाव एकदम सही लगा और मैंने उन्हें साइन कर लिया. मेगा बॉलीवुड प्रा. लि. और ओवल विलेज प्रा. लि. के बैनर तले बनी निर्माता भरत शाह की फिल्म घोस्ट जल्द ही प्रदर्शित होगी. फिल्म का लेखन-निर्देशन पूजा जतिंदर बेदी ने किया है, जबकि मुख्य भूमिकाएं शाइनी आहूजा, सयाली भगत, तेज सप्रू, दीपराज राणा, जूलिया ब्लिस और गुलशन राणा ने निभाई हैं. मशहूर कोरियोग्राफर संदीप सोपारकर पर आइटम नंबर फिल्माया गया है. गीत ए एम तुराज, कुमार, संदीप नाथ एवं सागर ने लिखे हैं, जिन्हें संगीतबद्ध किया है शारिब साबरी-तोषी साबरी ने.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

दिल्ली, 09 जनवरी–15 जनवरी 2012

www.chauthiduniya.com

विधान मंडल का शीतसत्र

विदर्भ की झोली में क्या आया

सिंचाई परियोजनाएं निधि आवंटन की राह ताक रही हैं. स्वास्थ्य सेवाएं लचर बनी हुई हैं. कुपोषण से मौतें जारी हैं. बिजली उत्पादन करने के बाद भी पूरा विदर्भ लोडशेडिंग से त्रस्त है. जनहित में जारी सभी सरकारी परियोजनाएं थम सी गई हैं. क़ानून- व्यवस्था के आंकड़ों में सुधार होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हत्या, डकैती, अपहरण के मामले बढ़ते ही जा रहे है. विधानसभा और विधान परिषद में विपक्ष की उपस्थिति लाचारगी पूर्ण रही और सरकार की दबंगता पूरे सत्र में साफ़ नज़र आई. विदर्भ के मुद्दे जब भी उठे सरकार ने उसे टालमटोल कर निपटा दिया.

प्रवीण महाजन

नागपुर में महाराष्ट्र का शीतकालीन सत्र ख़त्म हो गया. उसके बाद हमेशा कि तरह एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है कि इस शीतसत्र से आख़िरकार विदर्भ को क्या मिला. कहीं ऐसा तो नहीं कि यह शीतसत्र की रस्म अदायगी भर निभाकर आश्वासनों–वादों की ख़ैरात देकर मुंबई रवाना हो गई. यदि पूरे विधानमंडल सत्र की गतिविधियों का अवलोकन किया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि इस बार भी विदर्भ की झोली में 2000 करोड़ के आधे–अधूरे पैकेज व असिंचित खेती के लिए 10,000 करोड़ रुपये के मिशन की बात को छोड़ दिया जाए तो कुछ भी नहीं आया. किसानों की समस्या जस की तस बनी हुई है. प्रदेश में किसान आत्महत्या लगातार हो रही हैं. विदर्भ का बैकलॉग बढ़ता ही जा रहा है. वर्ष 2010 में संतरा उत्पादक के लिए घोषित मदद अब तक उन्हें नहीं मिली है. मिहान का सपना भी साकार होना बाकी है, सिंचाई परियोजनाएं निधि आवंटन की राह ताक रही हैं, स्वास्थ्य सेवाएं लचर बनी हुई हैं, कुपोषण से मौतें जारी हैं. बिजली उत्पादन करने के बाद भी पूरा विदर्भ लोडशेडिंग से त्रस्त है. जनहित में जारी सभी सरकारी परियोजनाएं थम सी गईं हैं. क़ानून– व्यवस्था के आंकड़ों में सुधार होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हत्या, डकैती, अपहरण के मामले बढ़ते ही जा रहे है. विधानसभा और विधान परिषद में विपक्ष की उपस्थिति लाचारगीपूर्ण रही और सरकार की दबंगता पूरे सत्र में साफ़ नज़र आई. विदर्भ के मुद्दे जब भी उठे सरकार ने उसे टालमटोल कर निपटा दिया.

दो सप्ताह चले विधानमंडल के शीत सत्र में मात्र 64 घंटे कामकाज हुआ. बाकी समय राजनीतिक हंगामे की भेंट चढ़ गया. सरकार के अनुसार विधानसभा की कुल 11 बैठकें हुईं , उनमें कामकाज हुआ 52 घंटे. बर्बाद हुए 13 घंटे. रोज़ के सरकारी कामकाज में ख़र्च हुए चार घंटे 45 मिनट. पांच विभागों से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा हुई 3 घंटे 33 मिनट. विधेयक पुनर्स्थापित हुए 17 और 14 विधेयक पारित हुए. विधानसभा सदस्यों द्वारा तारांकित प्रश्न पूछे गए 9151, जिनमें से 752 प्रश्न स्वीकृत किए गए. उसमें मात्र 36 प्रश्नों का मंत्रियों ने सदन के अंदर उत्तर दिया. 11 अल्प सूचनाओं सदन को मिली. इसी तरह विधान परिषद की कुल 11 बैठकें हुईं, जिसमें 67 घंटे 40 मिनट कामकाज हुआ. 5 घंटे 15 मिनट का वक्त विविध कारणों से बेकार गया. रोज़ के सरकारी कामकाज में 5 घंटे 45 मिनट का वक्त लगा. तारांकित प्रश्न पूछे गए 3527, जिनमें से सिर्फ़ 2979 को मान्य किया गया. उसमें भी सिर्फ़ 1256 को स्वीकृत किया गया. सदन के अंदर मंत्रियों ने मात्र 55 प्रश्नों का उत्तर दिया. लक्ष्यवेधी सवाल किए गए 1121, जिनमें से स्वीकृत किए गए 214. सदन के अंदर 26 विषयों पर चर्चा हुई. 136 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिसमें 41 को स्वीकार किया गया. इसके अलावा इस सत्र में मात्र 13 विधेयक पारित हुए, लेकिन इसके आयोजन और मुंबई से आए मेहमानों पर प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से क़रीबन 300 करोड़ रुपये जनता के ख़र्च हो गए, लेकिन इससे विदर्भ को क्या लाभ हुआ. इस सत्र के दौरान सवा सौ मोर्चों के निकलने से नागपुर का यातायात बाधित हुआ, जिसके कारण जनता को आर्थिक–मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा. इसका मतलब हुआ कि करोड़ों रुपये ख़र्च करने के बाद भी ख़ास उपलब्धियां हासिल नहीं हुईं.

शीतसत्र के दरम्यान एक बात साफ़ नज़र आई कि नगर पालिका चुनाव के परिणामों के पश्चात जहां सरकार की दबंगता बढ़ी, वहीं विपक्ष बिखरा हुआ नज़र आया. विपक्ष ने सरकार पर जितने तीर छोड़े सब हवा में तैरते हुए नज़र आए. बार–बार सदन का स्थगन करा कर सरकार विपक्ष के सारे मुद्दे ठंडे बस्ते में डलवाने में क़ामयाब रही. कभी सरकार के मंत्री सदन से ग़ायब नज़र आए तो कभी विपक्षी दल के नेता. नागपुर से संबंधित जितने मुद्दे विपक्षी विधायकों ने उठाया, सरकार ने उनको स्थानीय महानगर पालिका के ऊपर ढ़केल दिया. इसके अलावा सरकार कई मुद्दों में विपक्ष के बीच मतभेद पैदा करने की कूटनीति का अमल करके उसे कमज़ोर करती रही और अपनी मुश्किलों से निजात पाती रही. सत्र के प्रारंभ मे विपक्ष के जो नेता यह ज़ोर–शोर से घोषणा कर हुंकार भरते रहे कि कपास, धान, सोयाबीन उत्पादकों को उचित दाम दिलाकर ही दम लेंगे, उनका वह ज़ोर सदन के अंदर नज़र नहीं आया. सरकार ने शुरू से ही दबंगता दिखाते हुए विपक्ष के विधायकों को निलंबित करने की रणनीति अपनायी और विपक्ष अपनी लाचारी पेश करते हुए क्षमा याचना करता नज़र आया. यदि यह कहा जाए कि विपक्ष पूरे सत्र में बे–असर साबित हुआ तो अतिश्योक्ति नहीं होगी, क्योंकि कपास, धान और सोयाबीन और बेलगांव के मुद्दे को छोड़ दिया जाए तो अन्य किसी भी मुद्दे पर विपक्ष एकजुट नज़र नहीं आया. इन दोनों मुद्दे में भी सरकार ही विपक्ष पर भारी पड़ती दिखाई दी. दूसरी ओर विदर्भ के मुद्दे पर विदर्भ के जन प्रतिनिधि अपनी पार्टी के खांचों से बाहर नहीं निकल पाए. इसलिए जब भी विदर्भ से संबंधित मुद्दा सदन में उठा वह प्रश्न बन कर ही रह गया. विदर्भ के अनुशेष का मुद्दा उठा तो चर्चा में वह सिंचाई तक ही सिमट कर रह गया. मिहान का मुद्दा उठा ही नहीं. मिहान को सरकार ने भी अधिक तूल न देना ही उचित समझा. हालांकि विधानमंडल के बाहर एक–दो कार्यक्रमों में मिहान का ज़िक्र मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने ज़रूर किया. विधायक देवेंद्र फड़णवीस ने पृथक विदर्भ पर प्रभावी भाषण दिया, लेकिन उन्हें अन्य किसी विदर्भवासी का साथ नहीं मिला. बेलगांव में शिवसेना ने कर्नाटक सरकार को बर्ख़ास्तगी की मांग कर भाजपा से दूरी बढ़ा ली तो सरकार ने उसे साथ लेकर सदन में बेलगांव प्रस्ताव पास करा लिया. शिवसेना बहिष्कार कर बाहर जा बैठी. लोक निर्माण मंत्री छगन भुजबल, हर्षवर्धन पाटिल, गणेश नाईक द्वारा कारपोरेट घरानों से करोड़ों लेने के मामले में भी सरकार को विपक्ष नहीं घेर पाया. इंदू मिल को लेकर सदन में सरकार ने जो कहा वह विपक्ष ने चुपचाप सुना. बोगस शिक्षा संस्थाओं और बोगस विद्यार्थियों पर विपक्ष चुप्पी साधे रहा.

सदन में विपक्ष के बिखराव से उत्साहित सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए नगरपालिका चुनाव परिणाम संजीवनी साबित हुआ है. विपक्ष के पास जहां इस शीतसत्र के समाप्त होने के बाद जनता को बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है, वहीं सरकार अपनी उपलब्धियां बखान करना शुरू कर दिया है. सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि उसने अब तक के सबसे बड़े किसान पैकेज की घोषणा की है. इससे 81 लाख हेक्टेयर खेती को लाभ होगा. किसानों को राहत मिलेगी. हालांकि इस आधे–अधूरे पैकेज से किसानों को न अधिक मदद मिलने वाली और ना ही कृषि में कोई सुधार होने की संभावना है. सरकार ने सत्र के अंतिम दिन ज़रूर पैकेज की शर्तों को ढीला किया पर दूसरी शर्तें भी लाद दी हैं. अब पैकेज के तहत किसान को 4000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मात्र दो हेक्टेयर के लिए मदद राशि दी जाएगी फिर वह चाहे कितने ही हेक्टेयर पर फसल क्यों न लगाई हो. दूसरी उपलब्धि के रूप में सरकार असिंचित (कोरडबाहु) खेती के लिए 10,000 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है, लेकिन एक तो इसका लाभ मिलने पर ही पांच साल लग जाएंगे. दूसरी बात यह है कि विदर्भ का अनुशेष ही 76000 करोड़ रुपये का बकाया है तो 10,000 करोड़ से विदर्भ के आत्महत्या कर रहे किसानों का उद्धार कैसे होगा? इसका मतलब यह है कि असिंचित क्षेत्र को सिंचित क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए सरकार ने एक टुकड़ा डाला है. यह महज कोरी घोषणा है, क्योंकि सरकार की बात को ही सही माना जाए तो उसका कहना है कि कपास, धान और सोयाबीन उत्पादकों के लिए जिस 2000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है उसे पूरा करने के लिए अन्य विकास योजनाओं की निधि से कटौती की जाएगी. फिर दस हज़ार करोड़ रुपये की व्यवस्था राज्य सरकार कैसे करेगी? इसका तो यही अर्थ हुआ कि यह शीतसत्र भी रस्म अदायगी बन कर ही रह गया है. विदर्भ की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं अधूरी की अधूरी रह गई हैं.

इस सत्र की एक ही उपलब्धि गिनाई जा सकती है. वह है उपमुख्यमंत्री अजीत पवार द्वारा विदर्भवासियों व उनके जनप्रतिनिधियों को आईना दिखाना. अजीत पवार ने विदर्भ के औद्योगिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े होने का सारा दोष यहां की जनता पर मढ़ दिया है. विदर्भ के जनप्रतिनिधियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है. उनका स्पष्ट कहना था कि जब यहां के जनप्रतिनिधि यहां के मतदाताओं की अपेक्षानुसार विकास नहीं करते हैं तो बार–बार उन्हीं को क्यों चुनते हैं? आश्चर्य की बात यह है कि अजीत पवार के इस सवाल का विदर्भ के किसी भी नेता ने पलट कर जबाव नहीं दिया. इसलिए जब सदन में पृथक विदर्भ का मुद्दा उठा तो सारे विदर्भवादी (सभी दलों के) नेता अपने स्वार्थ के खोल में घुस गए. यदि विदर्भ के नेताओं में राजनीतिक सामंजस्य होता तो शीतसत्र का परिणाम कुछ और होता, लेकिन विदर्भ के किसान, जनता न केवल सरकार से निराश है बल्कि वह विपक्षी दलों के अकार्यक्षमता से भी नाखुश है. इसलिए विपक्ष यदि अभी नहीं संभला तो उसे आगे और जनता की नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है. आने वाले दो माह में महानगर पालिका और ज़िला परिषद चुनाव की आहट आने लगी है.

क़रार पर कैंची

जब महाराष्ट्र का निर्माण हुआ था और मध्यभारत की राजधानी का वैभव बरकरार रखने के लिए वर्ष 1960 में जो नागपुर क़रार हुआ था, उसे सरकार ने न केवल भूला दिया है, बल्कि उस क़रार को विपक्षी नेता भी भूल गए हैं. क़रार में यह तय हुआ था कि 6 सप्ताह के शीतसत्र में सिर्फ़ विदर्भ के मसलों पर ही ज़ोर दिया जाएगा, लेकिन कुछ सालों बाद ही विदर्भ में होने वाले शीतसत्र के समय पर निरंतर कटौती होती चली गई. अब मात्र यह सत्र दो सप्ताह की अवधि में सिमट कर रह गया है. कहने को दो सप्ताह का होता है, लेकिन देखा जाए तो मात्र 10 दिन ही विधानमंडल चलता है. उस पर भी राजनीतिक हंगामे में समय अधिक बर्बाद होता है. इसके साथ ही शीतसत्र में विदर्भ के मसलों को टाल दिया जाता है. अब इस क़रार की सार्थकता को लेकर विदर्भ की जनता बेक़रार हो उठी है. ऐसे में यह सवाल उठने लगा है कि नागपुर में शीतसत्र के आयोजित करने का आख़िर क्या औचित्य है?

feedback@chauthiduniya.com

सुनवाई में होने वाली देरी की वजह से भी राज्य की अदालतों में प्रलंबित प्रकरणों की संख्या बढ़ती जा रही है.

कई मामलों में यह बात भी सामने आयी है कि साहूकार ने गिरवी रखी गई ज़मीन धोखे से लिखाए बिक्री पत्र के आधार पर लाखों रुपये में बेच दिया और किसान को इसका पता भी नहीं चला.

महाराष्ट्र हलचल

बुलढाना ज़िला नागरिक मंडल के वार्षिक सम्मेलन में विधायक राहुल बोंद्रे, शिवसेना विधायक डॉ. संजय रायमुलकर, पूर्व मंत्री व राकांपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश बंग, विधायक डॉ. राजेंद्र शिंगणे, विधायक संचेती, विधायक डॉ. रंजीत पाटील, एड. पुरुषोत्तम पाटील, भैयालाल ठाकुर और भाऊ दांदडे मौजूद रहे.

नागपुर स्थित कॉटन मार्केट धर्मशाला परिसर में कर्मयोगी स्व. भाऊराव मोहोड की प्रतिमा का अनावरण किया गया. इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण. उनके साथ हैं विधायक सुनील केदार, वरिष्ठ पत्रकार उमेश चौबे, पालकमंत्री शिवाजी राव मोघे, सांसद विलास मुत्तेमवार, राज्यमंत्री राजेंद्र मुलक व अन्य.

विकलांगों की प्रलंबित मांगों का निवेदन स्वीकार करते मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण. उनके साथ हैं पालकमंत्री शिवाजी राव मोघे, मंत्री प्रा. लक्ष्मणराव ढोबले और राज्यमंत्री राजेंद्र मुलक.

नागपुर ज़िला परिषद की नई प्रशासकीय इमारत का मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के हाथों उद्घाटन किया गया. इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री मुकुल वासनिक, पालकमंत्री शिवाजी राव मोघे, मंत्री जयंत पाटील, मंत्री अनिल देशमुख और ज़िला परिषद उपाध्यक्ष नितिन राठी.

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले के जन्मदिन पर मुंबई के हिंदमाता में स्थित कमला मेहता अंध शाला के बच्चों को पावभाजी और मिठाई वितरित करते पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एड. दयानंद मोहिते व अन्य कार्यकर्ता.

अमरावती ज़िले में आयोजित संतरा परिषद को संबोधित करते उप मुख्यमंत्री अजीत पवार. मंच पर पूर्व विधायक हर्षवर्धन देशमुख, विधायक अनिल बोंडे, डॉ. विजय कुमार गावित और डॉ. सुधीर कुमार गोयल भी मौजूद रहे.

चन्द्रपुर ज़िले के विसापुर में आयोजित रक्त जांच शिविर में अपने ख़ून की जांच कराने के लिए कतार में खड़ीं महिलाएं.

लाखों मामले लंबित
लोगों को न्याय मिलने का इंतज़ार

आलोक मिश्रा

समय पर न्याय न मिल पाना कितना कष्टदायक होता है? इसकी पीड़ा वही जानता है, जो न्याय की आस में सरकारी दफ़्तरों और अदालतों के चक्कर काटते-काटते न केवल अपनी उम्र गुज़ार देता है, बल्कि अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई भी अदालत में वकीलों को फ़ीस देते गंवा देता है. इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. यहां तक की कई मामलों में फ़रियादी की न्याय की आस में मौत भी हो जाती है और उसकी संतानों को अदालती चक्कर विरासत में मिल जाती है. यही विडंबना है भारतीय न्याय व्यवस्था की. अदालतों में जजों की कमी एक बड़ी समस्या है. नतीजतन अदालतों में मुक़दमे का बोझ बढ़ता ही जा रहा है.

महाराष्ट्र में पिछले कुछ वर्षों की तुलना में फ़ैसलों में हो रही देरी और निर्णय न हो पाने से प्रलंबित मामलों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है. यदि राज्य अपराध अन्वेषण विभाग द्वारा महाराष्ट्र में अपराध 2010 रिपोर्ट को मानें तो पुलिस द्वारा अदालत के समक्ष पेश दो मामलों में एक का ही फ़ैसला हो पाता है. इस लिहाज़ से मामलों में फ़ैसला होने का अनुपात महज़ 2:1 है. रिपोर्ट के अनुसार राज्य की विविध अदालतों में वर्ष 2010 में चार प्रतिशत विविध मामलों की वृद्धि दर्ज की गई है. वर्ष 2010 में 27 लाख 98 हज़ार 495 विविध मामले राज्य की अदालतों में प्रलंबित हैं और इनसे जुड़े पक्षकारों को न्याय मिलने का इंतज़ार है. उक्त आंकड़ा महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या का दो प्रतिशत के क़रीब है. पिछले वर्ष के प्रलंबित मामलों के साथ ही 14 लाख 24 हज़ार 130 प्रकरण सुनवाई के लिए अदालत के सामने आए. इनमें से ही 13 लाख 27 हज़ार मामले प्रलंबित हैं यानी सुनवाई के लिए आए मामलों में से 93.2 प्रतिशत मामले प्रलंबित हैं. इसका मतलब यह है कि अदालतों में सुनवाई के लिए जाने वाले प्रकरणों में फ़ैसला होने की गति धीमी हुई है. अपराध अन्वेषण की रपट में कहा गया है कि सोलापुर (ग्रामीण) में सबसे अधिक 99.5 प्रतिशत मामले प्रलंबित हैं. उसके बाद लातूर का नंबर आता है, जहां 97.9 और पुणे (शहर) में 97.9 प्रतिशत मामले प्रलंबित हैं. रिपोर्ट से यह भी खुलासा हुआ है कि पुलिस द्वारा मामलों की जांच कर आरोप पत्र अदालतों में पेश करने के कार्य में जहां तेज़ी आई है, वहीं अदालतों में मामलों की भरमार होने से निर्णय आने में देरी होती है. इससे यह ज़ाहिर होता है कि पुलिस विभाग द्वारा मामलों में की जा रही जांच और अदालती प्रक्रिया के बीच तालमेल का अभाव है. यही वजह है कि अदालतों में आने वाले मामले और उनमें होने वाले फ़ैसले के बीच 2:1 का अनुपात रिपोर्ट में दर्शाया गया है. इसके साथ ही महाराष्ट्र में वर्ष 2009 में विविध मामलों में आरोपियों को सज़ा होने का प्रतिशत 9.6 था, वहीं वर्ष 2010 में घट कर मात्र 9 प्रतिशत रह गया. इस विषय में राज्य अपराध अन्वेषण विभाग के अपर पुलिस महासंचालक अशोक धिवरे ने भी चिंता ज़ाहिर की है. वह बढ़ते प्रलंबित मामलों को गंभीर समस्या मानते हैं, जिससे लोगों को न्याय मिलने में देरी होती है. राज्य की अदालतों में सुनवाई के पश्चात जितने प्रकरणों पर निर्णय सुनाया गया है उस पर विचार करने से जो तस्वीर सामने आती है, उसमें पति-पत्नी व आपसी रिश्तेदारों में छल-कपट, झगड़ों के मामले 2.1 प्रतिशत, जलाने के 3.8 प्रतिशत, दुर्घटना में घायल होने के 4.4 प्रतिशत, लड़ाई-झगड़े में हुई मौत के मामले 4.4 प्रतिशत, यौन उत्पीड़न के 5.1 प्रतिशत, डकैती के 5.2 प्रतिशत, अपहरण व भगा ले जाने के 6.1 प्रतिशत, दंगा संबंधी 6.5 प्रतिशत, दहेज के प्रकरण में हत्या 6.7 प्रतिशत, विश्वासघात 7.4 प्रतिशत और विनयभंग (छेड़छाड़) के 8.5 प्रतिशत ही फ़ैसले हुए हैं, जो किसी भी दृष्टि से संतोषजनक नहीं हैं. इसके साथ ही राज्य में महिलाओं के प्रति बढ़ रहे आपराधिक प्रकरणों के हिसाब से देखा जाए तो उन पर हो रहे अत्याचार के 91.71 प्रतिशत मामले राज्य की विविध अदालतों में प्रलंबित हैं. यह जानकारी भी अपराध अन्वेषण विभाग की रिपोर्ट में दी गई है. आरोपों के सिद्ध न होने के लिए रिपोर्ट में जिन कारणों को बताया गया है, उनमें प्रकरणों को सिद्ध करने के लिए ठोस सबूतों का अभाव, अदालत में आरोप पत्र पेश किये जाने में लगने वाला समय व उनके दोषपूर्ण होने, पुलिस विभाग और सरकारी वकील के कार्य को लेकर समन्वय न होना, प्रलंबित प्रकरणों के संबंध में जांच करने वाले अधिकारी के तबादले आदि की वजह से भी राज्य की अदालतों में प्रलंबित प्रकरणों की संख्या बढ़ती जा रही है. न्यायालयीन कर्मचारियों की संख्या में आबादी व प्रकरणों के हिसाब से कमी होना भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है, लेकिन इन कारणों की वजह से लाखों लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता है. कई बेगुनाह जेल के कठघरे के पीछे यातनामय जीवन गुज़ारने को मजबूर रहते हैं. विधि विशेषज्ञों की मानें तो उनकी एकमत से राय है कि न्याय व्यवस्था में व्यापक सुधार किया जाए. न्यायालयीन व्यवस्था और पुलिस विभाग के मध्य समन्वय स्थापित करने की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है.

feedback@chauthiduniya.com

करोड़ों का घोटाला
नागपुर मनपा आरोपों के घेरे में

मयूर रंगारी

नागपुर शहर में महानगर पालिका द्वारा चलाई जा रही स्टार बस सेवा विवादों के घेरे में फंस गई है. कम से कम 200 करोड़ रुपये का घोटाला होने की जानकारी चौथी दुनिया को मिली है. इसमें केवल स्टार बस को ऑपरेट कर रही वंश निमय इंफ्रा प्रोजेक्ट लि. द्वारा मनपा को रॉयल्टी देने का ही मामला नहीं है, बल्कि स्टार बस के कर्मचारियों से भी कंपनी द्वारा करोड़ों रुपये ऐंठने की बात सामने आई है. यह मामला इतना बड़ा है कि इसमें मनपा की सत्ता संभाल रहे भाजपा–शिवसेना के हाथ काले होने की बात कही जा रही है. राज्य परिवहन महानिगम की शहर बस सेवा को बंद कर 9 फरवरी 2007 से मनपा ने वंश निमय कंपनी के साथ मिलकर शहर में स्टार बस सेवा शुरू की थी. मनपा और कंपनी के बीच हुए शुरूआती क़रार के अनुसार बड़ी बस की 3750 रुपये और छोटी बस की 2387 रुपये रॉयल्टी तय की गई थी. उस समय कंपनी शहर में 230 बसें चला रही थीं. वर्ष 2010 तक कंपनी ने मनपा को इन बसों पर कितनी रॉयल्टी दी यह तो मनपा प्रशासन ही बता सकता है, लेकिन इसके बाद हुए सुधारित क़रार ने एक बड़े घोटाले को जन्म दे दिया है.

मनपा ने भरा बसों का पैसा

केंद्र सरकार के जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनरुत्थान अभियान (जेएनएनयूआरएम) के तहत नागपुर मनपा को शहर बस सेवा के लिए 240 बसें दी गईं. इसके लिए मनपा ने 70 फ़ीसदी और वंश कंपनी ने 30 फ़ीसदी शुल्क अदा किया. ग़ौरतलब है कि इससे पूर्व वंश कंपनी जो 230 बसें चला रही थीं, उसका पूरा शुल्क कंपनी ने ही अदा किया था. साथ ही इस पर लगने वाले अलग–अलग टैक्स भी कंपनी ने ही दिए थे. फिर जेएनएनयूआरएम के तहत मिली बसों के शुल्क का 70 फ़ीसदी के साथ–साथ अलग–अलग टैक्स मनपा ने क्यों अदा किए? मार्च 2010 में कंपनी और मनपा के बीच हुए सुधारित क़रार पर यदि नज़र दौड़ाई जाए तो पाएंगे कि पूरा क़रार कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया है. बस ख़रीदने के लिए मनपा ने कंपनी को राशि दी, लेकिन रॉयल्टी को नहीं बढ़ाया गया. इतना ही नहीं नए क़रार में तय किया गया कि एक बस पर तय फ़ायदा होने पर ही मनपा को कंपनी उस बस पर 3750 रुपये रॉयल्टी देगी. यदि फ़ायदा अधिक होता है तो रॉयल्टी अधिक दी जाएगी, लेकिन यदि फ़ायदा कम हुआ तो रॉयल्टी में भी कमी आएगी. क़रार के अनुसार हर बस की रोज़ जानकारी कंपनी को मनपा को देनी थी, जिसके आधार पर रॉयल्टी तय होनी थी, लेकिन क़रार के बाद से कंपनी ने मनपा को किसी भी बस की जानकारी नहीं दी है. ऐसे में रॉयल्टी का तो सवाल ही नहीं उठता. विपक्ष ने इससे मनपा को लगभग 95 करोड़ रुपये का घाटा होने का आरोप लगाया है, लेकिन जानकारों की मानें तो यह आंकड़ा इससे कहीं अधिक है.

अमरावती मनपा फ़ायदे में

इससे उलट अमरावती मनपा ने शहर बस सेवा के संबंध में जो क़रार किया है, उसमें प्रति किलोमीटर 1.10 रुपये के अनुसार रॉयल्टी तय की गई है. यानी एक बस रोज़ जितने किलोमीटर का सफ़र तय करेगी, उसके अनुसार कंपनी को 1.10 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से मनपा को रॉयल्टी देनी होगी. बताया जाता है कि केवल 35 बसों पर ही अमरावती मनपा को 40 लाख रुपये रॉयल्टी के रूप में मिले है, लेकिन नागपुर मनपा को 400 से अधिक बसों पर भी इतनी रॉयल्टी नहीं मिल पाई है. बताया जाता है कि इन 400 से अधिक बसों में से नागपुर शहर की सड़कों पर केवल 230 बसें ही शहर में दौड़ रही हैं.

बनी समिति, भ्रष्टाचार के मुद्दे को छोड़ा

नागपुर शहर के नगरसेवक रमन पैगवार ने स्टार बस में हुए घोटाले के संबंध में सबसे पहले आवाज़ उठाई. मामला तूल पकड़ता देख महापौर अर्चना डेहनकर ने भाजपा के पूर्व शहर अध्यक्ष व नगरसेवक अनिल सोले की अध्यक्षता में 15 सर्वदलीय नगरसेवकों की एक जांच समिति 11 जनवरी 2011 को बनाई. समिति ने 30 नवंबर 2011 को अपनी रिपोर्ट पेश की. हैरत की बात यह है कि इसमें कहीं भी क़रार से हुए आर्थिक भ्रष्टाचार की बात नहीं कही गई है. समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कंपनी ने अच्छी सेवा नहीं दी. आज तक कोई भी सुधार नहीं किए हैं, क़रार की शर्तों को पूरा नहीं किया है. इसलिए समिति ने ऑपरेटर को बदलने की सिफ़ारिश की है. ग़ौर करने वाली बात यह है कि जिस भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए समिति का गठन किया गया था, उस मुद्दे को समिति ने छूआ तक नहीं है. पूरी जांच बस ऑपरेटर कंपनी द्वारा दी जा रही सेवाओं पर ही केंद्रित रही. समिति की रिपोर्ट पर राकांपा नेता वेदप्रकाश आर्य और विपक्षी नेता व पूर्व महापौर विकास ठाकरे ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं. रिपोर्ट से साफ़ ज़ाहिर होता है कि भाजपा–शिवसेना पूरी तरह से ऑपरेटर को बचा रही है.

सीबीआई जांच की मांग

इस मुद्दे को सबसे पहले सामने लाने वाले नगरसेवक रमन पैगवार, राकांपा के नगरसेवक वेदप्रकाश आर्य और पूर्व महापौर विकास ठाकरे की मानें तो इस पूरे मामले में भाजपा–शिवसेना के हाथ रंगे हुए हैं. आर्य ने तो इस पूरे मामले की सीबीआई जांच तक की मांग कर डाली है. तीनों का कहना है कि पहले कंपनी ने जो बसें ख़रीदी उसका पूरा पैसा उसी ने अदा किया. इंश्योरेंस, आरटीओ का टैक्स, सर्विस टैक्स भी कंपनी ने ही अदा किया था, लेकिन जेएनएनयूआरएम के तहत मिली बसों की 70 फ़ीसदी राशि और टैक्स मनपा ने भरा, आख़िर क्यों? रॉयल्टी की शर्तों को क्यों बदला गया? क़रार के बाद अब तक कितनी रॉयल्टी मिली? किस तरह रॉयल्टी वसूली गई और कंपनी ने इस संबंध में क्या–क्या जानकारी दी? इसे मनपा की आमसभा में रखने की भी मांग की.

ऊंचे लोगों से पहचान

इसमें कोई शक नहीं कि वंश निमय कंपनी और मनपा के बीच हुए सुधारित क़रार में काफी गड़बड़ियां हुईं. विपक्ष ने पूरे मामले को बड़े पैमाने में उठाया. महापौर ने जांच समिति भी बनाई. उसमें भी कंपनी की सेवाओं को अपर्याप्त बताया गया. स्टार बस के चालक–परिचालकों ने अब तक कई ज्ञापन राज्य के मंत्रियों से लेकर पालकमंत्री आदि को दिए. उन पर हो रहे अत्याचार के सबूत भी दिए. सब कुछ साफ़ होने के बाद भी कंपनी के संचालक अजय ढवंगले के ख़िलाफ़ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. समिति ने भी केवल क़रार रद्द करने के लिए कहा है, जबकि बसों की हुई ख़स्ता हालत व उनकी मरम्मत के लिए कंपनी पर जुर्माना लगाने की कोई बात नहीं कही गई है. ऐसे में सवाल उठता है कि कंपनी पर इतनी मेहरबानी किस लिए? मनपा के वरिष्ठ नगरसेवकों (जिनमें भाजपा के भी नेता शामिल हैं) ने बताया कि कंपनी संचालक ढवंगले की काफ़ी ऊंचे लोगों से पहचान है. स्टार बस के चालक–परिचालकों ने पिछले दिनों अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की. बताया जाता है कि हड़ताल ख़त्म करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी के महल स्थित घर (वाड़ा) से फोन आया. स्टार बस मनपा की. ऐसे में मामला सुलझाने के लिए मनपा को आगे आना चाहिए था. इसमें गडकरी का घर बीच में कैसे आ गया? ऐसा एक बार नहीं बल्कि दो बार हुआ है. ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि इतने छोटे मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर से फोन आया.

feedback@chauthiduniya.com

बीती ताही बिसार दे आगे की सुध लेउ

ये क्या हो रहा है...

पुराना साल विदा हो गया. नया साल 2012 का स्वागत दुनिया भर में लोगों ने किया. सभी की आशा होती है कि नव वर्ष में देश के अंदर कुछ नया होगा. कुछ नया परिवर्तन होना भी चाहिए. परिवर्तन से ही कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती है, लेकिन न जाने हमारे राज्य की व्यवस्था को क्या हो गया है कि वह कोई बड़ा परिवर्तन करने का साहस ही नहीं कर पाती है? जनता सत्ताधीशों के भरोसे रहती है और सोचती है जो भी परिवर्तन करना है वह सरकार करेगी? लेकिन अपने अंदर कोई नया परिवर्तन नहीं करना चाहती है. इसलिए जहां कहीं अच्छी व्यवस्था होती है वह भी ख़राब हो जाती है. माना की सत्ताधीश सियासत के गणित में उलझे रहते हैं. परिवर्तन सियासत से हो या सामाजिक आंदोलन से, लेकिन उसके लिए किसी न किसी को पहल तो करनी ही पड़ती है, लेकिन नववर्ष में कुछ नया होता दिखाई नहीं दे रहा है. मानों विश्व मंदी का सारा बोझ यहीं आ पड़ा है. राज्य में सब पुराने ढर्रे पर चल रहा है. हमारे मंत्री–संतरी मंत्रमुग्ध अवस्था में बैठे हैं. राजनीतिक दलों का चिंतन–मनन–आत्ममंथन का समय चल रहा है. वे चुनावी गणित की चिंता में डूबे हुए हैं. नव विकास की बात सोचने की फ़ुर्सत नहीं है, क्योंकि पुराने विकास कार्य ही अधूरे पड़े हैं. उनके भी समय पर पूरे होने के आसार नहीं हैं. नए वर्ष पर उनके सामने कोई नया संकल्प नहीं हैं. चारों ओर भ्रष्टाचार व घोटालों का ही शोर सुनाई दे रहा है. उसके ख़िलाफ़ जो बोलता है सत्ताधीश उसका ही उत्पीड़न शुरू कर देते हैं. राज्य में क़ानून व्यवस्था बेहाल है. हत्या, अपहरण, डकैती की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है फिर भी हमारे माननीय गृहमंत्री जी कह रहे है कि महाराष्ट्र देश का सबसे सुरक्षित राज्य है. यह अलग बात है कि आतंकवादी जब चाहे कहीं आकर अपने नापाक इरादों पर अमल करने में कामयाब हो जाते हैं. शिक्षा की हालत ऐसी है कि स्कूल अब सरस्वती का मंदिर न रह कर दुधारू गाय बन गए हैं. इस दूधारू गाय को दूहने के लिए बोगस विद्यार्थियों –शिक्षकों का बोगस रिकार्ड बना कर संचालकों–अधिकारियों की मंडली द्वारा तिकड़म करने के कारनामे उजागर हो रहे हैं. हमारे भूमिपुत्र बदहाल हैं, कर्ज़ से बेजार हैं. उनकी ज़िंदगी पर सवालिया निशान है, लेकिन सरकार उनमें भी भेद करती है. समाज जातिवाद, ऊंच–नीच, अगड़ा–पिछड़ा से मुक्त होने की बजाय और उलझता नज़र आ रहा है. विकास की गति ऐसी है कि उससे ग़रीबी दूर होने की बजाय और बढ़ती जा रही है. महंगाई का मायाजाल समझ में नहीं आ रहा है. सरकार महंगाई को कम करना चाहती है कि नहीं यह जनता की समझ में नहीं आ रहा है. पेट्रोल–डीजल के दाम हर 15 दिन में बढ़ने की ख़बर अख़बारों की सुर्ख़ियां बनती हैं. इन सबके बीच भी राज्य की जनता आशा भरी नज़रों से राज्य के कर्ताधर्ताओं से कुछ नए दुस्साहसिक कदम उठाकर संपूर्ण व्यवस्था में बदलाव की अपेक्षा करती है. आशा है कि हमारे राज्य के नियंता बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध लेउ की नीति अपनाते हुए पिछले साल की कमियों–खामियों व बुरे को भूल कर नए साल में राज्य की प्रगति–विकास में कुछ नए आयाम जोड़ेंगे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

किसान के साथ धोखा
साहूकारों ने हड़पी हज़ारों एकड़ ज़मीन

महाराष्ट्र में क़ानूनन अवैध साहूकारी पर सरकार ने पूरी तरह प्रतिबंध लगा रखा है. बावजूद इसके राज्य में यह धंधा बेरोकटोक जारी है. क़ानूनन रोक के बाद भी बड़े पैमाने पर राज्य में अवैध साहूकारी का धंधा ज़ोरों से चल रहा है. ऐसा नहीं है कि शासन–प्रशासन इस हक़ीक़त से अनभिज्ञ है, लेकिन उसके सारे प्रयास विफल हैं, क्योंकि प्रशासन में भ्रष्टाचार की नदी बहने का फ़ायदा उठाना अवैध साहूकार अच्छी तरह जानते हैं. अवैध साहूकारों और भ्रष्ट अधिकारियों के चलते राज्य के कई ज़िलों में किसानों को अपनी ज़मीन से बेदखल होना पड़ रहा है. विदर्भ में ही मात्र 6 ज़िलों में अवैध साहूकारों ने किसानों की क़रीब दो हज़ार एकड़ ज़मीन हड़प लिया है, लेकिन शिकायतों के बाद भी प्रशासन किसानों को उसकी ज़मीन वापस दिलाने में नाक़ाम साबित हो रहा है.

ग़ौरतलब है कि राज्य के गृहमंत्री आर.आर. पाटिल ने एक–डेढ़ साल पहले अवैध साहूकारों के ख़िलाफ़ शिकायत करने का आह्वान किसानों से किया था. उनकी इस अपील को किसानों ने गंभीरता से लिया. इसके बाद पश्चिम विदर्भ के किसान आत्महत्या के लिए कुख्यात 6 ज़िलों में साहूकारों के ख़िलाफ़ शिकायत कराने की बाढ़ सी आ गई. यवतमाल (496), वर्धा (153), वाशिम (1070), अमरावती (773), अकोला (1432) और बुलढाणा (1176) ज़िले में अवैध साहूकारों के ख़िलाफ़ कुल 5100 शिकायतें पीड़ित किसानों द्वारा साहूकार विभाग के पास दर्ज कराई गई हैं. इसके बाद भी साहूकारी क़ानून की खामियों के कारण उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई अब तक नहीं की जा सकी है. किसानों की मानें तो उनका कहना है कि अवैध साहूकारों की संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ साठगांठ है. वहीं इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारी का कहना है कि कर्ज़ लेने वाले किसान पैसा लेते समय वे किस कागज़ पर अंगूठा लगाते हैं या दस्तख़त करते हैं, उस पर ग़ौर नहीं करते है. आसान कर्ज़ पाने के चक्कर में अवैध साहूकारों के पास जाते हैं और उनके चंगुल में फंस जाते हैं.

बढ़ती महंगाई, फसलों का उत्पादन पर्याप्त न हो पाने और कर्ज़ व उसके ब्याज़ को पटाने की चिंता में आर्थिक समस्याओं से घिरे किसानों को साहूकारों की शरण में मजबूरन जाना पड़ता है. उन्हें बैंकों की जटिल प्रक्रिया में उलझने की बजाय साहूकारों से आसानी से कर्ज़ लेना ज्यादा उचित लगता है. इसी का फ़ायदा साहूकार उठाते हैं. किसान ज़रूरत पड़ने पर जब साहूकारों के पास पैसा मांगने जाता है तो वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए कर्ज़ में दिए रुपयों के बदले उसकी ज़मीन गिरवी रख लेता है और उससे स्टांप पेपर पर अंगूठा लगवा लेता है या दस्तख़त करा लेता है. अधिकतर मामलों में किसान को यह पता ही नहीं होता है कि स्टांप पेपर पर लिखा क्या है. यहीं पर साहूकार चतुराई से काम लेता है. जानकारों का कहना है कि साहूकार जिन कागज़ों में किसान से अंगूठा लगवाता है या दस्तख़त कराता है, वह रेहन पत्र होने की बजाय खेत ख़रीदी–बिक्री पत्र रहता है. इसका लाभ उठाते हुए बाद में साहूकार ज़मीन से कब्ज़ा छोड़ने से साफ मना कर देता है. इस ख़रीदी–बिक्री पत्र के बल पर साहूकार ज़मीन के सातबारा में अपना नाम दर्ज़ करा कर उलटफेर भी करा लेता है. यह बात किसान को तब पता चलती है जब वह कर्ज़ की रक़म चुकाने के बाद अपनी ज़मीन से संबंधित काग़जात वापस मांगता है तो साहूकार हाथ खड़े कर देता है. इतना ही नहीं कई मामलों में यह बात भी सामने आई है कि साहूकार ने गिरवी रखी गई ज़मीन को धोखे से लिखाए बिक्री पत्र के आधार लाखों में बेच दिया और किसान को इसका पता भी नहीं चला. इन परिस्थितियों में जब किसान अपनी ज़मीन के काग़जात मांगने साहूकार के पास जाता है तो उसे दुत्कार दिया जाता है, पीड़ित किसान के साथ मारपीट करने तक के मामले सामने आ चुके हैं. ऐसे सभी मामलों में किसान हार थक कर सहकार विभाग में जाकर शिकायत करता है पर वहां भी उसकी नहीं सुनी जाती है. क़ानूनन देखा जाए तो खेती की ज़मीन गिरवी रखने की बात सिद्ध होने पर साहूकारी करने की बात भी सिद्ध हो जाती है. ख़रीदी–बिक्री पत्र से ज़मीन को ख़रीदे जाने की बात सिद्ध होती है, लेकिन सरल जीवन जीने वाले किसानों को क़ानून की जानकारी नहीं होती है. इसलिए वे साहूकारों के कहने पर कर्ज़ लेते समय कहीं भी दस्तख़त कर देते हैं. इसका लाभ उठाते हुए ही साहूकार सीधे किसान से अनजाने में बिक्री पत्र पर दस्तख़त कराने की कुटिल चाल चलते हैं. विशेष बात यह है कि साहूकार कुछ हज़ार या यों कहें कि मामूली रक़म देकर किसानों से बिक्री पत्र पर दस्तख़त करा लेते हैं, लेकिन यहां सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि अवैध साहूकारी को सिद्ध करने में किसान विफल साबित होते है और अपना सब कुछ खोने के बाद पछताने के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचता है. इस पर भी यदि किसी किसान ने अपनी ज़मीन पर साहूकार के ख़िलाफ़ जाकर खेती करता है तो फसल होने पर साहूकार के आदमियों द्वारा जबरन काट लिये जाने की घटनाएं होने की बात कही जाती है. इस हालत में किसान के पास आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं बचता है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

महाराष्ट्र हलचल

यवतमाल ज़िले के मुर्धोनी गांव में राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर के दौरान छात्राओं ने पानी की सुविधा के लिए बनाए गए वनराई बांध का अवलोकन किया.

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान के तहत वर्धा ज़िले के अल्लीपुर में श्री नामदेव महाराज बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था द्वारा आयोजित सिकलसेल बीमारी पर नियंत्रण कार्यक्रम में डॉ. टिचकुले, डॉ. झाड़े लोगों को परामर्श देते हुए.

दि लार्ड बुद्धा फाउंडेशन भंडारा की ओर से सार्वजनिक वाचनालय में आयोजित अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते डॉ. धनराज डहाट व मंचासीन अन्य अतिथि गण.

गढ़चिरोली ज़िला नियोजन सभा को संबोधित करते हुए गृहमंत्री आर. आर. पाटिल. इस मौके पर सांसद मारोतराव कोवासे, विधायक आनंदराव गेडाम, विधायक नामदेव उसेंडी, विधायक दीपक आत्राम और जि.प. अध्यक्ष रविंद्र ओल्लावार भी मौजूद रहे.

तिरोडा स्थित सी.जे. पटेल महाविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से वालडोंगरी में आयोजित शिविर को संबोधित करते प्रो. एस.यू. अनपट व अन्य अतिथिगण.

विदर्भ के 26 मित्रों ने मिलकर अपनी कला के माध्यम से एक अनूठी पहल की. उन्होंने अपनी चित्रों की प्रदर्शनी वन स्ट्रोक नागपुर शहर में आयोजित की. बिक्री से जमा हुई राशि को उन्होंने आत्महत्या करने वाले किसान के परिजनों को सौंपा.

अनाथों की माई के रूप में मशहूर वरिष्ठ समाजसेविका सिंधुताई सपकाल को नागपुर शहर के वसंतराव देशपांडे सभागृह में मैत्री गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया. इस अवसर पर डॉ. विलास डांगरे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश विकास शिरपुरकर और प्रमोद पेंड भी मौजूद रहे.

Postal Regn. No. RNP/NP/CITY/383/2011-13, RNI No. DELHIN/2009/30467

घोटालेबाज़ अधिकारी वैद्य को शासन की ओर से 138 क़ायम बिना अनुदानित स्कूलों के बोगस व कोरे प्रतिज्ञापत्र घोटाले की जांच की ज़िम्मेदारी सौंपे जाने की जानकारी मिली है.

आश्रमशाला बनी भ्रष्टाचार का केंद्र

राजेश नामदेव

राज्य की आश्रमशालाएं आदिवासी विभाग के अफसरों और निजी आश्रमशालाओं के संचालकों के लिए दुधारू गाय साबित हो रही हैं.भ्रष्टाचार का आश्रमशालाओं के बीच बड़ा गहरा संबंध है, लेकिन राजनीतिक दख़लांदाज़ी के चलते न कभी ईमानदारी से यहां व्याप्त कदाचार की जांच होती है और न ही कार्रवाई होती है. छात्रों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए हर वर्ष जो करोड़ों रुपये का अनुदान सरकार द्वारा आश्रमशालाओं को दिया जाता है उसका विधिवत बंटवारा आदिवासी विभाग के शिक्षा अधिकारी से लेकर प्रोजेक्ट ऑफिसरों के बीच होता है. आश्रमशालाओं की खोज-ख़बर लेने के लिए कभी-कभार दौरा करने वाले आयुक्तों को भी संचालकों द्वारा संतुष्ट करने की बातें अक्सर सामने आती रहती हैं. लिहाज़ा दूरद राज़ स्थित स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को यदि लाइफबॉय साबुन की जगह लाइटबॉय साबुन दिया जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है. इतना ही नहीं आश्रमशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए शासन-प्रशासन द्वारा निर्धारित खाने के मीनू का भी पालन नहीं किया जाता है. छात्र-छात्राओं को अंडा, दही और हरी सब्ज़ियों के कभी दर्शन तक नहीं होते हैं. इसका मतलब तो यही हुआ कि आदिवासी विभाग के अधिकारी आश्रमशालाओं के संचालकों से मिलीभगत करके छात्र-छात्राओं के हक़ में डाका डालते हैं. यह तो सामान्य रूप से लगने वाले आरोप हैं, लेकिन हाल ही में जो प्रकरण सामने आया है, वह बेहद चौंकाने वाला है. आश्रमशालाओं के लिए शासन द्वारा अनुशंसा न मिलने पर भी आदिवासी विभाग द्वारा नियमों को नज़रअंदाज़ कर पौने 6 करोड़ रुपये की लूट हुई. इस लूट में शामिल अधिकारियों को प्रमोशन देकर आदिवासी विभाग ने पुरस्कृत किया है.

पिछले माह नागपुर में संपन्न शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह में 21 दिसंबर को विधान परिषद में भाजपा विधायक संजय केलकर ने राज्य की आश्रमशालाओं की बदहालियत की ओर सरकार का ध्यान केंद्रित किया. इस पर आदिवासी विकास मंत्री बबनराव पाचपुते ने बताया कि आश्रमशालाओं की इमारतों के लिए राज्य सरकार ने 640 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इस पर शिवसेना विधायक डॉ. दीपक सावंत ने पूरक प्रश्न पूछते हुए आश्रमशालाओं में बच्चों को वितरित की जाने वाली निम्न किस्म के स्लेट्स, दंत मंजन व अन्य सामग्रियां निकालकर सदन के समक्ष रखकर व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करना शुरू किया तो मंत्री की बोलती बंद हो गई. डॉ. सावंत ने आदिवासी मंत्री को खुली चुनौती दी है कि वे आश्रमशालाओं में बच्चों को वितरित टूटी स्लेट में लिखकर दिखाएं. उस स्लेट में लिखना संभव नहीं था. घटिया दर्जे की साबुन, दंत मंजन, दवाइयां दिखाना शुरू किया तो आदिवासी मंत्री पाचपुते परेशान हो उठे. इसके बाद भी पाचपुते अधिकारियों का बचाव करते नज़र आए. इससे भड़के डॉ. सावंत ने कहा कि आदिवासी विकास विभाग ने छात्र-छात्राओं के भविष्य को मजाक बना रखा है. यदि सामग्री ख़रीदी में गड़बड़ी नहीं है तो मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूं या फिर मंत्री पाचपुते इस्तीफ़ा दें. उन्होंने सभी वस्तुओं की ख़रीदी की जांच कराने की मांग की. सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक उल्हास पवार ने भी डॉ. सावंत के आरोपों का समर्थन करते हुए आश्रमशालाओं में बच्चों को घटिया भोजन दिए जाने का मुद्दा उठाया. इस पर आदिवासी मंत्री पाचपुते ने सदस्यों के आक्रामक रुख़ को देखते हुए सभी मामलों की जांच कराने का आश्वासन देते हुए बताया कि अब तक 19 प्रकल्प अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन सदन में हुई इस बहस से साफ़ हो गया कि आश्रमशालाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के प्रति आदिवासी विभाग के मंत्री गंभीर नहीं है. वहां व्याप्त अनियमितताओं पर वे रह-रह कर अपने विभाग के अधिकारियों का ही बचाव करते नज़र आए.

दूसरी ओर सोलापुर में समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा अनुशंसा के बिना सैकड़ों पदों को मंजूरी दिए जाने और उससे करोड़ों रुपये की बंदरबांट करने के मामले में आदिवासी विकास मंत्री ने कोई ध्यान नहीं दिया. जिससे यही लगता है कि आदिवासी विकास विभाग रामभरोसे चल रहा है. शासन की अनुशंसा के बिना नियमों की अवहेलना करते हुए 200 पदों को मंजूरी दिए गया. इसके लिए 77 आश्रमशालाओं के परीक्षण अनुदान और वेतन अनुदान मिलाकर 5 करोड़ 83 लाख 80 हज़ार 868 रुपयों की लूट का पता जांच के दौरान चला है. इस लूट के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की बजाय उनको प्रमोशन देकर पुरस्कृत करने का मामला सामने आया है. दरअसल यह मामला उस समय सामने आया जब प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशालाओं में अनियमित कारभार को लेकर महादेव वाले ने मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दाख़िल की. इस याचिका की सुनवाई के दरम्यान 21 अक्टूबर 2010 को न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के तहत पुणे के विभागीय समाज कल्याण अधिकारी एस.बी. भंडारे की अध्यक्षता में लेखा उपसंचालक डी.डी. द्वारके व विजाभज कल्याण उपसंचालक ए.पी. कांबले की जांच समिति का गठन किया गया. इस समिति ने जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट न्यायालय को सौंप दी है. जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि आर्थिक ग़ैर व्यवहार व अनुशंसा न होने पर भी पदों को मंजूरी देने के लिए ज़िम्मेदार उमाकांत कांबले उपसंचालक पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं. इसी तरह सोलापुर के तत्कालीन विशेष समाज कल्याण अधिकारी माधव वैद्य और राजेंद्र कलाल को प्रमोशन दिया गया है. वर्तमान में वैद्य अमरावती और कलाल नासिक में विभागीय समाज कल्याण अधिकारी के रूप में पदस्थ हैं.

सोलापुर में विशेष समाज कल्याण अधिकारी के पद पर माधव वैद्य वर्ष 2006 से अगस्त 2008 तक पदस्थ थे. वर्ष 2006 से 2007 के दरम्यान किमती (खु.) स्थित आश्रमशाला में 25 पदों को मान्यता प्रदान की गई, जिसमें तहत 5 सहायक शिक्षक, एक लिपिक, दो चपरासी, एक खाना बनाने वाला और शासन से अनुशंसा के बिना एक प्रयोगशाला सहायक, एक आंशिक ग्रंथपाल, एक अधीक्षक शामिल थे. इन 12 पदों पर नियुक्तियां नियम से बाहर होकर मान्यता दी गई और वेतन का भुगतान सभी को किया गया. इसी तरह ज़िले की अन्य आश्रमशालाओं में नियुक्तियां की गईं. इसके चलते वैद्य ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बतौर वेतन 18 लाख 27 हज़ार 477 रुपये अधिक मंजूर किए. इसके बावजूद इस घोटालेबाज़ अधिकारी वैद्य को शासन की ओर से 138 क़ायम बिना अनुदानित स्कूलों के बोगस व कोरे प्रतिज्ञापत्र घोटाले की जांच की ज़िम्मेदारी सौंपे जाने की जानकारी मिली है. इसी तरह उमाकांत कांबले वर्ष 1995 से 1999 की अवधि के दरम्यान विशेष समाज कल्याण अधिकारी और उसके बाद विभागीय समाज कल्याण अधिकारी के पद पर पदस्थ रहे हैं. जिस समय वे विशेष समाज कल्याण अधिकारी थे उस वक्त नियमों के विपरीत चार पदों को मंजूरी देकर 1 लाख 65 हज़ार 916 रुपये शासन के खजाने से निकाला. राजेंद्र कलाल ने अपने कार्यकाल में आश्रमशाला में कक्षाओं के वर्ग (तुकड़ीवाढ) को मंजूरी दी गई. जांच समिति को अतिरिक्त शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की मंजूरी का प्रस्ताव संबंधित फाइलों में दिखाई नहीं दिया. बनावटी आदेश पत्र क्रमांक 65 के अनुसार नियमों के तहत न होने पर भी पदों को मंजूर करने के तथ्य सामने आए हैं और उक्त बोगस आदेश के तहत 22 पदों को मंजूर किया गया. लिहाज़ा इसके कारण समाज कल्याण विभाग को बतौर वेतन 80 लाख 35 हज़ार 550 रुपये का फटका लगा. घोटाले की यह कहानी यहीं नहीं रुकती है. कलाल के बाद 2-4 माह के लिए प्रभारी बनकर पदभार ग्रहण करने वाले आर.के. भोंसले और एस.के. जाधव ने भी सोलापुर में आकर बिना अनुशंसा के सात पदों को मंजूर किया. यह भी पता चला की इस नियम के बाहर पदों को मंजूरी देने का गोरखधंधा शुरू करने का श्रेय एक स्वर्गीय हो चुके आधिकारी को जाता है. इस घोटाले के तहत वर्ष 2007 से 2008 और 2008 से 2009 में वर्ष के अंत में परीक्षण अनुदान के नाम पर 4 करोड़ 57 लाख 14 हज़ार 474 रुपये आश्रमशालाओं को ज्यादा भुगतान किया गया. यह आंकड़ा मात्र एक ज़िले का है. यदि पूरे राज्य में आश्रमशालाओं में होने वाली नियुक्तियों की जांच की जाए तो यह मामला भी बोगस छात्राओं के नाम पर अनुदान लूटने जैसा व्यापक हो सकता है.

feedback@chauthiduniya.com

सेनिटरी में भी गोलमाल

राज्य की आश्रमशालाओं व छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को सेनिटरी वितरित करने का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है, लेकिन 8 वीं से 12वीं तक की छात्राओं को यह कभी नहीं दिया जाता है, जबकि सेनिटरी के लिए सरकार ने वर्ष 2010-11 के लिए भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित, मुंबई को 1 करोड़ 71 लाख 19 हज़ार रुपये का ठेका दिया गया था. यह बात विधान सभा में विधायक डॉ. दीपक सावंत ने उठाया था, लेकिन आदिवासी विकास मंत्री उनका जबाव तक नहीं दे पाए.

विधानसभा में उठ चुका है यह मुद्दा

ऐसा नहीं है कि इस घोटाले की जानकारी सरकार को नहीं है. सरकार को इस पूरे घोटाले की जानकारी है, लेकिन अब तक उसने दोषियों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की. पिछले वर्ष 2010 में विधानसभा में इस प्रकरण को विपक्षी विधायक सुधीर मुनगंटीवार, विधायक पंकजा (मुंडे) पालवे, विधायक संजय भेगड़े व विधायक मधुदी मिसाल ने लक्ष्यवेधी सूचना के रूप में उठाया था, लेकिन लगता है कि सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और बग़ैर अनुशंसा के पदों को मंजूरी देकर जनता के पैसों की लूट की. यह मामला ठीक उसी तरह का है जैसे बोगस छात्रों के नाम पर अनुदान डकारने का था. फ़िलहाल बिना अनुशंसा के पदों को मंजूरी देकर करोड़ों का गोलमाल करने का मामला सिर्फ़ सोलापुर ज़िले में उजागर हुआ है. यदि पूरे राज्य में स्थित आश्रमशालाओं की जांच की जाए तो यह मामला काफी बड़ा हो सकता है. बहरहाल सोलापुर का मामला भी मुंबई उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण सामने आया है. यदि सरकार वाकई भ्रष्टाचार के ख़ात्मे को लेकर गंभीर है तो वह राज्य में स्थित सभी आश्रमशालाओं के क्रिया-कलापों की जांच कराए, ताकि उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को रोका जा सके और जनता के धन को बचा कर अन्य विकास कार्यों में लगाया जा सके.

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. बवनराव पाचपुते भले आदमी हैं और वारकरी समुदाय से संबंध रखते हैं. ऐसे में उनसे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे आदिवासी समाज के उद्धार के लिए जो विभाग उनके सुपुर्द किया गया है, उसमें व्याप्त कदाचार को ख़त्म करने की बजाय दोषी अधिकारियों का बचाव कर अपनी ज़िम्मेदारी से पल्ला झाड़ लें. आश्रमशालाओं में लगने वाले आरोपों को उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए और छात्र-छात्राओं के हक़ की सामग्री दिलाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए.

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 09 जनवरी–15 जनवरी 2012

www.chauthiduniya.com

संजीवनी का है ऐलान, झारखण्ड–बिहार में हो सबका मकान

SANJEEVANI BUILDCON

3rd & 4th floor, GEL Church Complex, Main Road, Ranchi, Customer Care No. - 0651-2331429

Our on going projects–

Sanjeevani Dynasty-I
PLOT-13 LAC, DUPLEX-25 LAC
Near Ranchi College

Sanjeevani Dynasty-II
PLOT-10 LAC, DUPLEX-22 LAC
Booty More

Future City (BIT)
PLOT-4 LAC,
BUNGLOW-10 LAC

Future City (Namkom)
PLOT-4 LAC,
BUNGLOW-10 LAC

Future City (Pithoria)
PLOT-4 LAC,
BUNGLOW-10 LAC

Sanjeevani Mega Township
PLOT-3.5 LAC, BUNGLOW-09 LAC
Hazaribagh

अब तो जागिए हुज़ूर

नीतीश कुमार की दूसरी पारी में राजद व लोजपा ने यह कह कर छह महीने चुप्पी साधी रखी कि वह सरकार को काम करने का मौका देना चाहते हैं. लोगों को यह समझ में नहीं आई कि चुनाव में जिस सरकार को वह भ्रष्ट व निकम्मा बता रहे थे वह दूसरी पारी में पूरी पाक साफ कैसे हो गई और छह महीने तक उसके सारे गुनाहों को चुपचाप देखने से जनता का क्या भला होगा. दरअसल, ये दल काम करने का मौका नहीं बल्कि अपनी करारी हार से इतना टूट गए थे कि उनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी. उस दौरान अब्दुलबारी सिद्दीक़ी, रामकृपाल यादव व उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता आधे अधूरे मन से पटना में बयानबाजी करते रहे पर ज़मीन पर मज़बूत आंदोलन छेड़ने का साहस नहीं जुटा पाए.

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

सरोज सिंह

साल बदल गया मगर बिहार में विपक्षी पार्टियों के रंग और ढंग जस के तस हैं. लगता है सत्ता की खुमारी अब भी इन्हें सड़कों पर आने से रोक रही है. जनता ने तो इन्हें सड़क पर संघर्ष का जनादेश दिया पर वे इस जनादेश का सम्मान नहीं कर रहे हैं. पिछले साल जनता से जुड़े सारे संघर्ष के मुद्दे इनका इंतजार करते रहे पर विपक्षी नेता सपनों की दुनिया में समय काटते रहे ताकि जनता से इनकी दूरी बनी रही. दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने जनता से रूबरू होने का कोई मौका नहीं गंवाया और जनता दरबार और सेवा यात्रा के माध्यम से वह जनता की नब्ज टटोलने में लगे रहे. जनता से मिलने का यही फ़र्क़ नीतीश कुमार को चुनावी राजनीति में आगे ले जा रहा है और विपक्ष एयरकंडीशन कमरे में बयान जारी कर हाथ मलता रह जा रहा है.

नीतीश कुमार की दूसरी पारी में राजद व लोजपा ने यह कह कर छह महीने चुप्पी साधी रखी कि वह सरकार को काम करने का मौका देना चाहते हैं. लोगों को यह समझ में नहीं आई कि चुनाव में जिस सरकार को वह भ्रष्ट व निकम्मा बता रहे थे वह दूसरी पारी में पूरी पाक साफ कैसे हो गई और छह महीने तक उसके सारे गुनाहों को चुपचाप देखने से जनता का क्या भला होगा. दरअसल, ये दल काम करने का मौका नहीं बल्कि अपनी करारी हार से इतना टूट गए थे कि उनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी. उस दौरान अब्दुलबारी सिद्दीक़ी, रामकृपाल यादव व उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता आधे अधूरे मन से पटना में बयानबाजी करते रहे पर ज़मीन पर मज़बूत आंदोलन छेड़ने का साहस नहीं जुटा पाए. कांग्रेस अपनी दुर्गति से इतनी कमजोर हो गई कि जनता को उसमें उम्मीद की कोई किरण ही दिखाई नहीं दे रही है. इसलिए इससे अपेक्षा भी नहीं थी. प्रदेश अध्यक्ष निजी कामों में इतने व्यस्त हैं कि पार्टी के स्थापना दिवस पर सदाकत आश्रम तक नहीं गए. वाम दलों ने भी पहले छह महीने में निराश किया. छह माह बाद लालू प्रसाद और रामविलास पासवान ने मुंह खोला. उन्होंने कहा कि उन्हें जनता के दर्द का अहसास है और हमलोग जनता से जुड़े मामले को सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे. लेकिन यह बात भी केवल अख़बारों में छप कर रह गई. लोजपा से बात शुरू करें तो उनके प्रदेश अध्यक्ष पटना से बाहर निकलते ही नहीं हैं. पटना में भी पशुपति पारस के दर्शन हो जाएं तो अहो भाग्य. पार्टी ने गांधी मैदान में स्थापना दिवस के मौके पर रैली का आयोजन किया. रैली में जुटी भीड़ की संख्या ने बता दिया कि जनता इन नेताओं से कितनी दूर जा रही है. प्रमंडल व जिलास्तर पर जनसमस्याओं को लेकर कोई आंदोलन पिछले साल पार्टी ने नहीं छेड़ा. राजद ने भी पोल खोल यात्रा का कार्यक्रम बना रखा है पर ज़मीन पर इसकी शुरुआत का इंतजार है. राजद के मीडिया प्रभारी रणधीर यादव बताते हैं कि पार्टी पूरी तरह सक्रिय है लेकिन मीडिया के असहयोग के कारण इनकी बात जनता तक पहुंच नहीं पा रही है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल सुलभ कहते हैं कि चुप बैठने जैसी बात नहीं है, मेरी पार्टी पूरे साल संगठनात्मक कार्यों में लगी रही. कांग्रेस के आंतरिक ढांचे को मज़बूत कर लिया गया है और नए साल में पार्टी जनता के मुद्दे पर ज़ोर–शोर से संघर्ष करेगी. कांग्रेस ने हमेशा आम आदमी का ख्याल रखा है और हम अपनी ज़िम्मेदारियों से भागने वाले नहीं हैं. दावों से अलग हटें तो यह सच्चाई सामने आती है कि लालू व पासवान दिल्ली में अपनी जगह बनाने में इतने मशगूल हैं कि उन्हें बिहार की चिंता ही नहीं हैं. पिछले साल लालू प्रसाद बहुत कम पटना आए. रामविलास पासवान पटना आते रहे पर दो कामों से, पार्टी कार्यालय में बयान जारी करने और अपने बेटे की फिल्म के प्रमोशन में. इन दोनों नेताओं के खाते में बस एक आंदोलन का स्कोर है फारबिसगंज का. इसे भी ये दोनों मुकाम तक नहीं पहुंचा पाए. यहां सताए गए लोगों को अभी भी पूरा न्याय नहीं मिल पाया है. तालमेल व रणनीति की बात करें तो हाल यह है कि लौकहा को छोड़कर सभी उपचुनाव अलग–अलग लड़े और बुरी तरह मात खा गए. इसके बाद भी सबक सीखने को तैयार नहीं. इस मसले पर पूर्व विधान पार्षद प्रेमकुमार मणि कहते हैं कि इन नेताओं को अब भी लगता है कि वे सत्ता में बने हुए हैं. इस खुमारी से वे उबरे नहीं हैं. चुनावी हार पर मणि का मानना है कि केवल रणनीतिक भूल के कारण ही यह स्थिति पैदा हो रही है. नीतीश कुमार की बुनियाद बहुत ज्यादा वोटों पर नहीं टिकी है. लेकिन दिक्कत यह है लालू प्रसाद व रामविलास पासवान एक ही गलती बार बार दोहरा रहे हैं. मणि कहते हैं कि जब तक नीतीश कुमार के आधार वोट बैंक में सेंध नहीं लगेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है. ये दोनों नेता प्रभुनाथ सिंह और रामा सिंह से ताक़त लेना चाहते हैं पर जगदानंद सिंह और रघुवंश सिंह उन्हें नज़र नहीं आते.

उपेंद्र कुशवाहा व अरुण कुमार जैसे नेता अपनी ढपली अपना राग वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं. नवल यादव व रामबदन राय बाबा रामदेव को आगे रखकर क्या करना चाहते पता नहीं. इस दौरान पी के सिन्हा व मिथिलेश सिंह ज़रूर सरकार को क़ानूनी मोर्चे पर घेरने में लगे रहे. विपक्ष के कुछ नेताओं ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि यह सारा खेल तमाशा राज्यसभा व विधान परिषद के चुनाव तक चलेगा. दरअसल, विपक्ष से जुड़े कई नेता केवल अभी दबाव की राजनीति व संघर्ष कर रहे हैं. वे चाहते हैं कि बैठे–बैठे उनके नाम की लाटरी निकल जाए. कुछ नेताओं को उम्मीद है कि उन्हें राज्यसभा व विधान परिषद में जगह मिल जाएगी, इसलिए वे चुप हैं. एक बार जब तस्वीर सामने आ जाएगी तो कई दिग्गजों का भ्रम टूटेगा और बिहार में विपक्ष की राजनीति का नए सिरे से ध्रुवीकरण होगा. हो सकता है इसमें जदयू से जुड़े कई नेता भी हों.

feedback@chauthiduniya.com

जगदानंद ने दी नीतीश को बहस की चुनौती

सरकार बार-बार दावा कर रही है कि केंद्र की अड़चन के कारण बिहार में चीनी मिलों का ताला नहीं खुल पा रहा है और इस वजह से प्रदेश उद्योग के मामले में पिछड़ रहा है. लेकिन सासंद जगदानंद सिंह ने इसे बिहार सरकार का जनता के साथ धोखा क़रार दिया है. जगदानंद सिंह ने कहा कि बिहार सरकार गन्ना से सीधे इथेनॉल के उत्पादन की इजाज़त मांग रही है जो देश में कहीं नहीं है. भारत सरकार ने पूरे देश में कहीं भी गन्ना से सीधे इथेनॉल उत्पादन की इजाज़त नहीं दी है तो बिहार इसकी मांग की जिद पर क्यो अड़ा है. दरअसल, सरकार अपनी नाकामी का ठीकरा केंद्र सरकार पर ठोंक रही है. जगदानंद सिंह ने चुनौती दी कि मैं चीनी मिल व इथेनॉल के मामले में नीतीश कुमार सहित किसी से भी खुली बहस करने को तैयार हूं. नीतीश कुमार में अगर ईमानदारी व हिम्मत है तो वह मुझसे इस मसले पर बहस करें. बिहार की जनता समझ जाएगी कि कौन सच बोल रहा है. उन्होंने कहा कि यह बिहार का दुर्भाग्य है कि हम अपना पेट भरने के लिए अनाज आयात कर रहे हैं. पूरे देश को खिलाने की क्षमता रखने वाला बिहार आज आयायित अनाज पर निर्भर है. उन्होंने कहा कि सरकार को सोचना चाहिए कि उसे शराब व इथेनॉल बनाना है या फिर अनाज पैदा करके बिहारियों का पेट भरना है. सिंह ने कहा कि इथेनॉल के नाम पर धोखा देने का काम तुरंत बंद होना चाहिए और सरकार को जनता के सामने सही तस्वीर पेश करना चाहिए.

खाद्यानों पर माफ़ियाओं का राज

चंद्रेश कुमार शर्मा

झारखंड में सत्ता में बैठे राजनेता भी अब बिहार की तर्ज पर सुशासन-सुशासन की रट लगाने लगे हैं. राज्य में चहुंमुखी विकास का नारा लगाने वाले राजनेताओं और उनके नौकरशाहों ने कैसी-कैसी कारस्तानियां की हैं, इसका जीता जागता उदाहरण चतरा ज़िले में दिखता है. ग़रीबों को मिलने वाले खाद्यानों पर माफिया तत्व कितने हावी हैं, इसका उदाहरण हंटरगंज प्रखंड में देखा जा सकता है. हंटरगंज को चतरा ज़िले का सबसे बड़ा प्रखंड माना जाता है. यहां जागरूकता की दर सबसे ज़्यादा है, ऐसे जागरूक प्रखंड में वर्षों से सक्रिय खाद्यान माफ़िया इतने हावी हैं कि लोग सब कुछ जानकर भी मौन रहते हैं. यहां प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के तौर पर पदस्थापित हैं शशि भूषण अम्बष्ठ. इनके रहमोकरम पर ही यहां का आपूर्ति कार्यालय चलता है. यहां आपूर्ति पदाधिकारी की इतनी तूती बोलती है कि पूछिये मत. आपूर्ति विभाग में इनकी पकड़ का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे प्रखंड में लगभग 124 जनवितरण की दुकानें संचालित हैं, जिसमें से एक दर्जन से ज़्यादा महिला दुकानदारों को अपने हस्ताक्षर तक करने नहीं आते और इनके ज़िम्मे ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें आवंटित कर दी गई हैं. जिस दुकानदार को अपना हस्ताक्षर करना नहीं आता वह कार्डधारियों के नाम कैसे लिखता होगा और उन्हें खाद्यान कैसे देता होगा, यह सोचने वाली बात है. इसके अलावा कुछ ऐसे भी लाइसेंसधारी दुकानदार हैं, जिनके पास कार्डधारियों का कहीं अता पता नहीं और माह में एक सौ क्विंटल खाद्यान की आपूर्ति की जाती है. ऐसे मामलों को पिछले दिनों नवीनीकरण कैम्प में चतरा के अनुमंडलाधिकारी ने पकड़ा. उन्होंने मौके पर ही ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उनके ही कार्यकाल में पिछले एक वर्ष से एक जिला परिषद सदस्य सुरेश सिंह, जनवितरण प्रणाली का दुकानदार बना रहा और उनको पता तक नहीं चला. है ना आश्चर्य की बात! अब ऐसे पदाधिकारी के रहते आपूर्ति विभाग कितनी तरक्की कर रहा होगा, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है. पूरे प्रकरण का खुलासा भी काफी नाटकीय तरीके से तब हुआ, जब चतरा के अनुमंडल अधिकारी अरुण कुमार रतन जनवितरण प्रणाली की दुकानों के नवीनीकरण के लिए प्रखंड कार्यालय पहुंचे. नवीनीकरण की प्रक्रिया के समय जिला परिषद सदस्य सुरेश सिंह उर्फ सुरेश पासवान कार्यक्रम स्थल पर लगातार जमे रहे, और जब उनकी बारी आई तो अनुमंडल अधिकारी चौंक पड़े. अनुमंडल अधिकारी ने तत्काल जिला परिषद सदस्य की जनवितरण दुकान रद्द करने का फरमान सुना दिया. इस प्रकरण पर अनुमंडल अधिकारी अरुण कुमार रतन ने चौथी दुनिया को बताया कि नवीनीकरण प्रक्रिया के दौरान उन्हें लगा कि जिला परिषद सदस्य जनप्रतिनिधि की हैसियत से कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं, लेकिन नवीनीकरण प्रक्रिया में दुकानदार के तौर पर उनकी उपस्थिति आश्चर्यचकित कर देने वाली थी. उन्होंने बताया कि सरकार का यह नियम है कि कोई भी जनप्रतिनिधि जनवितरण प्रणाली का दुकानदार नहीं हो सकता. इस परिस्थिति में यह बड़े आश्चर्य की बात है कि चुनाव की प्रक्रिया सम्पन्न होने के बाद भी एक वर्ष तक सरकारी राशि का दुरुपयोग होता रहा और उन्हें जानकारी तक नहीं दी गयी. उन्होंने बताया कि जिला परिषद सदस्य ने एक वर्ष के दौरान जितनी राशि के खाद्यान का उठाव

कैम्प में महिला दुकानदार

नवीनीकरण प्रक्रिया में अनुमंडलाधिकारी

हंटरगंज

किया गया है, उसकी रिकवरी की जाएगी. यहां उल्लेख करना आवश्यक है कि हंटरगंज प्रखंड में खाद्यान की कालाबाज़ारी काफी समय से हो जाती रही है और इस कालाबाजारी समूह के मुखिया रहें है जिला परिषद के सदस्य सुरेश सिंह. हालांकि एक वर्ष पूर्व ही पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं, परंतु कालाबाज़ारी का यह किस्सा काफी पुराना है. वर्ष 1989 में सुरेश सिंह ने दुकान का लाइसेंस लिया था, तब से लेकर अब तक उनके नाम से ही दुकान चलती रही. जबकि नियम यह कहता है कि जब आप जनप्रतिनिधि के तौर पर चुनाव में निर्वाचित होते हैं तो तत्काल दुकान का सरेंडर कर दें. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. बहरहाल, मामला चाहे जो भी हो परन्तु एक बात तो तय है कि बिना प्रशासनिक सहयोग के जिला परिषद सदस्य सुरेश सिंह जनवितरण के दुकानदार नहीं बने रह सकते थे. इस पूरे प्रकरण पर निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है कि जिला प्रशासन के कौन-कौन से अधिकारी इस गोरखधंधे में शामिल थे और क्या इस पूरे प्रकरण में किसी दल विशेष के राजनेता का भी प्रशासन पर दवाब था?

feedback@chauthiduniya.com

मोटापे और तनाव से हार्ट अटैक के मामले बढ़ते हैं

डॉ अतुल कुमार

मोतिहारी के जाने माने चिकित्सक डॉ अतुल कुमार ने मलेरिया के बढ़ते प्रकोप पर चिंता जताते हुए लोगों को इससे बचने के लिए कुछ सलाह दी हैं. पथरी व दिल के दौरे पर भी उन्होंने जानकारी दी है. प्रस्तुत है उनसे बातचीत के कुछ ख़ास अंश.

▶ **मलेरिया जैसी बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए?**

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है. मलेरिया से बचने के लिए हमें अपने आस-पास पानी का जमाव नहीं होने देना चाहिए. यदि जल-जमाव हो तो इसमें कीटनाशक दवा का छिड़काव करना चाहिए. ऐसे में मिट्टी के तेल को समय-समय पर डालते रहने से मच्छर मर जाते हैं. मच्छर से बचने के लिए फुल साइज के कपड़े पहनकर रहना चाहिए. सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करना उचित है.

▶ **मलेरिया के लक्षण क्या-क्या हैं?**

ठंड देकर तेज बुखार आना, सिर तथा शरीर में दर्द, उल्टी और बेहोश हो जाना जैसे कुछ लक्षण हैं मलेरिया बुखार के.

▶ **किडनी में पथरी किस वजह से होती है?**

किडनी में पथरी होने के बहुत से कारण हैं. कम पानी पीने, शरीर में अधिक कैल्शियम होने, बैंगन, टमाटर, साग आदि के अधिक सेवन करने से यह बीमारी हो सकती है.

▶ **हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, खासकर महिलाओं में, क्या कारण है?**

हार्ट अटैक ज्यादातर 50 वर्ष के बाद होता है. स्टोजन लेवल ... पुरुषों की अपेक्षा यह महिलाओं में कम होता है. महिलाओं में हार्ट अटैक होने का मुख्य कारण मोटापा है. महिलाएं अब बाहर निकलकर काम करने लगी हैं. स्ट्रेस बढ़ने के कारण इनमें पुरुषों की अपेक्षा अधिक अटैक आते हैं.

अमिया कण
feedback@chauthiduniya.com

बीज और खाद को तरसते किसान

शुभम रानी चौहान

छपरा

नीतीश सरकार की किसानों तक खाद बीज पहुंचाने की घोषणा मात्र छलावा बनकर रह गई है. जनता लगातार कालाबाज़ारी की शिकार हो रही है, वहीं अधिकारी गोलमटोल जवाब देकर अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं. जबकि अधिकतर पैक्स सरकारी तंत्र के प्रभाव में उद्देश्य से भटक गए हैं. दो वर्ष पूर्व छपरा जिले की सभी पंचायतों में पैक्सों का गठन एवं चुनाव करा कर किसानों को खेती से लेकर उनकी उपज की बिक्री तक भरपूर सहयोग की ज़िम्मेवारी दी गयी. परंतु कुछ को छोड़ कर अधिकतर पैक्स अध्यक्षों की कारगुजारियों एवं विभागीय पदाधिकारियों की उदासीनता के कारण किसानों को फसल उत्पादन से लेकर विक्रय तक का लाभ नहीं मिल रहा है. सरकार द्वारा बार बार पैक्सों को बेहतर सुविधा देकर किसानों को ज़्यादा लाभ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है. गत एक सितंबर को विभाग के तत्कालीन निदेशक पंकज कुमार पाल ने सारण ज़िले में खाद का व्यवसाय करने वाली सभी उर्वरक कंपनियों यथा एनएफए, पीपीएल, आरसीएफ, नागार्जुन, पारस आटा केमिकल्स लिमिटेड, आईपीएल के राज्य प्रबंधकों को पत्र लिख कर निर्देशित किया था कि इफको एवं कृभको नामक सरकारी खाद कंपनियों के अलावा उन निजी खाद कंपनियों को भी बिहार में अपनी अपनी खपत की 15 फीसदी खाद अपने अधीन सभी थोक विक्रेताओं के माध्यम से वैसे पैक्स संचालकों को दी जाए जो उर्वरक का व्यवसाय करना जानते हैं. उन्हें प्रपत्र ओ उपलब्ध करा कर जिला कृषि पदाधिकारी से अनुज्ञप्ति दी जा सकती है. यदि खाद संबंधित पैक्स द्वारा नहीं उठाया जाता है तो इसी प्रखंड के अन्य विक्रेताओं को उपावंटित कर दिया, जिससे उर्वरक का परिचालन प्रभावित न हो, परंतु विभागीय पदाधिकारियों की उदासीनता के कारण निजी कंपनियों द्वारा जिले मे एक फीसदी खाद भी किसी पैक्स को नहीं दी जाती. हालांकि, सहकारिता विभाग के निर्देश के आलोक मे जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा डीएओ, सारण को पत्र लिख कर गत नवंबर मे ही कहा गया था कि निजी कंपिनयों से 15 फीसदी खाद लेने के लिए इच्छुक पैक्सों एवं व्यापार मंडल को प्रपत्र ओ उपलब्ध कराया जाए तथा किसी भी स्थिति में पैक्स एवं व्यापार मंडल के अलावा अन्य सहकारी समिति को इन सरकारी कंपनियों की खाद उपलब्ध नहीं करायी जाए, परंतु जिले में स्थिति संतोषजनक नहीं दिखती. जिले में लगभाग 25 ऐसे पैक्स अध्यक्ष हैं, जो अब तक खाद के लाइसेंस को लेकर किसानों को सरकार के उद्देश्य के तहत सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत नहीं समझते. सहकारी समिति के सहायक निबंधन कार्यालय के सूत्रों के अनुसार इन पैक्स संचालकों मे जलालपुर प्रखंड के विष्णुपुरा, किशुनपुर, मांझी के बेरजा, तैतपुर बेलसरा, मांझी पश्चिमी, माझी पूर्वी लहलादपुर के मिर्जापुर, बनियापुर के सरेया, मढौरा की बहुआरा पटी, अंवारी, तेजपुरवा, परसा के परसौना, तरैया का पोखरेरा, भगगाई, एकमा का परसा इतरी, देवपुरा, रिविलंगज का सिताब दियारा, दक्षिणवारी चक्की प्रभुनाथ नगर, मुकरेडा, गडखा के पचपटिया, जलालबसंत, मिठेपुर, पानापुर के कोंध तथा मशरक के सेमरी पैक्स शामिल है. जब इन पैक्स संचालकों द्वारा खाद का लाइसेंस डीसीओ के पत्राचार के बावजूद नहीं लिया गया, तो किसानों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं की क्या बात. राजद नेता प्रो. ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि नीतीश की सरकार खाद बीज का अपने अधिकारियों के माध्यम से कालाबाजारी करा रही है. दिघवारा प्रखंड के मानुपुर पंचायत के मुखिया संजीत कुमार सिंह के अनुसार खाद किसानों की पहुंच से दूर है. वहीं युवा जदयू के प्रदेश महासचिव पुरुषोत्तम सिंह गुड्डा ने बताया कि सरकार खाद पैक्स के माध्यम से किसानों तक पहुंचा रही है, जबकि कुछ कामचोर अधिकारी इसमें बाधक बन रहे हैं.

प्रो. ओम प्रकाश

पुरूषोत्तम गुड्डा

संजीत कुमार सिंह

feedback@chauthiduniya.com

एनजीओ का फ़र्ज़ीवाड़ा: पालनवाड़ी के नाम पर करोड़ों की ठगी

अरुण साथी

कहां कहां थे केंद्र

नाम	गांव	थाना	ज़िला	राशि
सुधा कुमारी	अकौना	धोसी	जहानाबाद	8000
रूबी कुमारी	सकरावां	अस्थावां	नालंदा	7000
संजना कुमारी	हरगांवां	अस्थावां	नालंदा	6500
विभा देवी	सामाचक	बरबीघा	शेखपुरा	7000
रेखा देवी	बेलवव	बरबीघा	शेखपुरा	7000
ताराप्रविन	अकबरपुर	अकबरपुर	नवादा	7000
लुसी कुमार	काजीचक	बाढ़	पटना	8000
पल्लवी कुमारी	पियारेपुर	सरमेरा	नालंदा	6000
संगीता देवी	गोविन्दपुर	फतुहा	पटना	12000
अनीता कुमारी	घोसैठ	पिड़ी बाज़ार	लक्खीसराय	4000
रिक्कू कुमारी	गुलाबचक	हिल्साय	नालंदा	5000

feedback@chauthiduniya.com

अररिया: तस्कर कांप रहे हैं

राजधानी पटना के बाद सीमांचल के अररिया में भी एसपी शिवदीप लांडे सुर्ख़ियां बटौर रहे हैं. पदस्थापन के एक माह के अंदर आर्थिक अपराध करने वाले तस्कर, माफ़िया व सिंडिकेटों के गोदामों में छापामारी कर उन्होंने इनकी नींद हराम कर दी है. एक माह के अंदर ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों के गोदामों में छापामारी के ज़रिए करोड़ों रुपये की रासायनिक खाद व मिलावटी खाद्य सामग्री ज़ब्त की गई है.

एसपी की इस कार्रवाई से न केवल अररिया व फारबिसगंज के जमाखोरों के बीच घबराहट पैदा हुई बल्कि इंडो-नेपाल में फैले तस्करों के होश भी गुम हो गये. पहली छापामारी गत 7 दिसंबर को नेपाल सीमा से सटे कुआड़ी में खाद व्यवसायी के गोदाम में की गई.

एसपी लांडे ने गत 24 नवंबर 2011 को पदभार ग्रहण के दौरान कहा था कि मैं विशेष कार्य करने के लिए आया हूं. इस बात को ख़ासकर तस्कर, माफिया व सिंडिकेटों ने मजाक समझा. लेकिन 24 घंटे के अंदर उन्होंने तस्कर, जमाखोर, माफिया और सिंडिकेटों का परेशान कर दिया.

एसपी की इस कार्रवाई से न केवल अररिया व फारबिसगंज के जमाखोरों के बीच घबराहट पैदा हुई बल्कि इंडो-नेपाल में फैले तस्करों के होश भी गुम हो गये.

पहली छापामारी गत 7 दिसंबर को नेपाल सीमा से सटे कुआड़ी में खाद व्यवसायी के गोदाम में की गई. जिसमें करीब साढ़े तीन करोड़ मूल्य की खाद जब्त की गई. 8 दिसंबर को अररिया आरएस व शहर में छापामारी कर मिलावटी खाद्य तेल व मसाला कारोबारी के चेहरे को बेनक़ाब किया. इसमें क़रीब 7 करोड़ से अधिक मूल्य के सामग्रियों को बरामद किया गया. जिसकी जांच आज भी चल रही है. एसपी की कार्यशैली का एक नायाब नमूना यह भी है कि छापामारी के बाद वाणिज्यकर, आयकर, खाद्य निरीक्षक, आपूर्ति विभाग, कृषि विभाग भी हरकत में आ गए. इन विभागों के पदाधिकारी कुंडली मारकर ज़मखोरों के धन पर आनंद उठाते रहते थे. सबसे अहम जोगबनी स्थित इंट्रीगेटेड चेक पोस्ट पर अवैध उगाही करते एक कर्मी को भी दबोच कर भ्रष्टाचारियों के बीच सनसनी फैला दी. एक ओर जहां समाज का हर तबका उनकी कार्यशैली से बाग-बाग हैं, वहीं दूसरी ओर अपराधी, जमाखोर, तस्करों के बीच खलबली मची हुई है. दबी ज़ुबान से अगर कही जाए तो सिंडिकेट में शामिल कई सफ़ेदपोशों के भी नींद उड़ी हुई है.

उपेंद्र यादव
feedback@chauthiduniya.com

सारण एक नज़र

हिन्दी विद्यापीठ के सोलहवें वार्षिक महा अधिवेशन में विद्यासागर डीलिट की उपाधि दी गई, उन्हें यह सम्मान भोजपुरी साहित्य में पत्र पत्रिकन के विकास यात्रा पर शोध के लिए प्रदान किया गया. डॉ. जयकान्त सिंह जय, डॉ. ब्रजभूषण मिश्र, प्रो. ब्रजकिशोर, डॉ. जौहर शाफिया वादी, ज्योतिष पाडेय ...

नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर

श्रीभागवत कथा में उमड़े भक्त

जनहित में वित्तीय साक्षरता आवश्यक

वार्षिकोत्सव कार्यक्रम सम्पन्न

विश्वनाथ शर्मा को मिला डीलिट सम्मान

आरक्षण बिल की प्रतियां जलायीं

गोलबंद हुए पंचायत सचिव

विधान पार्षद ने किया सड़क का उद्घाटन

छात्र ही विद्यालय के एंबेसडर होते हैं

गरीबों की हर तरह से करेंगे मदद

सीवान में गरीबों के साथ हर कदम पर खड़े रहने के संकल्प के साथ ...

गोपालगंज में याद किये गये मजहरूल हक

18 सौ करोड़ की योजना

प्रस्तुति-शुभम रानी चौहान और मनीष कुमार कश्यप

भीम सिंह की घोषणा से भ्रष्ट अधिकारियों में हड़कंप

रिंकी सिंह

मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक, एलडब्लू से लेकर मुख्य सचिव और सिपाही से लेकर डीजीपी तक सभी लोकायुक्त अधिनियम 2011 के दायरे में हैं, जनता के हक़ के साथ जो अधिकारी व कर्मचारी खिलवाड़ करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध काफ़ी गंभीर है. जमुई के प्रभारी मंत्री डॉ. भीम सिंह के इस ऐलान से ज़िले के भ्रष्ट अधिकारियों में हड़कंप मच गया है.

जमुई समाहरणालय में आयोजित बीस सूत्रीय बैठक में पहली दफ़ा सूबे के ग्रामीण कार्य विभाग एवं पंचायती राज विभाग के मंत्री डॉ. भीम सिंह इस ज़िले के प्रभारी मंत्री बनने के बाद बैठक की कार्यवाही में शिरकत कर रहे थे. जब ग़रीब और विकलांग लोगों को सरकार की ओर से पेंशन के रूप में मिलने वाली आर्थिक मदद को कतिपय सरकारी कर्मियों के द्वारा डकारे जाने का मामला बीस सूत्रीय बैठक में उठाया गया तो फौरन प्रभारी मंत्री ने वरीय पुलिस अधिकारियों को उक्त मामले में त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया. मंत्री के आदेश पर जमुई थाना में कांड संख्या 213/11 में मामला दर्ज किया गया. वैसे जमुई ज़िले का सौभाग्य है कि डॉ. भीम सिंह जैसे ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ कबीना मंत्री यहां के प्रभारी मंत्री बने हैं, जिन्होंने पहली ही बैठक में वर्षों से उपेक्षित भगवान महावीर के जन्म स्थान को पर्यटन स्थल बनाने का निर्णय लिया है. जन्म स्थान को जाने वाली सड़क को चका-चक करने, महावीर जन्म स्थान को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के अहम फ़ैसले ने यह साबित कर दिया है कि प्रभारी मंत्री डॉ. भीम सिंह कार्यों में विश्वास करते हैं, कोरी घोषणाओं में नहीं. डॉ. भीम सिंह का मानना है कि यहां के सभी पर्यटन स्थलों को विकसित करने से क्षेत्र में विकास की गति और तेज़ होगी. इसके साथ ही साथ ज़िले सभी मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों को जाने वाली सड़कें जर्जर हैं तो उनकी मरम्मत होगी. इसके लिए ज़िला प्रशासन को सूची मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है.

feedback@chauthiduniya.com

नववर्ष की हार्दिक शुभकामनायें

M/S. BISHWANATH AGRAWAL
Gulabbagh - 854 326 Purnea (Bihar)
A House of Agro Inputs
Ph : 06454-234249, 234093 (Office)
Fax : 06454-232077
Mob : 9334181066
E-mail : bnaglb@rediffmail.com

डी.जे. फ्रूट्स
पूर्णिया सिटी
प्रो. युगल प्रसाद

एडवान्स डेन्टल हॉस्पिटल
डॉ. अनुराग कु. सिंह
B.D.S., M.I.D.A. (DELHI)

धारा रिफाईन ऑयल
मे अमित स्टोर्स
गुलाबबाग पूर्णिया

मे. अग्रवाल फर्टिलाइजर
गुलाबबाग, पूर्णिया
प्रो. बद्री अग्रवाल

निवेदक
मनोज कुमार चौधरी
समाजसेवी
गुलाबबाग, पूर्णियां

निवेदक नीरज खेमका (सचिव)
मारवाड़ी युवा मंच
गुलाबबाग पूर्णिया

भ्रष्टाचार मिटाओ बिहार बनाओ
K. Singh
VISION CLASSES
IIT-JEE
एक सपना
बिहार से भ्रष्टचार मिटाने का
प्रयास हमारा, योगदान आपका
नव वर्ष 2012 की आप सभी को
हार्दिक बधाई
बेहतर शिक्षा, एक विकल्प
आईये गर्व से कहें "हम बिहारी हैं"
मंथन
कंकड़बाग सेन्टर
कुंवर सिंह (एकेडमिक हेड)
बोरिंग रोड सेन्टर
Head Office: : In front of gate No. 2, Kendriya Vidayalaya, Kankarbagh, Patna-20, Ph: 0612-3265424, 6567270, 9204324122
Branch Office: : Jai Kamla plaza, near lalita Hotel, East Boaring Canal Road, Patna-01, Ph : 0612-3265423, 2532441

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

ददुआ गैंग को पकड़ने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपये फूंके. अपहरण, डकैतियों और पुलिस के तमाम जवानों की जाने लीं. दिन दहाड़े लोगों के घरों को फूंक दिया.

कल्याण की राम दरबार में दस्तक

राम जन्म भूमि का दर्षन करने पहुंचे कल्याण
तीर-कमान से बजाते चुनावी विगुल

22 दिसंबर को कल्याण सिंह अपने परिवार और जनक्रांति पार्टी के सदस्यों के साथ भगवा चादर ओढ़कर राम लला का दर्शन करने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी से 162 प्रत्याशियों की सूची भी जारी की और मिशन 2012 फतह के लिए भाजपा पर दोष मढ़ते हुए कहा कि भाजपा पुन: राम के नाम पर राजनीति करना चाहती है, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर वह मुस्लिम तुष्टिकरण नीति भी अपना रही है.

राकेश कुमार यादव

राम नाम की ओढ़ चदरिया कैसे तुझे भुलाऊं का गीत अयोध्या में एक बार फिर हिंदूवादी नेताओं के लिए सौगात बन गया है. हिंदूवादी विचारधारा से जुड़े नेता आम जनमानस में समस्याओं को भले ही न तरजीह दें लेकिन उन्हें यह पता है कि हिंदुत्व के नाम पर यदि राम के नाम को छोड़ दिया जाएगा तो उनका सियासी खेल चौपट हो जाएगा. यही वजह रही कि भाजपा समेत उनके सानिध्य में रहने वाले नेताओं ने भले ही अलग दल बना लिया है लेकिन राम के नाम को वह भुनाने से पीछे नहीं हटना चाहते है और अपने आप को हिंदुओं का असली रखवाला बताकर जनता के बीच में वहीं कहानी दोहराने के फ़िराक़ में दिख रहे हैं. उत्तर प्रदेश 2012 चुनावी मुहिम के समय एक बार फिर भाजपा ने जहां 16 नवंबर को अपनी जनस्वाभिमान यात्रा का समापन करने आए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कहा था कि अयोध्या में रामजन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग हाईकोर्ट के निर्णय से प्रशस्त हो गया है. अब प्रदेश की तकदीर बदलने के लिए राम–राज लाना है. जनता भाजपा को पूर्ण बहुमत दे तो उत्तर प्रदेश की तकदीर बदल देंगे.

वहीं 22 दिसंबर को भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भी अपने पुत्र, पोते सहित अपनी जनक्रांति पार्टी के सदस्यों के साथ भगवा चादर ओढ़कर राम लला का दर्शन करने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी से 162 प्रत्याशियों की सूची भी जारी किया और मिशन 2012 के फतह के लिए भाजपा पुन: राम के नाम पर राजनीति करना चाहती है लेकिन हिंदुत्व के नाम पर वह मुस्लिम तुष्टीकरण नीति भी अपना रही है. यह सरासर जनता के साथ खिलवाड़ है. यदि जनता के साथ भाजपा होती तो अपने एजेंडे में हिंदुत्व को ही शामिल करती लेकिन अब राम के स्थान पर जिन्ना का शब्द यह बतलाता है कि भाजपा को सत्ता चाहिए, राम से कोई मतलब नहीं.

कल्याण सिंह ने बसपा, कांग्रेस व सपा को विरोधी और भाजपा को छद्म हिंदूवादी बताते हुए कहा कि हिंदुत्व राष्ट्र का प्राण तत्व है अगर यह कमजोर हुआ तो राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हौसले बुलंद होंगे. सिंह यहां पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे. उन्होंने कहा कि भाजपा ने सिर्फ़ सत्ता प्राप्ति के लिए हिंदू व भगवान राम के नाम का उपयोग किया है. सभी दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सभी मुस्लिम वोट के लिए मुसलमानों की अलग से आरक्षण देने की बात कह रहे हैं. आज भाजपा की नीतियों की व्याख्या भी उनके मुस्लिम प्रवक्ता ही करने लगे हैं. उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन से इन्कार करते हुए कहा कि बहुमत न मिलने पर वे विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे.

अपने अयोध्या यात्रा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि, कनक भवन व हनुमानगढ़ी में अपने प्रत्याशियों के साथ जाकर चुनाव में विजयी होने का आशिर्वाद लिया. इस दौरान उनके साथ उनके पुत्र राजवीर सिंह, उनका पोता संदीप सिंह, पूर्व विधान परिषद सदस्य वीरसेन, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीएल वर्मा, राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र कुमार, फ़ैज़ाबाद जिलाध्यक्ष ज्ञान केसरवानी समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे. सिंह बाद में नाका हनुमानगढ़ी विराजमान हनुमानजी का दर्शन पूजन कर श्रीराम जन्मभूमि के पक्षकार महंत भास्कर दास व उत्तराधिकारी रामदास से भी मिले. हालांकि इस दौरे में कल्याण के साथ वहीं चेहरे दिखे जो कभी भाजपा का झंडा ढ़ोते थे. इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें भेंट में दिए गए धनुष–बाण थामकर चुनावी बिगुल का शंखनाद किया.

feedback@chauthiduniya.com

सर्थ चुनाव लड़ेगा

क़रीब तीस वर्षों तक बीहड़ों में उत्तर प्रदेश की पुलिस को छकाने वाला दस्यु सम्राट ददुआ का दाहिना हाथ रहा राधे पटेल इन दिनों जेल में है. ददुआ गैंग के मारे जाने में वही एक मात्र पुलिस से बच सका था. जिसे पुलिस ने जिंदा पकड़ा. कहते हैं कि दस्यु ददुआ की एक आवाज़ पर कई सांसद और विधायक चुनाव जीतकर विधानसभा और लोकसभा में पहुंचते थे. चुनावों के दौरान उसकी तूती बोलती थी. लेकिन मायावती सरकार के आते ही ददुआ पर नज़र पड़ी. दुर्दांत ददुआ का बीहड़ों में पीछ कर रहता था. कठिन प्रयास के बाद तीस वर्षों तक राज्य कर रहे ददुआ को उत्तर प्रदेश पुलिस मारने में कामयाब रही. डकैत ददुआ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर लाखों का ईनाम रखा था लेकिन ददुआ राजनीतिज्ञों के बीच पैठ होने के कारण बहुत वर्षों तक अपराध करता रहा और अपने लोगों को चुनाव में जिताता रहा. ददुआ गैंग को पकड़ने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपये फूंके. अपहरण, डकैतियों और पुलिस के तमाम जवानों की जाने लीं. दिन दहाड़े लोगों के घरों को फूंक दिया, लेकिन मायावती सरकार की यह सफ़लता ही कही जाएगी जब ददुआ जैसे दुर्दांत दस्यु और उसके गिरोह का सफ़ाया कर दिया. यह पहला अवसर है जब बीहड़ों में दस्युओं का असर इस बार के चुनाव में कमांडर रहे सूबेदार सिंह उर्फ राधे पटेल ने विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है. अपना यह इरादा उसने जेल में रहकर बनाया है. उसने किसी दल विशेष के राजनीतिज्ञों का नाम लिए बिना कहा कि उसने जिन लोगों पर इतने उपकार किए हैं. आज कोई उसकी मदद के लिए खड़ा नहीं दिख रहा है. उसके परिवार को सताया जा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है. पेशी पर अदालत में लाए गए दस्यु राधे ने लिखित रूप से विज्ञप्ति में साफ़ कहा कि अगर किसी दल ने उसे टिकट नहीं दिया तो वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेगा. अगर इसे कोर्ट से अनुमति नहीं मिली तो वह परिवार के किसी सदस्य को चुनाव में खड़ा करेगा. राधे ने मऊ या कर्वी अथवा बांदा के बबेरू विधानसभा से चुनाव मैदान में उतरने की मंशा जताई है.

दर्शन शर्मा, लखनऊ ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

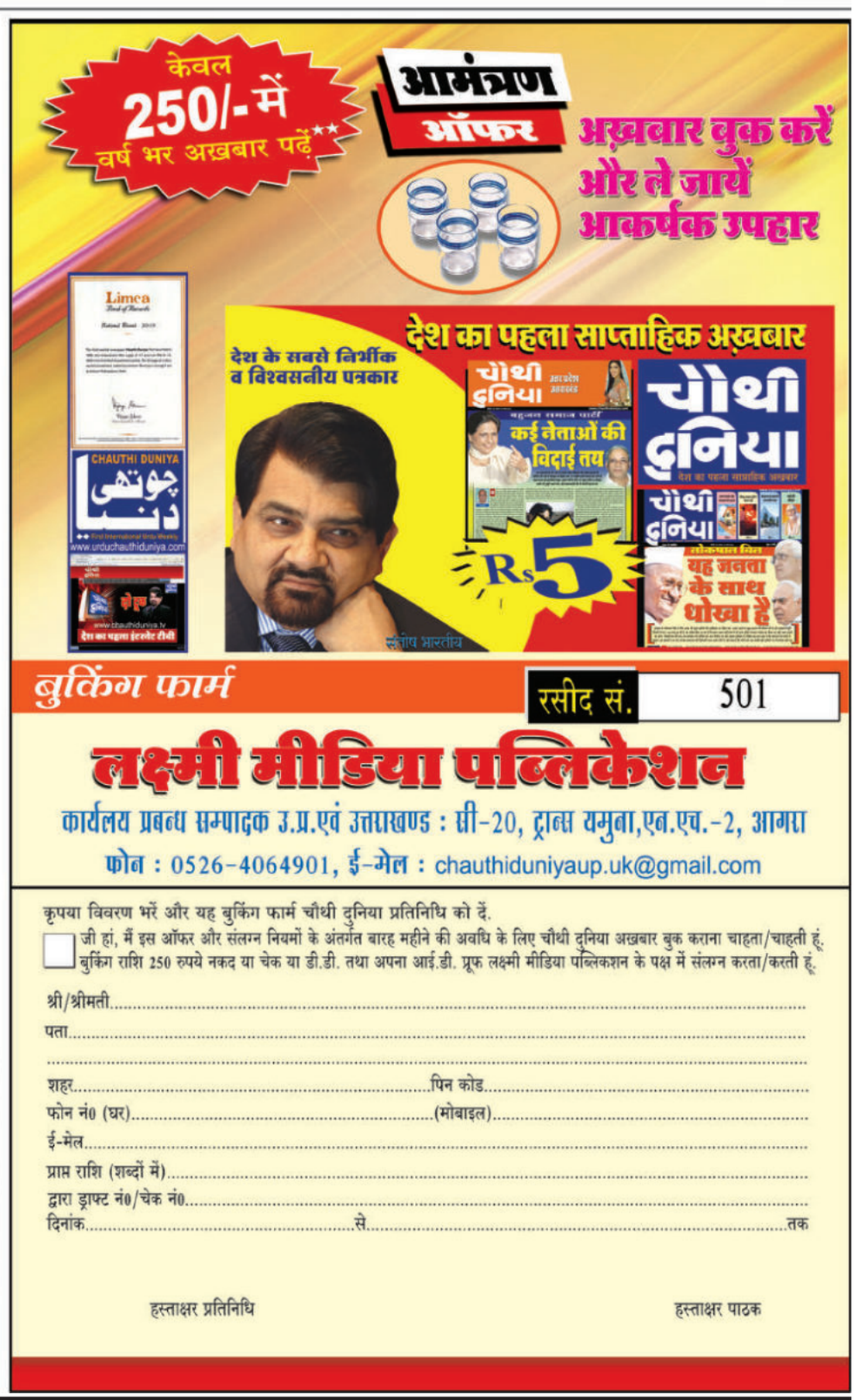

उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के सभी ज़िलों में वितरण एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें : श्रीनिवास गुप्ता (ठाकुर), प्रबंध संपादक : 09837082462

समाजवादी पार्टी की शुरूआती सूची में संतोष पांडेय उम्मीदवार घोषित किए गए. कुछ दिनों बाद उनकी जगह उनके अग्रज अनिल पांडेय को मौक़ा मिला.

कांग्रेस पर भड़की मायावती

खरी बात सुनाने वाली मायावती आज तक हर किसी पर हावी होने की ही सोचती रही हैं. हार हो या जीत, सामने वाले की बोलती बंद कर देना उनके मिजाज में है. वह ईंट का जवाब पत्थर से देती हैं. बात अतिथिगृह कांड की लीजिए. इस कांड के बाद मायावती की जब-जब सरकार बनी तो मायावती और मुलायम के बीच सदन के अंदर तक द्वंद्व छिड़ा. माया- मुलायम के विधायक एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हुए.

बसपा सरकार और केंद्र सरकार में तू डाल-डाल, मैं पात-पात की सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है. प्रदेश में चुनाव सामने देख कांग्रेस और बसपा में घमासान आज से नहीं क़रीब एक साल से लगातार जारी है. कभी सोनिया को लेकर मायावती भड़की तो कभी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी का घर जलने पर उल्टे जेल की सलाख़ों तक पहुंचाने की बातें होती रहीं. राहुल का दलितों के घर जाना मायावती को हमेशा खटकता रहा है. खरी बात सुनाने वाली मायावती आज तक हर किसी पर हावी होने की ही सोचती रही हैं. हार हो या जीत, सामने वाले की बोलती बंद कर देना उनके मिजाज में है. वह ईंट का जवाब पत्थर से देती हैं. बात अतिथिगृह कांड की लीजिए. इस कांड के बाद मायावती की जब-जब सरकार बनी तो मायावती और मुलायम के बीच सदन के अंदर तक द्वंद्व छिड़ा. माया- मुलायम के विधायक एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हुए. धक्का मुक्की के बीच मायावती तो सुरक्षित निकल गईं लेकिन इसके बाद सरकार बनने पर उन्होंने इन विधायकों की जमकर ख़बर ली जिन्होंने उनके साथ उत्पात मचाया था. किसी को सीधे जेल भिजवाया वहीं मुलायम सिंह को कभी उबरने का मौक़ा न दिया. वह मुलायम से इतना क्रोधित रहीं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में न बैठकर दिल्ली की लोकसभा में बैठना उचित समझा. अपने हठीले और क्रुद्ध स्वभाव के चलते उनके ब्यूरोक्रेट तक जूती पहनाते नज़र आए. वहीं आईपीएस और आईएएस नतमस्तक होते दिखे.

सोशल इंजीनियरिंग के बल पर विशाल बहुमत में आई मायावती का सिर्फ़ एक ही कार्य रहा कि अपने महापुरूषों की मूर्तियां और पार्टी चिन्ह हाथी की मूर्तियां बड़े-बड़े पार्कों में स्थापित करना. हठीली मायावती ने विपक्ष को बौना कर दिया. अपने नजदीक ऐसे अफ़सरों को रखा, जो उनकी हर बात का पालन करवा सकें. इस मिजाज ने प्रदेश के मज़लूम, ग़रीबों को ताख़ पर रख दिया. यह बातें विपक्ष को अखरती रहीं, विपक्ष कमज़ोर होने से मायावती का दांव हमेशा भारी पड़ता रहा. सत्र लंबे नहीं चले. विकास कार्यों के लिए सदन के अंदर पूरी चर्चा ही नहीं की गई. इसे लोकतंत्र का उपहास माना गया. पूरे पांच वर्ष मायावती का एक छत्र शासन अपने लिए या अपने लोगों के लिए ही चलता रहा. यह विपक्ष के लोगों का मानना है कि बसपा सरकार सिर्फ़ मुट्ठी भर लोगों को फ़ायदा देने तक ही सीमित रही है. मंहगाई को लेकर मायावती सरकार ने केंद्र पर ही ठीकरा फोड़ने की कोशिश की, भले ही वह केंद्र सरकार में समर्थन दे रही हो. विकास के नाम पर प्रधानमंत्री को चिट्ठियां दर चिट्ठियां भेजनी शुरू कर दी. शीतकालीन विधानसभा सत्र में मायावती सरकार ने ऐसा पैंतरा चलाया कि विपक्ष के हौसले धरे के धरे रह गए और 16 मिनट में ही लेखानुदान और राज्य विभाजन विधेयक पारित करवाकर सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया. सरकार की तरफ़ से इसे संवैधानिक रूप से पारित विधेयक बताया गया. वहीं विपक्ष और मीडिया में इस सत्र की जमकर आलोचना की गई. हालांकि यह पहला अवसर नहीं था, जब किसी सरकार ने क्षण भर में प्रस्ताव पेश कर विपक्ष से किनारा कर लिया हो. लेकिन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के लिए शर्मनाक था. बिना चर्चा के उत्तर प्रदेश के चार खंड कर दिए गए और मायावती ने सियासती दांव खेलते हुए उत्तर प्रदेश के विभाजन की संस्तुति की गेंद केंद्र के पाले में डाल दी. नए राज्यों के गठन की बढ़ती मांग के मद्देनज़र सरकार ने लोकसभा में बताया कि संबंधित राज्य में इस मामले में व्यापक सर्वसम्मति होने तथा सभी प्रासंगिक तत्वों पर विचार के बाद ही केंद्र इस दिशा में आगे बढ़ता है. गृह राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि किसी भी नए राज्य के गठन के व्यापक प्रभाव होते हैं और इसका सीधा असर देश की संघीय व्यवस्था पर पड़ता है. उन्होंने कहा कि संबंधित राज्य में इस मामले में व्यापक सर्वसम्मति होने तथा सभी प्रासंगिक तत्वों पर विचार के बाद ही केंद्र इस दिशा में आगे बढ़ता है. मंत्री की यह टिप्पणी आंध्र प्रदेश में अलग तेलंगाना राज्य के गठन तथा उत्तर प्रदेश को चार राज्यों में विभाजित करने के लिए प्रदेश विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने की पृष्ठभूमि में आई है.

बसपा सरकार ने प्रदेश के विभाजन के मुद्दे पर केंद्र के सवालों को अनावश्यक ऐतराज करार दिया हैं. मुख्यमंत्री मायावती का कहना रहा कि केंद्र सरकार राज्य के विभाजन का मामला लटकाना चाहती है. विभाजन के प्रस्ताव पर उसके द्वारा भेजा गया पत्र संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन है, इसका समुचित जवाब दिया जाएगा. वास्तव में केंद्र यदि गंभीर है तो वह तो वह उत्तर प्रदेश पुनर्गठन के संबंध में वही प्रक्रिया अपनाए जो उत्तराखंड के गठन के लिए अपनाई गई थी. अगर केंद्र सरकार से संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत राज्य पुनर्गठन विधेयक प्राप्त होता है, तो इसे राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाएगा. केंद्र सरकार को यूपी को पत्र भेजने के बजाए राष्ट्रपति के माध्यम से उत्तर प्रदेश विधानमंडल से संवाद करना चाहिए. पत्र से मीडिया के माध्यम से ग़लतफ़हमी पैदा की जा रही है कि प्रदेश सरकार ने राज्य के पुनर्गठन के संबंध में जो कार्रवाई की है, इसमें कमियां हैं. राज्य विभाजन पर भाजपा का कहना है कि इसपर मायावती का पाखंड उजागर हुआ है. इससे साबित होता है कि बसपा व कांग्रेस में नूराकुश्ती चल रही है. वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि राज्य विभाजन का मामला अब केंद्र व प्रदेश के बीच फुटबॉल बन गया है. कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रीता बहुगुणा जोशी का कहना है कि केंद्र को प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार है. जनमत संग्रह कराने के बाद ही इस पर कोई निर्णय होना चाहिए. बीस करोड़ लोगों के भविष्य का फ़ैसला जल्दबाज़ी में नहीं होना चाहिए. मायावती ने पांच साल तक नाटक किया. चर्चा कराने तक की ज़रूरत नहीं समझी और चुनाव से ठीक पहले केंद्र को एक लाइन का प्रस्ताव भेज दिया. कांग्रेस भी छोटे राज्यों की पक्षधर है लेकिन इससे पहले जनता की राय और इससे जुड़े हर पक्ष पर विमर्श भी ज़रूरी है. बहरहाल मुख्यमंत्री मायावती का कहना है कि राज्य विभाजन का प्रस्ताव केंद्र सरकार ने लौटाया नहीं है. केवल कुछ मुद्दों पर जानकारी मांगी है. इसके पूर्व भी पृथक राज्य बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को 2007 में भेजा गया था और इसके बाद भी कई बार अनुरोध किया गया. जब केंद्र ने कुछ नहीं किया तो राज्य का प्रस्ताव विधानमंडल से पास कराकर भेजा गया ताकि केंद्र सरकार पर दबाव बन सके लेकिन केंद्र के लिए इस प्रस्ताव का कोई मतलब ही नहीं रह गया है.

दर्शन शर्मा, लखनऊ ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राहुल का मिशन अजित पूरा करेंगे

पृष्ठ संख्या 17 का शेष

बड़ा कारण अनुराधा चौधरी के वर्चस्व वाली विधानसभा सीटों को कांग्रेस के लिए छोड़ा जाना है. एक तरफ़ अनुराधा और अजित के बीच रूठने-मनाने का दौर चल रहा है तो दूसरी तरफ़ ख़बरें ऐसी भी आ रही हैं कि अनुराधा भाजपा नेताओं के संपर्क में भी हैं. अनुराधा के क़रीबी कहते हैं कि वह अपने फ़ायदे के लिए भाजपा के साथ क्यों नहीं जा सकती. आख़िर कोई कितना त्यागकर सकता है. अजित को मंत्रिमंडल में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़े वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता रशीद मसूद को कांग्रेस में शामिल करके कांग्रेस ने प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा की सवा सौ से ज़्यादा सीटों पर अपने प्रभावी प्रदर्शन की तैयारी कर ली है. इस गठबंधन से कांग्रेस को जहां रालोद से जुड़े जाट और मुस्लिम मतदाताओं के वोट मिलने की उम्मीद है, वहीं अजित भी कांग्रेस के वोट बैंक से अपना लाभ होते देख रहे हैं. फिलहाल उत्तर प्रदेश विधानसभा में रालोद के 10 और कांग्रेस के 22 सीटें हैं. इस गठबंधन पर चुटकी लेने वाले भी कम नहीं हैं. कोई इसका कार्यकाल छह माह बता रहा है तो कोई साल भर. ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो सोचते हैं कि कांग्रेस यूपी में फाइट में है ही नहीं. इन लोगों का कहना है कि सपा को कमजोर करने के लिए मायावती कांग्रेस को मजबूत दिखाने का नाटक कर रही हैं. असलियत में वह समाजवादी पार्टी को ही अपना प्रतिद्वंद्वी मानती हैं. राहुल और मायावती की जुबानी जुबा ख़र्च से सपा फ्रंट पर नहीं आ पा रही है जो उसके लिए नुक़सानदायक साबित हो सकता है. गठबंधन के मामले में अजित सिंह पर अक्सर निशाना साधा जाता रहा है. पिछले दिनों पीस पार्टी के साथ ही लगभग एक दर्जन स्थानीय पार्टियों ने एक मोर्चा बनाकर इसकी कमान रालोद नेता को सौंपी थी ताकि विधानसभा चुनावों में बड़े दलों को धूल चटाई जा सके लेकिन अजीत ने इस मोर्चे को बिना बताए ही अकेला छोड़ दिया. अजीत पर यह आरोप भी लगते रहे हैं कि वह एक समय में कई दलों से बातचीत कर रहे होते हैं. इस तरह के आरोपों को तब और बल मिला था जब हाल ही में विकीलीक्स ने ख़ुलासा किया था कि वर्ष 2008 में परमाणु करार के विरोध में होने की बात कहने वाले रालोद सांसदों को सरकार का समर्थन करने के लिए 10-10 करोड़ रुपए दिए गए थे.बहरहाल, जो हालात बन रहे हैं इससे तो यही लगता है कि कांग्रेस अपने युवराज का मिशन 2012 अजित के कंधे पर बैठकर पूरा करना चाहती है. अकेले चलने में उसके हाथ-पांव फुलने लगते हैं.

feedback@chauthiduniya.com

प्रत्याशी बदलने का रिकॉर्ड

सपा की शुरूआती सूची में संतोष पांडेय उम्मीदवार घोषित किए गए. कुछ दिनों बाद उनकी जगह उनके अग्रज अनिल पांडेय को मौक़ा मिला. संतोष पांडेय समर्थकों ने दबाव बनाया तो पार्टी ने अनिल पांडेय की जगह फिर संतोष की उम्मीदवारी तय कर दी. संतोष के प्रत्याशी बन जाने पर दूसरे उम्मीदवारों ने अपनी अपनी ताक़त लगानी शुरू कर दी.

विधानसभा चुनाव में बसपा ने सबसे पहले उम्मीदवार घोषित किए थे, दूसरा नंबर रहा समाजवादी पार्टी का, तीसरे स्थान पर कांग्रेस और चौथे स्थान पर भाजपा ने अपने उम्मीदवारों को किश्तों में उतारना शुरू किया. इसी तरह छोड़ी पार्टी किश्तों में सूचियां जारी करती रहीं लेकिन प्रत्याशी अदला बदली में जितनी जद्दोजहद समाजवादी पार्टी को करनी पड़ी, उतनी शायद अन्य दूसरी पार्टियों को नहीं करनी पड़ी हो. सपा एक-एक सीट पर प्रत्याशियों का दबाव और असंतोष झेलना पड़ा. कहीं-कहीं टिकट न मिलने पर प्रत्याशियों ने गुस्सा जनसभाओं के दौरान उतारा, वहीं सपा सुप्रीमो तक प्रत्याशियों की शिकायतें पहुंची लेकिन सुल्तानपुर ज़िले की लंभुआ विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशियों की सात-सात बार अदला बदली सपा के लिए एक नया रिकॉर्ड साबित हुई है. दरअसल लंभुआ सीट मामला यूं रहा. पिछले छह महीनों में इस क्षेत्र में सात उम्मीदवार बदल चुकी सपा असमंजस में पड़ गई है कि किस तरह प्रत्याशियों की बार बार अदला बदली से निजात पाई जा सके. क्षेत्र में संतोष पांडेय, अनिल पांडेय, इंदु प्रकाश मिश्र और सुरभि शुक्ल की सपा उम्मीदवार के रूप में होर्डिंग और प्रचार सामग्री स्थान-स्थान पर लगी हुई है. सपा की शुरूआती सूची में संतोष पांडेय उम्मीदवार घोषित किए गए. कुछ दिनों बाद उनकी जगह उनके अग्रज अनिल पांडेय को मौक़ा मिला. संतोष पांडेय समर्थकों ने दबाव बनाया तो पार्टी ने अनिल पांडेय की जगह फिर संतोष की उम्मीदवारी तय कर दी. संतोष के प्रत्याशी बन जाने पर दूसरे उम्मीदवारों ने अपनी अपनी ताक़त लगानी शुरू कर दी. टिकट पाने की होड़ में लगे इंदु प्रकाश मिश्र ने ताक़त लगाकर संतोष पांडेय का टिकट कटवाकर अपनी उम्मीदवारी का दावा ठोंक दिया लेकिन क्षेत्र में इंदु प्रकाश मिश्र प्रचार प्रसार कर पाते इससे पहले सुरभि शुक्ल ने फिर अपनी टिकट की दावेदारी पेश कर सूची में नाम दर्ज करा दिया. एक दूसरे को टिकट से वंचित करने का दौर निरंतर जारी रहा. कोई पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था. दबाव के चलते सुरभि शुक्ल का विरोध होना शुरू हो गया तो दो बार वंचित किए गए संतोष पांडेय फिर टिकट की दौड़ में आ गए. तीसरी बार टिकट पाए संतोष को टिकट पाने की प्रक्रिया पूरी भी नहीं हो पाई थी कि पार्टी नेतृत्व ने दबाव में आकर अपना फ़ैसला बदलते हुए कद्दावर प्रत्याशी सुरभि शुक्ल को पुन: सातवीं बार टिकट दे दिया. बहरहाल उत्तर प्रदेश में सत्ता पाने की गंभीर दावेदार समाजवादी पार्टी लंभुआ विधानसभा क्षेत्र में बार-बार प्रत्याशी बदलने के लिए हंसी का पात्र बनी हुई है. लंभुआ के सपा कार्यकर्ता उम्मीदवारों की अदला-बदली से थक चुके हैं. कुछ यादव उम्मीदवार सपा सुप्रीमो के पास शिकायत लेकर पहुंचे कि बार-बार उम्मीदवार को क्यों बदला जा रहा है. यादवों को टिकट क्यों नहीं दिया जा रहा है.

हालांकि लंभुआ क्षेत्र से आमतौर पर ठाकुर प्रत्याशियों का हीं वर्चस्व रहा हैं. यहां के ब्राह्मण मतदाता संगठित रूप से चुनौती देते हैं. इस समय बसपा के विनोद सिंह इस सीट पर क़ाबिज़ है. प्रदेश में पर्यटनराज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है. सपा यहां से ब्राह्मण उम्मीदवार उतारती रही है. 2002 में इस क्षेत्र में इकलौती क़ामयाबी उसे ब्राह्मण उम्मीदवारों से ही मिली थी. सपा इस बार भी इसी रणनीति को अपनाना चाहती है लेकिन उम्मीदवारों के चयन के चक्कर में सात-सात बार उम्मीदवारों की अदला बदली पास हो गई है. सपा कार्यकर्ताओं को कहना है कि ऐसे प्रत्याशी का चयन नहीं होना चाहिए जिन पर पार्टी को ख़ुद ही भरोसा न हो. इतने प्रत्याशियों की अदला बदली से लंभुआ सीट का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बन गया है. देखना यह है कि अगला प्रत्यासी कौन उभरकर आता है या सातवीं बार के प्रत्यासी से ही विराम लग जाएगा.

दर्शन शर्मा, लखनऊ ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

अजय कुमार , लखनऊ ब्यूरो प्रमुख कार्यालय का पता : जे-3/2 डॉलीबाग़, हजरतगंज, लखनऊ-226001, फोन -(0522) 2204678/09415005111

मुख्यमंत्री खंडूरी ने जनता के हित की बात कर राजनीति की रोटी सेंकने के लिए रोलबैक किया. इस बाबत मुख्य सचिव सुभाष कुमार का कहना है कि सरकार ने व्यापक जनहित में यह क़दम उठाया है.

बसपा ने जारी किया श्वेत पत्र

अमिताभ आकाश

मुख्यमंत्री मायावती ने जिस तरह आनन–फानन में उत्तर प्रदेश को चार भागों में विभाजित करने की घोषणा की, फिर विधानसभा में चतुराई से प्रस्ताव भी पारित करा लिया, इससे उन्हें लग रहा था कि आगामी चुनाव में नया राज्य निर्माण मुद्दा बनेगा और इसका चुनावी फ़ायदा बसपा को ही मिलेगा. यह सच है कि राज्य विभाजन का मुद्दा अब मुख्य मुद्दा बन चुका है लेकिन इसका फ़ायदा बसपा को मिलता नहीं दिख रहा है. बसपा के शासनकाल में भ्रष्टाचार का ग्राफ तेजी से बढ़ा है. यह आरोप महज विपक्षी दलों की रणनीति का हिस्सा मात्र नहीं है, बल्कि इस तथ्य को मतदाता भी महसूस कर रहा है. ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री इससे अनजान है. मायावती को मिली ख़ुफ़िया जानकारी ने उनकी बैचेनी और बढ़ा दी है. निजी टीवी चैनलों पर चुनावी सर्वेक्षण रिपोर्टों में समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में काफ़ी बढ़त लेने की संभावना बताई जा रही है. वहीं सत्ताधारी बसपा को भारी नुक़सान होने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है. मीडिया रिपोर्टों और ख़ुफ़िया सूचनाएं दोनों बसपा के ख़िलाफ़ होने से बसपा सुप्रीमो मायावती काफ़ी आहत है, डैमेज कंट्रोल के लिए उन्होंने अपने कार्यकाल में लिए गए फ़ैसलों पर सफ़ाई प्रस्तुत करने का प्रयास शुरू कर दिया है. विपक्षी दलों के भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों के आरोपों के जबाव में अपने कार्यकाल में लिए गए फ़ैसलों को जायज बताते हुये श्वेतपत्र जारी किया गया है. उनका दावा है कि सभी फ़ैसले पारदर्शी, सही और नियमों के अनुरूप है. जहां शिकायत मिली अथवा गड़बडी की जानकारी मिली, दोषियों के ख़िलाफ़ सख्त कारवाई की गई. मुख्यमंत्री के आदेश पर उत्तर प्रदेश के आलाअधिकारियों ने माथापच्ची कर के बसपा कार्यकाल में हुए कार्यकलापों और सरकारी फैसलों पर 84 पेज का श्वेतपत्र तैयार किया. मायावती द्वारा जारी किए गए श्वेतपत्र में सरकार ने 24 विभागों के फ़ैसलों पर सफ़ाई देते हुए विपक्षी दलों से मांग की है कि उन्हें भी अपनी सरकार के कार्यकाल में घोटाले पर श्वेतपत्र जारी करना चाहिए. मुख्यमंत्री की ओर से कैबिनेट सचिव शशांक शेखर सिंह ने श्वेतपत्र जारी किया. उन्होंने सरकार के साढ़े चार साल के कामकाज का लेखा जोखा मंत्रीपरिषद की स्वीकृति के बाद ही प्रस्तुत किया. उत्तर प्रदेश की बसपा सरकार पर लगे सबसे बड़े आरोपों में से एक आरोप ऊर्जा क्षेत्र में बिजली परियोजना को लेकर भाजपा नेता किरीट सौमेया ने लगाया था. उनका आरोप था कि प्रदेश में बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र से बिजली की ख़रीद की गई यही नहीं विद्युत वितरण में अनिमितताएं बरती गई. श्वेतपत्र में कहा गया है कि बिजली की ख़रीद निविदा के आधार पर ही की गई थी, बिडिंग गाइडलांइस के अनुसार निविदापत्र तैयार कर विघुत नियामक आयोग से गठन कराया गया. न्यूनतम दर वालों की एनर्जी टास्क फोर्स ने पहले संस्तुति और बाद में कैबिनेट से इसकी मंजूरी ली गई. मुख्यमंत्री पर लगा दूसरा सबसे बड़ा आरोप यह भी था कि उन्होंने महापुरूषों के स्मारक और मूर्तियां के लिए सरकारी धन का दुरूपयोग किया और समानों में भारी कमीशनबाज़ी की गई. इसे लेकर जनता के अरबों रुपये फुंक डाले, जबकि इस धन का उपयोग प्रदेश के विकास के लिए किया जा सकता था. श्वेतपत्र में इसका जबाव देते हुए प्रदेश सरकार ने सफ़ाई दी है कि ख़र्च का बजट बाकायदा विधानसभा में पास कराया गया और मूर्तियों की ख़रीद नियमानुसार ही की गई. साथ में तर्क दिया गया है कि पत्थर के प्रयोग से हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया गया. बसपा के शासनकाल में शराबमाफ़िया का संबंध मुख्यमंत्री से होने का आरोप लगता रहा है. राजनीतिक हलकों में यह बात फैली हुई है कि इस खेल में मुख्यमंत्री का नज़दीकी सांइलेंट पार्टनर है. विपक्ष का आरोप है कि शराब का कारोबार एक व्यापारी को सौंपा गया. व्यापारी के हित में आबकारी नीति में बदलाव भी किया गया. श्वेतपत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री द्वारा इसका जबाव दिया गया कि आबकारी राजस्व बढ़ाने के लिए यह तय हुआ है कि अर्धसरकारी तंत्र के रूप में उत्तर प्रदेश चीनी संघ को लिया जाए. इसे किसी भी निजी क्षेत्र से ज्वांइट बेंचर करने का अधिकार सौंपा गया है. शराब का पूरा कारोबार किसी एक के हाथ में नियंत्रित नहीं हुआ. शराब वितरण के लिए तय शर्तों को पूरा करने के बाद ही ब्लू वाटर हार्वेस्टिंग को दिया गया. इससे प्रदेश में शराब के राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय ब्रांड उपलब्ध हो गए. विपक्षी दलों द्वारा बसपा सरकार पर खाद्यान्न घोटाले को लेकर काफ़ी होहल्ला उत्तर प्रदेश विधानसभा में मचाया गया था, जो समाचारपत्रों की सुर्खियां में भी छाया रहा. प्रदेश सरकार पर आरोप था कि उसने पीडीएस के तहत अनाज खुले बाज़ार में बेच दिया. बसपा सरकार ने इसका बचाव करते हुए कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार का मामला सामने आने पर 27 जून 2007 और 26 अप्रैल 2008 को विभिन्न ज़िलों के जांच एजेंसियों से जांच कराई गई. जांच के बाद सात आयुक्तों के अलावा 75 छोटे बड़े अधिकारियों, कर्मचारियों के विरूद्व कारवाई की गई. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार पर औद्योगिक समूह को फ़ायदा पहुंचाने का गंभीर आरोप लगा था. नोयडा और ग्रेटर नोयडा में नियमों का उल्लंघन कर फॉर्महाउस के लिए ज़मीन आवंटित की गई. किसानों की ज़मीन को अधिकृत कर ख़ास लोगों को फ़ायदा पहुंचाया गया. अपनी भूमि को जबरन अधिग्रहण से बचाने के लिए किसानों ने आंदोलन भी किया. केंद्र सरकार की ओर से भी उत्तर प्रदेश सरकार के तौर–तरीक़ों पर आपत्ति की गई थी. स्वयं राहुल गांधी ने किसानों के हक़ में मायावती सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की थी. इसी भूमि अधिग्रहण को लेकर केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण क़ानून लाने के लिए बाध्य हुई. इसे लेकर प्रदेश सरकार की ओर से सफ़ाई पेश की गई है कि संबंधित प्राधिकरण द्वारा ज़मीन का आवंटन नियमानुसार किया गया. कई बार प्राधिकरणों द्वारा किसी क्रियाविशेष को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यकता के अनुसार शुल्क या ज़मीन अर्जन दरों पर ही ज़मीन आवंटित होती है. सरकारी योजना मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगे थे कि इसमें धन का दुरूपयोग किया गया और अपात्र लोगों को राशि का भुगतान भी किया गया. योजना का धन अन्यत्र इस्तेमाल किया गया, इसके अलावा अनेकों गड़बड़ियां भी प्रकाश में आई. मनरेगा में हुई गड़बड़ियों के मद्देनज़र जवाब में बताया गया है कि प्रदेश सरकार द्वारा इसकी जांच कराए जाने पर 117 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई. इसके अलावा 57 मामलों में चार्जशीट दर्ज की गई है, बाक़ी 55 मामलों में पुलिस की विवेचना होनी है. जांच में पाए गए 78 आरोपियों को जेल भेजा गया. दो डीएम, 6 सीडीओ, 7 परियोजना अधिकारी, 28 ग्राम प्रधान पर अनुशानात्मक कार्यवाही की गई. शिकायतों की जांच कर के 58 लाख 84 हज़ार वसूले गए. विपक्षी दलों द्वारा चीनी घोटाले को लेकर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए गए थे कि उसने चीनी मिलों को कौड़ियों के भाव बेच दिया, ऐसा जानबूझकर किया गया. उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी श्वेतपत्र में इसका जबाव दिया गया है कि चीनी मिलों के विनिवेश का विभीन्न माध्यमों से मुल्यांकन किया गया. इसके बाद निजी कंपनी का चयन किया गया. कैबिनेट ने मिलों को बेचे जाने के लिए मूल्य की मंजूरी दी.

मुख्यमंत्री द्वारा जारी किए गए श्वेतपत्र में जो सफ़ाई पेश की गई है इससे उनकी परेशानियां कहीं से कम होती नहीं दिखाई दे रही है. टीवी चैनलों ने आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट मिलने का दावा किया है. इधर ख़ुफ़िया जानकारियों ने मुख्यमंत्री की घबराहट बढ़ा दी है तो बसपा के कार्यकर्ता भी परेशान हैं कि इस बार बहिनजी दुबारा सत्ता हासिल कर पाएंगी या नहीं क्योंकि जनसाधारण के बीच में रहने वाले कार्यकर्ता मतदाताओं की नाराज़गी को भली–भांति समझते हैं. दूसरी तरफ़ पार्टी के मंडल स्तर के नेताओं का कहना है कि सब कुछ ठीक है, बसपा दुबारा प्रदेश की सत्ता हासिल करेगी. पिछले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी. बड़े–बड़े सियासत के खिलाड़ी बसपा की सफ़लता से आश्चर्यचकित रह गए थे. हालांकि यह फॉर्मुला मायावती का नहीं था, बल्कि बसपा के संस्थापक कांशीराम की राजनीतिक चिंतन का प्रमुख अंग था जिसमें उन्होंने भारत की वर्णव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सत्ता की चाबी हासिल करने का तरीक़ा खोज निकाला था. उन्होंने अनुसूचित जाति–जनजाति, पिछड़ी जातियों के साथ अल्पसंख्यकों के राजनीतिक गठजोड़ को लेकर बहुजन समाज की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया था. उनकी मृत्यु के बाद बसपा की मुखिया बनीं मायावती ने उनके मिशन को पलीता भले ही लगा दिया हो लेकिन सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मुला सत्ता प्राप्त करने के लिए बख़ूबी किया. वह अचानक बहुजन से सर्वजन हो गईं, पिछले चुनाव में उन्होंने ब्राह्मणों को सर्वाधिक टिकट देकर पार्टी का धुर समर्थन हासिल कर लिया. चुनाव परिणाम आने के बाद ऊंची जातियों की पार्टी कहीं जाने वाली भाजपा के साथ कांग्रेस भी हक्की–बक्की रह गई. लेकिन, आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लगभग सभी विपक्षी दलों ने सोशल इंजीनियरिंग के सूत्र को ध्यान में रखकर तैयारियां की है, ख़ासतौर पर सपा ने बसपा की काट खोज निकाली है. सपा द्वारा चुनाव से पहले सारे समीकरणों पर ध्यान दिया गया. मुलायम सिंह यादव ने बसपा की प्रत्येक रणनीति पर ध्यान रखा. माना जा रहा है कि मुलायम सिंह के दाहिने हाथ रहे अमर सिंह के जाने से क्षत्रिय वोट बिखर जाएगा, लेकिन यह सच नहीं है. बाह्मण मतदाता बसपा से जुड़ा हुआ है, इसलिए ठाकुर मतदाता अपनी ज़मीन सपा में तलाश कर रहा है. कल्याण सिंह और अमर सिंह के सपा से दूर होने का लाभ पार्टी को भी मिलेगा. भाजपा पिछड़ी हुई है और कांग्रेस कहीं से भी मुक़ाबले में नहीं दिख रही है. विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों का जबाव मायावती ने अवश्य श्वेतपत्र के माध्यम से देने की कोशिश की है, लेकिन वह यह भी जानती हैं कि यह नाकाफी है. इसे देखते हुए उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां बनानी शुरू कर दी है, ताकि वह विपक्ष के आरोपों का जवाब अपने रैलियों में दे सकें.

feedback@chauthiduniya.com

मुख्यमंत्री का रोलबैक

रिपोर्ट में आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की सिफ़ारिश की गई है. सूबे में विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र घटना के तक़रीबन सवा साल बाद सरकार ने इस मामले में रोलबैक कर लिया.

राजकुमार शर्मा

चुनाव से ऐन पहले सरकार ने ज़िला प्रशासन, पुलिस और शासन की अलहदा रिपोर्ट के बावजूद कालाढूंगी (हल्द्धानी) प्रकरण में आरोपियों पर मुक़दमें तो वापस ले लिए, लेकिन सियासी दबाव में उठे इस क़दम से कर्मचारी–अधिकारी वर्ग नाखुश है. सूबे के मुख्यमंत्री जनरल भूवन चंद खंडूरी के इशारे पर थाने में घुस कर हिंसा आगजनी कर पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारने वाले अराजक तत्वों के साथ जिस तरह सरकार खड़ी दिखी इससे जनरल के रोल बैक पर जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं. कालाढूंगी थाना परिसर में 23 अगस्त, 2009 को कोटाबाग ब्लॉक प्रमुख रहे बलवंत सिंह कन्याल की हत्या के बाद गुस्साई भीड़ ने आगजनी और सरकारी संपत्ति की भारी क्षति के साथ थाने पर हमला बोल कर पुलिसकर्मियों की पिटाई की थी. इसमें एक पुलिसकर्मी की मौक़े पर मौत हो गई थी. इस मामले में पुलिस ने 49 आरोपियों के ख़िलाफ़ मुक़दमें दर्ज किए थे. ज़िला प्रशासन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस मामले पर शासन को रिपोर्ट सौंपी थी. रिपोर्ट में आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की सिफ़ारिश की गई है. सूबे में विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र घटना के तक़रीबन सवा साल बाद सरकार ने इस मामले में रोलबैक कर लिया. सभी आरोपियों के ख़िलाफ़ मुक़दमें वापस लिए गए हैं. गृह प्रमुख सचिव उत्पल कुमार सिंह ने आदेश जारी किया. यह आदेश चुनाव के पूर्व राजनीतिक लाभ लेने के लिए जनरल ने हमलावरों को बचाने के लिए राजनीतिक दबाव बनाकर प्रमुख सचिव गृह से आदेश जारी करवाया. सरकार के इस फ़ैसले से पुलिस कर्मचारियों में रोष है. मुख्यमंत्री खंडूरी ने जनता के हित की बात कर राजनीति की रोटी सेंकने के लिए रोलबैक किया. इस बाबत मुख्य सचिव सुभाष कुमार का कहना है कि सरकार ने व्यापक जनहित में यह क़दम उठाया है. इस घटना के बारे में सरकारी अफ़सरों का कहना है कि सरकार की कार्यवाही ने जनरल के सुशासन के नारे की भी पोल खोल दी है. प्रदेश सरकार ने रुद्रपुर हिंसा प्रकरण की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी है. रिपोर्ट में उक्त घटना में मरने वालों और घायलों का ब्योरा दिया गया है.

feedback@chauthiduniya.com

जरायम-सियासत के बाद जेल में पिता-पुत्र

संजय सक्सेना

ज़िला फ़ैज़ाबाद के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर एक बार माननीय का दर्जा हासिल करने की हसरत लिए 78 वर्षिय दबंग समाजवादी पार्टी प्रत्याशी और पूर्व सांसद मित्रसेन यादव जेल पहुंच गए. बीस वर्ष पूर्व एक स्कूल के निमार्ण के लिए आए सरकारी धन हड़पने के कारण ज़िला फ़ैज़ाबाद के प्रथम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार शुक्ला की अदालत ने उन्हें सात साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया. वैसे मित्रसेन की यह पहली जेल यात्रा नहीं थी, इससे पहले भी उम्र कैद की सज़ा काटने के साथ कई बार सलाखों के पीछे जा चुके हैं. मित्रसेन वो नाम है जो सियासत और जरायम दोनों की ही दुनिया में हमेशा फिट रहा. मित्रसेन को उसी जेल में रखा गया है जहां उनके पुत्र और बसपा सरकार के पूर्व मंत्री आनंद सेन यादव एक छात्रा शशि के अपहरण और हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे हैं. बात मित्रसेन की पहचान की कि जाए तो उनका सिक्का आज भी जरायम की दुनिया में चलता है. फ़ैज़ाबाद के इनायतनगर थाना क्षेत्र के भिटारी निवासी मित्रसेन यादव ने लाल झंडा थामकर सियासत का सफ़र शुरू किया था. कई बार वह लोकसभा और विधानसभा के सदस्य रहे. मित्रसेन की ताक़त का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि अपने बाहुबल पर उन्होंने अपने बेटे आनंद सेन को भी बसपा के टिकट से चुनाव जिताकर न केवल विधानसभा तक पहुंचा दिया, बल्कि उन्हें लालबत्ती भी दिला दी थी. इलाकाई राजनीति में जमींदार का रूतबा रखने वाले मथुरा प्रसाद के दो बेटों जटाशंकर व सुरेंद्र तिवारी की हत्या कर दहशत का पर्याय बने मित्रसेन ने एक बार अपराध की दुनिया में क़दम क्या रखा फिर पीछे मुड़ कर नहीं देखा. हनक बनाने के लिए मौक़े–बेमौक़े क़ानून को अपने हाथ में लेने में महारथ हासिल रखने वाले मित्रसेन की फ़ेरहिस्त एक समय तो तीन दर्जन के क़रीब पहुंच गई थी. उन्हें सज़ा भी हुई लेकिन राजनीतिक पकड़ के चलते वह राष्ट्रपति से क्षमा याचना प्राप्तकर बाहर आ गए. दबंग पिता के रसूख में पला पुत्र आनंद सेन यादव भी युवावस्था में ही जरायम की दुनिया में कूद पड़ा था. उसका यह सफ़र तब थमा जब उसे अपहरण और हत्या के मामले में उम्र क़ैद हो गई. मित्रसेन के ख़िलाफ़ अंबेडकरनगर ज़िले के असगवां के किसान हाईस्कूल बनकटा के लिपिक हरिओम यादव ने 28 अक्टूबर 2001 को रिपोर्ट लिखाई थी कि मित्रसेन यादव स्कूल के तथाकथित प्रबंधक हैं. उन्होंने हाईस्कूल की मान्यता की अनिवार्य शर्त प्राभूत कोष की आय जो तहसीलदार ने विद्यालय की भूमि से एक वर्ष के लिए तीन हज़ार एक सौ रुपये निर्धारित की थी. उसका क़रीब 62 हज़ार रुपया अपने निजी खाते में जमा कराकर गबन किया था. उसे लेकर उनके ख़िलाफ़ थाना तारून में धारा 420,409 के तहत मुक़दमा दर्ज किया गया था, जिसमें उन्हें 21 दिसंबर 2011 को सज़ा सुनाई गईं. भारतीय दंड विधान की धारा 409 मे तहत उम्रकैद की सज़ा का प्रावधान है लेकिन एसीजेएम की अदालत को केवल सात साल तक की ही सज़ा सुनाने का अधिकार है और तीन साल की सज़ा के मामले में ही यह अदालत जमानत पर आरोपी को रिहा कर सकती है. इसी लिए मित्रसेन को जेल जाना पड़ गया.

feedback@chauthiduniya.com